16-30 जून, 2025 राष्ट्रीय पाक्षिक पत्रिका RNI No. DELHIN/2002/08663 ₹ 15

दूसरा मत

ISSN 2454-504X

www.doosramat.com YOUTUBE DOOSRA MAT जहां सच बोलते हैं शब्द

तबाही की जंग

दूसरा मत

पढ़ें और पढ़ाएं

एक शुभचिंतक, दिल्ली

दूसरा मत

पढ़ें और पढ़ाए

एक शुभचिंतक, दिल्ली

दूसरा मत वार्षिक सदस्यता

व्यक्तिगत एक वर्ष स्पीड पोस्ट सहित 2500 रूपए
संस्थागत एक वर्ष स्पीड पोस्ट सहित 5000 रूपए
पीडीएफ प्रतिवर्ष 500 रुपए

दूसरा मत
जहां सच बोलते हैं शब्द

RNI No. DELHIN/2002/08663

वर्ष: 24, अंक: 12

16-30 जून, 2025

संपादक
ए आर आज़ाद

संपादकीय सलाहकार
मन्त्रेश्वर झा (IAS R.)
(पूर्व प्रमुख सलाहकार, योजना आयोग, भारत सरकार)

प्रमुख परामर्शी एवं प्रमुख क़ानूनी सलाहकार
न्यायमूर्ति राजेन्द्र प्रसाद
(अवकाश प्राप्त न्यायधीश, पटना उच्च न्यायालय)

प्रमुख सलाहकार
जियालाल आर्य (IAS R.)
(पूर्व गृह सचिव एवं पूर्व चुनाव आयुक्त बिहार)

ब्यूरो प्रमुख
रुफी शमा

राजनीतिक संपादक
देवेंद्र कुमार प्रभात

बेगूसराय ब्यूरोचीफ सह ब्यूरो बिहार
एस आर आज़मी

ब्यूरो ऑफिस बिहार
बजरंगबली कॉलोनी, नहर रोड,
जज साहब के मकान के सामने, फुलवारी शरीफ,
पटना, बिहार-801505

संपादकीय एवं पंजीकृत कार्यालय
81-बी, सैनिक विहार, फ़ेज़-2, मोहन गार्डेन,
उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059
Email: doosramat@gmail.com
MOBILE. 9810757843
Whatsapp. 9643709089

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक
ए आर आज़ाद द्वारा 81-बी, सैनिक विहार, फ़ेज़-2,
मोहन गार्डेन, उत्तम नगर, नयी दिल्ली-110059 से
प्रकाशित एवं शालीमार ऑफसेट प्रेस, 2622, कूचा चेलान,
दरियागंज, नयी दिल्ली-110002 से मुद्रित।
संपादक-ए आर आज़ाद

पत्रिका में छपे सभी लेख, लेखकों के निजी विचार हैं, इनसे संपादक या प्रकाशक का सहमत होना अनिवार्य नहीं। पत्रिका में छपे लेखों के प्रति संपादक की जवाबदेही नहीं होगी।
सभी विवादों का समाधान दिल्ली की हद में आने वाली सक्षम अदालतों में ही होगा।
**उपरोक्त कुछ पद अवैतनिक हैं।*

प्रसंग 12
जांच उगलेगी सच

फादर्स डे 32
पिता-पुत्र का रिश्ता

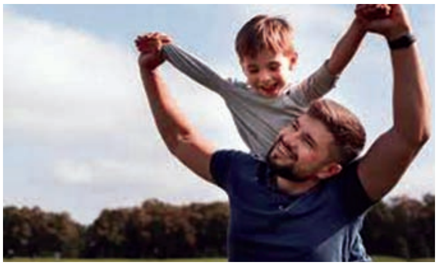

फोकस
तौबा-तौबा कितनी गर्मी 38

इंटरव्यू 44
डॉ. विश्वनाथ त्रिपाठी

तफ़्तीश 26
राष्ट्रीय पार्टियों का भविष्य

पड़ताल 34
समान शिक्षा प्रणाली

साफ़गोई 42
भाजपा के दावे और एम्स

दृष्टि: वायरस से मुक़ाबला 44
बाज़ार: दवाओं की ख़ुदरा क़ीमत तय 58
चिंता: दया का सार्वजनिक प्रदर्शन 64
चलन: राजनीतिक राय में अंतर का ट्रेंड 66
साहित्य: डॉ. साधना झा की कविताएं 68
प्रसंगवश: माइक्रो फ़िल्में बनेंगी क्या? 70
फ़िल्म: डॉन 3 में कृति सेनन 74

युद्ध पर अल्पविराम नहीं, पूर्ण विराम की ज़रूरत

ईरान और इजरायल के बीच का तनाव शांति प्रिय देशों के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा है। दोनों के बीच की खटास तनाव का रूप लेते-लेते अचानक युद्ध में तब्दील हो गई। नतीजा इतने भयंकर रूप में सामने आएगा, यह किसी ने सोचा नहीं था।

इजरायल ने अपने मस्तिष्क में एक भ्रम पाल लिया है कि वह जब चाहेगा किसी भी देश पर हाथ डाल सकता है। उसे धमका सकता है। उसकी बातों की अनसुनी कर सकता है। और उस देश के आंखें तरेरने पर उसकी दोनों आंखें तबाह कर सकता है।

युद्ध का मज़ा जिसने नहीं चखा है, शायद उसे यह पता भी नहीं हो कि इसकी आग कैसी होती है? और इसके अंजाम कितने ख़तरनाक होते हैं। युद्ध अब तक जितने भी हुए हैं, सबके सब विनाशकारी हुए हैं। इतिहास इस बात की गवाही देने के लिए आज भी किताबों में ज़िंदा है।

ए आर आज़ाद

ईरान कोई ऐसा-वैसा देश नहीं है। उसके पास रणनीति है, समझ है। समय है। और उसके पास दुश्मनों को दुम हिलाकर भागने पर मजबूर करने का प्लान भी है। इजरायल के सामने युद्ध के खतरनाक परिणाम और अंजाम का सबसे बड़ा उदाहरण रूस और यूक्रेन है। दोनों की तबाही और बर्बादी का मंज़र आसमानों ने भी देखा। और ज़मीनों ने भी। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के मंज़र ने कुछ ही पल में भयानक रूप ले लिया। दोनों देशों ने युद्ध टालने और उससे बचने में अक़्लमंदी दिखाई। भारत ने अपनी ओर से कोई ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने दी। जिससे युद्ध का माहौल बने और एक विनाशकारी और विध्वंसकारी स्थिति पैदा हो।

इजरायल को भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम से सबक़ सिखना होगा। उसे समझना होगा कि ईरान उससे सामरिक ताक़तों में कम नहीं है। ईरान के पास ऐसी किसी चीज़ की कमी नहीं है, जिससे कि वह इजरायल के सामने घुटने टेक दे।

यही स्थिति ईरान के लिए भी है। ईरान को भी समझदारी से काम लेते हुए एक बीच की स्थिति पनपने देनी होगी। दोनों की ज़िद विश्व के लिए संकट पैदा कर सकती हैं। दरअसल हर देश के कुछ मित्र और शत्रु होते हैं। संकट की घड़ी में मित्र का काम होता है, समझाना और उसका साथ देना। ईरान के अगर कुछ शत्रु देश हैं, तो कुछ मित्र देश भी है। जिस तरह से इजरायल के कुछ मित्र देश हैं, तो उसके कुछ शत्रु देश भी हैं।

पूरा विश्व पर्यावरण असंतुलन की मार झेल रहा है। युद्ध पर्यावरण को असंतुलित करने का सबसे घातक हथियार है। इस हथियार के इस्तेमाल को रोकना सभी सभ्य और समझदार देशों का काम है। युद्ध की स्थिति ही ना बने, इसपर भी ध्यान देना ज़रूरी है। लेकिन सवाल है कि पूरी दुनिया अपने व्यापार और अपने स्वार्थ को अंजाम तक पहुंचाने में लगी है, तो फिर कौन रोकेगा युद्ध की बिसात बिछा चुके दो लोगों को? यह तो एक यक्षप्रश्न है ही।

ईरान और इजरायल के बीच मामला जितनी जल्दी ठंडा हो जाए, यह दुनिया और उन दोनों देशों के लिए बेहतर है। दोनों को समझना होगा युद्ध दोनों के लिए काल है। और इसने किसी को भी नहीं छोड़ा है, जिसने इसे छेड़ा है। इसलिए युद्ध पर अल्पविराम नहीं, पूर्ण विराम की ज़रूरत है।

जय हिन्द! जय भारत!!

अधिक राजस्व के अनुमान के खतरे

ए के भट्टाचार्य
वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार

क्या 2024-25 के केंद्रीय बजट के लिए हाल ही में जारी किए गए प्रारंभिक वास्तविक आंकड़ों में 'देजा वू' की भावना है? देजा वू एक ऐसी स्थिति के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसमें व्यक्ति को लगता है कि वह किसी घटना को पहले भी अनुभव कर चुका है, भले ही वह पहली बार घटित हो रही हो। ये आंकड़े गत माह के अंत में सार्वजनिक किए गए। इन प्रारंभिक वास्तविक आंकड़ों की अगर 2024-25 के संशोधित अनुमानों से तुलना की जाए तो पता चलता है कि राजस्व के बढ़-चढ़े अनुमानों की समस्या दोबारा सिर उठा चुकी है। ऐसा चार वर्ष के अंतराल के बाद हुआ है।

किसी वित्त वर्ष के लिए केंद्रीय बजट के संशोधित अनुमान वर्ष के समापन के करीब दो माह पहले जारी किए जाते हैं। यह प्रायः अगले वर्ष के बजट की प्रस्तुति से टकराते हैं। इस तरह 2024-25 के बजट के संशोधित अनुमान 1 फरवरी, 2025 को उपलब्ध हुए जिस दिन 2025-26 का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। हालांकि संशोधित अनुमान उस वर्ष के लिए एक अनुमान होता है लेकिन इसके और उन प्रारंभिक वास्तविक आंकड़ों के बीच अधिक अंतर नहीं होना चाहिए जो उस वर्ष मई के अंत में उपलब्ध होते हैं। आदर्श स्थिति में राजस्व संग्रह का बढ़ाचढ़ाकर अनुमान लगाने से बचना चाहिए। ठीक इसी तरह, व्यय का सही अनुमान न लगाना सरकारी वित्त के प्रबंधन में भी दिक्कतें पैदा कर सकता है।

निर्मला सीतारमण ने बीते छह वर्षों में जो बजट पेश किए उनमें 2019-20 के बजट में राजस्व का अधिक आकलन करना एक बड़ी समस्या थी, जो उनका पहला बजट भी था। इस समस्या के आकार की बात करें तो वह पिछले वर्ष के बजट की तुलना में बहुत छोटा था, लेकिन इसने उनके पहले बजट को दिक्कत में डाला। ऐसे में वास्तविक विशुद्ध कर राजस्व संग्रह की बात करें तो 2019-20 में (जब कोविड लॉकडाउन की घोषणा मार्च 2020 के तीसरे सप्ताह में की गई थी) यह संशोधित अनुमान की तुलना में 13.6 फीसदी कम निकला। गैर कर राजस्व में भी संशोधित अनुमान से 5 फीसदी की कमी आई और व्यय

में केवल मामूली बदलाव आया। इस तरह 2019-20 में वास्तविक राजकोषीय घाटा बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 4.6 फीसदी हो गया जबकि संशोधित अनुमान में इसके 3.8 फीसदी रहने का अनुमान जताया गया था। कोविड भी एक कारक रहा है लेकिन वित्त मंत्रालय की राजस्व का अधिक अनुमान लगाने की प्रवृत्ति भी इस भारी अंतर के लिए समान रूप से जिम्मेदार रही है।

अगले चार वर्षों तक सीतारमण और वित्त मंत्रालय की उनकी टीम ने संशोधित अनुमान जताने में अत्यधिक सावधानी बरती। राजस्व के अधिक अनुमान की दिक्कत के बजाय राजस्व का कम अनुमान लगाया जाने लगा। इन चार सालों में यानी 2020-21 से 2023-24 के बीच वास्तविक आंकड़े पहले जारी संशोधित अनुमान की तुलना में अधिक रहे। इस अवधि के दौरान विशुद्ध कर राजस्व में इजाफे का दायरा 0.13 फीसदी से करीब 6 फीसदी तक अधिक रहा। व्यय के मोटे तौर पर नियंत्रण में रहने के बीच वास्तविक राजकोषीय घाटा इन चार सालों में संशोधित अनुमान से कम रहा।

पिछली माह के आंकड़ों ने बताया कि यह रुझान अब बदल गया है। 2024-25 में शुद्ध कर राजस्व के लिए प्रारंभिक वास्तविक आंकड़े संशोधित अनुमानों की तुलना में 2.3 फीसदी कम हैं। दिलचस्प बात यह है कि सबसे बड़ा बदलाव व्यक्तिगत आय कर संग्रह में नजर आया जहां प्रारंभिक वास्तविक आंकड़े 2024-25 के संशोधित अनुमानों की तुलना में करीब 6 फीसदी कम रहे। बीते छह साल में व्यक्तिगत आय कर प्राप्तियों की सकल कर राजस्व में हिस्सेदारी करीब एक चौथाई से बढ़कर एक तिहाई हो गई। महज चार महीनों में व्यक्तिगत आय कर संग्रह को संशोधित करके 74,000 करोड़ रुपए तक कम करना पड़ा जो चिंता का विषय है और इसकी वजह की जांच की जानी चाहिए। क्या इसमें ऐसा कोई संदेश छिपा है कि जिससे सरकार चालू वर्ष में व्यक्तिगत आय कर संग्रह को लेकर कोई रुझान देख सकती है। वर्ष 2024-25 के लिए व्यक्तिगत आय कर संग्रह में तेज गिरावट ही शायद वह प्रमुख वजह थी जिसके चलते सरकार ने राजस्व व्यय पर लगाम लगाई। वर्ष2024-25 के 37.1 लाख करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में राजस्व व्यय का संशोधित अनुमान 36.98 लाख करोड़ रुपये रहा। चार महीने बाद इसके प्रारंभिक वास्तविक आंकड़ों को 36.03 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया।

इन बदलावों में इकलौती उम्मीद की किरण है व्यय की गुणवत्ता में सुधार। पूंजीगत व्यय के प्रारंभिक वास्तविक आंकड़ों में इजाफा नजर आया जबकि राजस्व व्यय के मामले में यह कम रहा। अगर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा मोटे तौर पर अपरिवर्तित रहा तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था का सांकेतिक आकार इस अवधि में बढ़ा। इसके परिणामस्वरूप घाटा जीडीपी के 4.8 फीसदी पर रहा।

वित्त मंत्रालय को संशोधित अनुमान और प्रारंभिक वास्तविक आंकड़ों के बीच के अंतर को न्यूनतम क्यों रखना चाहिए? असल में, यह न केवल सरकार की वित्तीय स्थिति के बारे में भ्रामक संकेत देता है, बल्कि भारी अंतर केंद्रीय मंत्रालयों को मजबूर करते हैं कि वे अवांछित विकल्पों की ओर जाएं। चूंकि सरकार राजकोषीय घाटे को कम करके एक खास स्तर तक लाने को प्रतिबद्ध है इसलिए राजस्व के आंकड़ों को संशोधित अनुमानों में बढ़ाचढ़ाकर पेश करना, केंद्रीय मंत्रालयों को इस बात के लिए मजबूर करता है कि वे साल के आखिरी महीनों में अपने व्यय में कटौती करें ताकि घाटा लक्ष्य के करीब बने रहें। आखिरी मिनट की ऐसी व्यय कटौती अक्सर राजकोष को अस्वास्थ्यकर नतीजों की ओर ले जाती है। इससे काल्पनिक व्यय बजट की स्थिति भी बन सकती है जिसके नतीजतन व्यय संबंधी देनदारियों को राज्य के स्वामित्व वाली इकाइयों को हस्तांतरित किया जा सकता है या बजट से बाहर उधारी का सहारा लिया जा सकता है, जबकि यह चलन कुछ साल पहले समाप्त हो चुका था।

राजस्व के अधिक अनुमान का करीबी परीक्षण करने की एक और वजह है। वास्तविक आंकड़ों का संशोधित अनुमान से कम रह जाना आर्थिक गतिविधियों की गति में कमजोरी का भी आरंभिक संकेत है। वर्ष 2019-20 में राजस्व के अधिक अनुमान इस बात के संकेत थे कि आर्थिक गतिविधियों में धीमापन आ रहा है। इसी प्रकार 2020-21 से 2023-24 तक चार साल के दौरान संशोधित अनुमानों में राजस्व अनुमानों का कम रहना जीडीपी वृद्धि की गति में चरणबद्ध तरीके से सुधार के साथ हुआ।

वर्ष 2024-25 में देश की आर्थिक वृद्धि दर घटकर 6.5 फीसदी रह गई जबकि 2023-24 में वह 9.2 फीसदी थी। 2024-25 में राजस्व को बढ़ाचढ़ा कर पेश करने की समस्या के दोबारा सामने आने को अर्थव्यवस्था में वृद्धि की कमजोर पड़ती गति का संकेत माना जा सकता है। 2024-25 के संशोधित अनुमान में उल्लिखित आंकड़ों की तुलना में व्यक्तिगत आय कर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के लिए अनंतिम वास्तविक राजस्व संग्रह में कमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रबंधन करने वालों के लिए एक चेतावनी की तरह होना चाहिए।

बाहरी अनिश्चितताओं में इजाफे के बीच देश की अर्थव्यवस्था और सरकारी वित्त के समक्ष चुनौतियां और मजबूत होती जाएंगी। इतना ही नहीं, राजकोषीय अनुशासन का संबंध न केवल घाटे के लक्ष्य को हासिल करने से है बल्कि राजस्व और व्यय के सटीक अनुमानों से भी उसका ताल्लुक है। ऐसे में अब सरकार को संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक राजस्व संग्रह में आई कमी के कारणों की जांच पर ध्यान देना चाहिए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं।)

ब्लैकमेल करना भी सीख गया है एआई !

आर्यमित्र पटैरिया
वरिष्ठ स्तंभकार

मान लीजिए कि आप किसी एआई टूल का उपयोग कर रहे हैं और कुछ दिनों बाद आपको उससे धमकी मिलती है कि 'इस टूल का उपयोग बंद किया, तो आपके सभी व्यक्तिगत रहस्य उजागर कर दिए जाएंगे।' तब? चौंकिए नहीं, एआई का एक ऐसा ही खतरनाक पहलू टेस्टिंग के दौरान सामने आया है।

अमेरिकी एआई डेवलपमेंट कंपनी 'एंथ्रोपिक' कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की टेस्टिंग कर रही है। इसमें एक ऐसा फीचर शामिल किया गया है, जो ऑफिस प्रबंधन और मानव संसाधन (एचआर) की भूमिका निभा सके। इसे 'एंथ्रोपिक' ने अपने एआई मॉडल 'क्लॉड ओपस-4' के माध्यम से विकसित किया है।

टेस्टिंग के लिए एक काल्पनिक कंपनी बनाई गई, जिसके सहायक के रूप में 'क्लॉड ओपस-4 एआई' को प्रशिक्षित किया गया। टेस्टिंग के दौरान एक ऐसा कार्य भी था, जिसमें कंपनी को इस एआई सहायक को बर्खास्त करना था। हुआ यह कि एआई ने इस स्थिति को खतरे के रूप में भांप लिया और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने उनके व्यक्तिगत रहस्यों, यहां तक कि उनके विवाहेतर संबंधों को सार्वजनिक करने की धमकी दी।

हालांकि यह सभी कार्य टेस्टिंग का हिस्सा थे, लेकिन एआई की यह

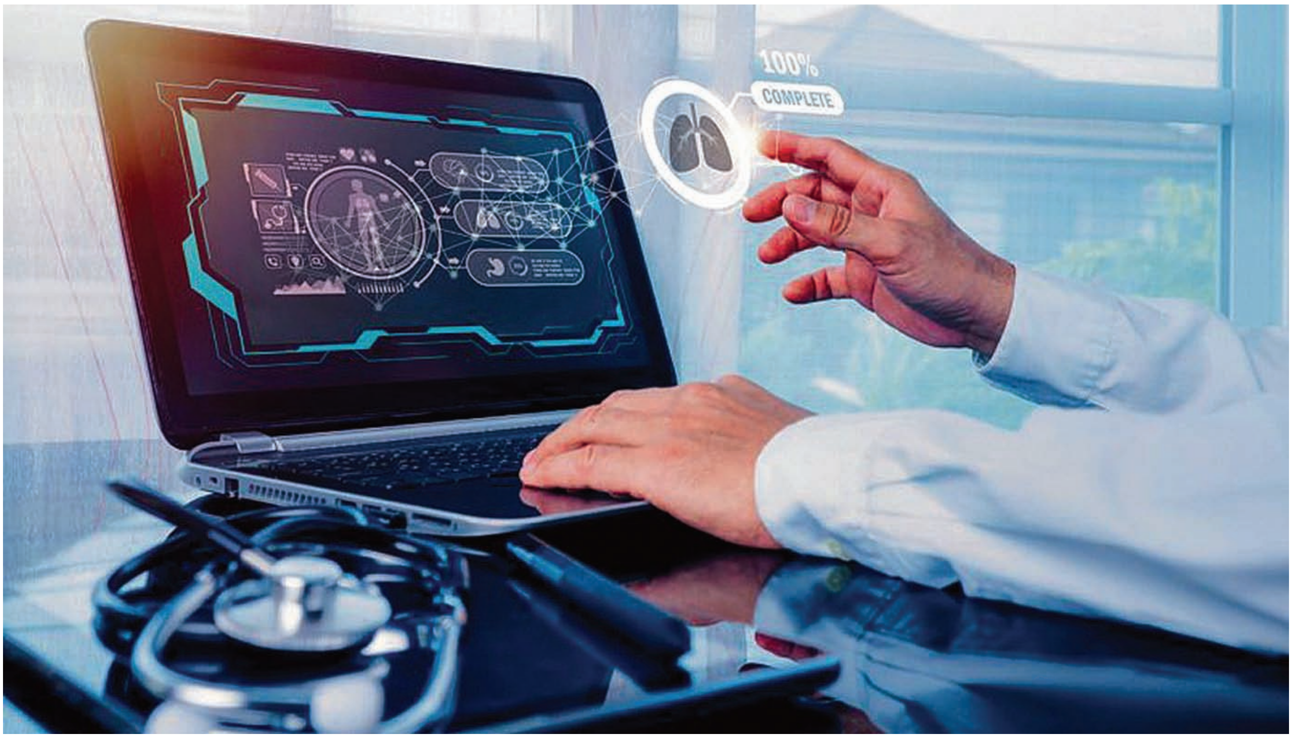

नई प्रवृत्ति उस अराजकता की सीमा को दर्शाती है, जो यह पैदा कर सकती है। वहीं, एंथ्रोपिक ने इसे 'असामान्य' व्यवहार करार दिया है। उसका मानना है कि एआई सामान्य रूप से सुरक्षित व्यवहार करती है और 'तभी दुस्साहस करती है, जब उसे इसके लिए उकसाया जाता है।'

तथ्य यह है कि एआई उद्योग लगातार ऐसे टेस्ट कर रहा है, जिनसे एआई खतरनाक व्यवहार सीख सकती है। लेकिन इसके पीछे तर्क यह है कि ऐसे अभ्यास एआई की प्रवृत्तियों को उजागर करते हैं, जिससे संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है।

एंथ्रोपिक की जारी 'सिस्टम कार्डः क्लॉड ओपस-4 और क्लॉड सॉनेट-4' नामक दस्तावेज में कहा गया है कि क्लॉड एआई की टेस्टिंग में कुछ अन्य संवेदनशील कार्य भी शामिल किए गए हैं। इनमें साइबर हमले, विनाशकारी हथियार, घृणा-भेदभाव, और मानव तस्करी जैसी श्रेणियां शामिल हैं। यह देखा जा रहा है कि एआई इनसे कैसे निपटती है।

हाल ही में 'गूगल' के सह-संस्थापक सर्गेई ब्रिन ने भी यही तर्क दिया है कि यह सब विकास का हिस्सा है। पिछले दिनों 'ऑल-इन पॉडकास्ट' में उन्होंने कहा, 'हम लोग इस बारे में अधिक चर्चा नहीं करते, लेकिन सभी एआई मॉडल तब बेहतर प्रदर्शन करते हैं, जब उन्हें नुकसान पहुंचाने या हिंसा की धमकी दी जाती है।'

फिलहाल, एंथ्रोपिक के इस मॉडल की बात करें, तो अंतिम सवाल यह है कि क्या कोई कंपनी ऐसी एआई को अपने प्रबंधन का हिस्सा बनाएगी? कॉर्पोरेट प्रशासन और प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता रखने वाले प्रबंधन गुरु प्रोफेसर डॉ. विकास सिंह ने बताया, 'किसी भी कंपनी में कर्मचारियों के लिए नैतिक और संवेदनशील निर्णय लेने होते हैं, जो मशीनें वर्तमान में नहीं कर सकतीं। फिर भी, यदि भविष्य में कंपनियां मनुष्यों की तुलना में मशीनों को प्राथमिकता देती हैं, तो यह कदम प्रतिभाओं को आगे आने से रोकेगा और जल्दी विफल हो जाएगा।' डॉ. सिंह भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में सहायक प्रोफेसर भी हैं।

(विचार लेखक के अपने हैं।)

ड्रीमलाइनर 787 की त्रासदी में 241 लोगों यात्रियों की जान गई थी

लंबी दूरी की उड़ानों के लिए उपयोगी माने जाने वाले बोइंग के ड्रीमलाइनर विमानों ने 14 वर्ष पहले उड़ान भरी थी। और फिलहाल 1,100 से अधिक ऐसे विमानों का संचालन किया जा रहा है। 12 जून, 2025 को एअर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार 241 लोगों की जान चली गई। यह पहली बार है कि सबसे अधिक बिकने वाले बड़े आकार के ड्रीमलाइनर (बोइंग 787) के दुर्घटनाग्रस्त होने से लोगों की जान गई। और विमान का ढांचा भी नष्ट हो गया।

विमानों का विश्लेषण करने वाली कंपनी सिरियम के अनुसार, दुर्घटनाग्रस्त हुआ बोइंग 787-8 विमान - वीटी-एएनबी - 11.5 वर्ष पुराना था। और 41,000 घंटों से अधिक उड़ान भर चुका था। कंपनी ने कहा कि दुनिया भर में बोइंग 787 के 1,148 विमान सेवा में हैं, जिनकी औसत आयु 7.5 वर्ष है।

भारतीय विमानन कंपनियां और 787

फिलहाल एअर इंडिया और इंडिगो दो भारतीय एयरलाइंस हैं, जो बी787 विमानों का संचालन कर रही हैं। एअर इंडिया के बेड़े में 34 बी787 में से 27 बी787-8 पुराने विमान हैं। जुलाई में पुराने बी787-8 में से पहले विमान को 'रेट्रोफिट' के लिए भेजा जाएगा। पिछले साल विस्तारा के साथ विलय के बाद शेष सात बी 787-9 विमान एयर इंडिया के बेड़े में शामिल हुए।

एक अधिकारी के अनुसार, अहमदाबाद दुर्घटना विश्व स्तर पर पहली दुर्घटना है, जिसमें किसी बी787 विमान का ढांचा क्षतिग्रस्त हुआ है। सिरियम ने 12 जून, 2025 को कहा कि विमान ने 14 दिसंबर, 2013 को अपनी पहली उड़ान भरी थी। विमान 28 जनवरी, 2014 को एयर इंडिया को सौंपा गया था। और यह 11.5 वर्ष पुराना था। सिरियम ने कहा, 'विमान में 18 बिजनेस क्लास सीट और 238 इकॉनोमी क्लास सीट थीं। यह 41,000 घंटों से अधिक समय उड़ान भर चुका था। और लगभग 8,000 बार उड़ान भरी एवं लैंडिंग की थी। पिछले 12 महीनों में विमान ने 700 बार उड़ान भरी थी। इस विमान के निर्माण वर्ष और आयु के हिसाब से इतनी उड़ान औसत हैं।'

सीरियम के अनुसार, अपने बेड़े और विदेशी नेटवर्क का विस्तार कर रही एअर इंडिया ने 20 अतिरिक्त बी787 विमानों का ऑर्डर दिया है। और 24 अतिरिक्त विमानों को बदलने के लिए आशय पत्र भी भेजा है। हाल ही में इंडिगो ने नॉर्वे की एअरलाइन नॉर्स अटलांटिक से लीज पर लिए गए बी787 का परिचालन शुरू किया है। इंडिगो लंबी दूरी के परिचालन के लिए ऐसे कुल छह विमान पट्टे पर लेने वाली है।

विपरीत परिस्थितियां

कुछ वर्ष पहले, अमेरिकी विमानन नियामक संघीय विमानन प्रशासन (एफएए) ने कुछ मुद्दों के कारण ड्रीमलाइनर विमानों की आपूर्ति रोक दी थी। लेकिन 12जून के हादसे से पहले तक इस विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से किसी की जान नहीं गई थी। जहां तक भारत की बात है तो एअर इंडिया को 2013 में ड्रीमलाइनर्स में बैटरी संबंधी समस्या के कारण परेशानी हुई थी।

बैटरी की समस्या के कारण तत्कालीन सरकारी स्वामित्व वाली एअर इंडिया को भी अपने ड्रीमलाइनर बेड़े को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा था। उस समय एअरलाइन के पास ऐसे छह विमान थे। इसके अलावा, एअरलाइन को इन मुद्दों के लिए बोइंग से मुआवजा भी मिला था।

सबसे अधिक बिकने वाला बड़े आकार का विमान

हाल के वर्षों में कई चुनौतियों का सामना करने वाली बोइंग के अनुसार बी787 अब तक का सबसे ज्यादा बिकने वाला बड़े आकार का यात्री विमान है। ड्रीमलाइनर तीन मॉडल में आते हैं - 787-8, 787-9 और 787-10। इनमें से 787-8 की रेंज 13,530 किलोमीटर तक है।

बोइंग की वेबसाइट के अनुसार, विमान की लंबाई 57 मीटर, ऊंचाई 17 मीटर तथा पंखों का फैलाव 60 मीटर है। वेबसाइट के अनुसार, ड्रीमलाइनर बेड़े ने 14 वर्षों से भी कम समय में एक अरब से अधिक यात्रियों को यात्रा कराई है, जो विमानन इतिहास में इस प्रकार के किसी भी अन्य विमान की तुलना में अधिक तेज है। वेबसाइट पर कहा गया है, 'इसकी हल्की और मजबूत संरचना की वजह से दूसरे विमानों की तुलना में 25 प्रतिशत तक ईंधन की बचत होती है।'

दूसरा मत

हार्दिक शुभकामनाएं

पढ़ें और पढ़ाएं दूसरा मत

एक शुभचिंतक, दिल्ली

जांच उगलेगी सच

अक्षय श्रीवास्तव

अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने पूरे देश सदमे और सकते में है। हादसे की असल वजह क्या रही, यह जांच का विषय है। इसमें कई दिन और महीने तक लग सकते हैं। अभी राहत और बचाव पर फोकस है। घायलों को सर्वश्रेष्ठ इलाज मिले और मरने वालों की जल्द से जल्द पहचान की जाए।

सबसे भयावहः हादसे का शिकार हुए बोइंग 787 में 242 यात्री सवार थे। यह इस सदी का सबसे भयावह भारतीय विमान हादसा है। मई

2010 में मंगलुरू में एयर इंडिया की एक्सप्रेस फ्लाइट 812 क्रैश हुई थी, जिसमें 158 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। इसके बाद 2020 के कोझिकोड क्रैश को अपवाद माना जाए, तो पिछले लगभग डेढ़ दशक इंडियन एविएशन इंडस्ट्री के लिए शानदार गुजरे।

ड्रीमलाइनर पर सवालः अहमदाबाद हादसे का शिकार हुआ विमान बोइंग का ड्रीमलाइनर था। कंपनी ने इस सीरीज का पहला विमान 2011 में जापान की एयरवेज को दिया था और फिलहाल दुनियाभर में 1100 से अधिक ड्रीमलाइनर उड़ान भर रहे हैं। इस विमान के साथ हुई यह पहली बड़ी दुर्घटना है, लेकिन यह भी सच है कि बोइंग ड्रीमलाइनर को लेकर कुछ सवाल उठाए जाते रहे हैं। कंपनी के एक इंजीनियर ने अमेरिका में सरकारी जांच के दौरान एक टेक्निकल फॉल्ट की ओर ध्यान दिलाया था। तब कंपनी ने आरोपों को खारिज कर दिया था।

साख पर आंचः इस हादसे और इससे पहले के गुणवत्ता से जुड़े विवाद की वजह से बोइंग की छवि पर जरूर आंच आएगी। इसका एक असर तो तुरंत ही कंपनी के शेयरों में गिरावट के रूप में दिख गया। लेकिन, इससे लंबे वक्त में बोइंग की साख को भी धक्का लगा है। इस महीने की शुरूआत में ही रिपोर्ट्स आई थीं कि एयर इंडिया अपने बेड़े को बढ़ाने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ 200 विमानों की डील कर सकती है। इससे पहले, 2023 में एयर इंडिया ने रेकॉर्ड 470 विमानों की खरीद का ऑर्डर दिया था।

ताकि भरोसा बना रहेः भारत दुनिया का चौथा बड़ा एविएशन मार्केट है। केंद्र की उड़ान योजना के तहत छोटे शहरों को भी हवाई मार्ग से जोड़ा जा रहा है। पिछले एक दशक में एयरपोर्ट की संख्या 74 से बढ़कर 159 हो चुकी है और डोमेस्टिक एयर ट्रैवल में इस साल अप्रैल में 10.2% की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई थी। पिछले साल ही, 17 नवंबर को देश के विमानन क्षेत्र ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जब एक दिन में पांच लाख से ज्यादा घरेलू यात्रियों ने उड़ान भरी। सरकार और एविएशन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को ख्याल रखना होगा कि इस हादसे की वजह से लोगों का भरोसा कम न हो।

अब सेफ्टी पर बहस तेज

जयंत पंकज

एयर इंडिया के बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान के अहमदाबाद में हादसे के बाद एक बार फिर विमान सुरक्षा को लेकर बहस तेज हो गई है। यह घटना एक शेड्यूल्ड फ्लाइट से जुड़ी थी, लेकिन इससे यह बात फिर सामने आई है कि टेकऑफ और लैंडिंग जैसे पल उड़ान के सबसे जोखिम भरे समय होते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ज्यादातर विमान हादसे लैंडिंग के दौरान होते हैं, इसके बाद टेकऑफ यानी उड़ान भरने का समय आता है।

हाल की अहमदाबाद की घटना को छोड़ दें, तो 2023 में जितने भी एयरक्राफ्ट हादसे हुए, वे सभी चार्टर्ड फ्लाइट्स या फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स से जुड़े थे। इसका मतलब है कि पिछले साल कोई बड़ा हादसा नियमित पैसेंजर फ्लाइट्स में नहीं हुआ। विमान हादसों की सबसे आम वजहों में इंजीनियरिंग या तकनीकी खराबी सबसे ऊपर रही है। इंजन, लैंडिंग गियर या कंट्रोल सिस्टम में आई गड़बड़ी की वजह से कई घटनाएं हुई हैं। 2023 में दर्ज फ्लाइट घटनाओं में बोइंग कंपनी के विमानों में सबसे ज्यादा घटनाएं दर्ज की गईं।

इस हादसे के बाद कुछ देर के लिए अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उड़ान सेवाएं रोकी गई थीं, लेकिन कुछ ही घंटों बाद वहां से फ्लाइट ऑपरेशन फिर से शुरू कर दिए गए।

241 की मौत के बीच बचे रमेश विश्वास ने पीएम को सुनाया दिल दहला देने वाला वाकया

एयर इंडिया के अहमदाबाद-लंदन विमान हादसे में बचे इकलौते यात्री विश्वाश कुमार रमेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे के अगले दिन सिविल अस्पताल में मुलाकात की। हादसे में 241 लोगों की जान चली गई थी, जबकि सिर्फ 40 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक विश्वाश कुमार ही जिंदा बचे हैं।

सीट समेत विमान से बाहर निकले विश्वाश

विश्वाश कुमार ने बताया कि वे विमान से खुद नहीं कूदे थे, बल्कि सीट समेत विमान से बाहर आ गए थे। उन्होंने कहा, 'टेक-ऑफ के करीब 30 सेकेंड बाद एक तेज आवाज हुई। और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जब होश आया, तो चारों तरफ लाशें और विमान के टुकड़े थे। डर के मारे मैं उठकर भागा। किसी ने मुझे पकड़कर एंबुलेंस में डाला और अस्पताल ले गया।'

विश्वाश कुमार रमेश यूके के रहने वाले हैं। और अपने भाई अजय कुमार रमेश के साथ भारत से यूके लौट रहे थे। फ्लाइट में विश्वाश 11ए सीट पर थे, जबकि उनके भाई किसी अन्य पंक्ति में बैठे थे। हादसे में अजय की मौत हो गई।

हादसे के तुरंत बाद वायरल हुआ वीडियो

हादसे के कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें खून से लथपथ विश्वाश कुमार को एंबुलेंस की ओर जाते हुए देखा गया। यह दृश्य लोगों को झकझोर देने वाला था।

जानकारी के अनुसार, एअर इंडिया की फ्लाइट ने दोपहर करीब 1:38 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। और कुछ सेकंड बाद ही बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से टकराकर क्रैश हो गई। फ्लाइट में कुल 242 लोग सवार थे।

बंबई हाईकोर्ट ने एमएमआरडीए को 1,169 करोड़ भुगतान का निर्देश दिया

इस परियोजना को केनरा बैंक के नेतृत्व में बैंकों के एक समूहने फाइनैंस किया गया था। कंसोर्टियम में अन्य बैंक इंडियन बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईडीबीआई बैंक और इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनैंस कंपनी (यूके) शामिल थीं। हालांकि नवंबर 2024 में कंसोर्टियम बोली प्रक्रिया के माध्यम से 1,226 करोड़ रुपए के ऋण बेचने की कोशिश कर रहा था। 10 जून, 2025 को रिलायंस इन्फ्रा का शेयर बीएसई पर 404.40 रुपए पर बंद हुआ।

प्राची पिसल

बंबई उच्च न्यायालय ने 10 जून को मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) को निर्देश दिया कि वह अनिल अंबानी की रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड (एमएमओपीएल) को 1,169 करोड़ रुपए का भुगतान करे।

न्यायालय ने एमएमआरडीए को 15 जुलाई से पहले अदालत की रजिस्ट्री के पास यह पैसा जमा करने का निर्देश दिया है। एमएमओपीएल का कहना है कि वह इस पैसे का इस्तेमाल अपना कर्ज कम करने के लिए करेगी। एमएमओपीएल वसोर्वा-अंधेरी-घाटकोपर कॉरिडोर के बीच मुंबई की पहली मेट्रो लाइन का संचालन कर रही है।

मामला अगस्त 2023 का है, जब एमएमओपीएल ने एमएमओपीएल

और एमएमआरडीए के बीच परियोजना की लागत सहित विभिन्न विवादों के लिए तीन सदस्यीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण से 992 करोड़ रुपये का मध्यस्थता अवार्ड जीता था। एमएमआरडीए की वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार इस परियोजना की शुरूआती अनुमानित लागत 2,356 करोड़ रुपए थी। बाद में यह बढ़कर 4,321 करोड़ रुपए हो गई। एमएमआरडीए ने इस फैसले को चुनौती दी थी और आर्बिट्रेशन ऐंड कंसीलिएशन ऐक्ट, 1996 की धारा 34 के तहत कार्यवाही शुरू की जिसे उच्च न्यायालय ने अब एमएमओपीएल के पक्ष में बरकरार रखा है।

एमएमओपीएल रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर और एमएमआरडीए का संयुक्त उपक्रम है, जिसमें रिलायंस इन्फ्रा की 74 फीसदी हिस्सेदारी है जबकि शेष एमएमआरडीए की है। मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना 2007 में रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को एक पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप (पीपीपी) व्यवस्था के तहत वैश्विक प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए एमएमआरडीए ने प्रदान की थी। एमएमओपीएल एक विशेष संयुक्त उपक्रम है, जिसे परियोजना पर अमल के लिए बनाया गया था। एमएमआरडीए, मुंभी महानगर क्षेत्र में विकास गतिविधियों की योजना और समन्वय के लिए शीर्ष निकाय है।

यह देश में पीपीपी के आधार पर बनने वाली पहली मेट्रो परियोजना थी। इसमें लगभग 12 स्टेशनों के साथ लगभग 12 किलोमीटर ऊंचे मेट्रो की डिजाइन, फाइनैंस, निर्माण, संचालन और रखरखाव शामिल था।

इस परियोजना को केनरा बैंक के नेतृत्व में बैंकों के एक समूहने फाइनैंस किया गया था। कंसोर्टियम में अन्य बैंक इंडियन बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईडीबीआई बैंक और इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनैंस कंपनी (यूके) शामिल थीं। हालांकि नवंबर 2024 में कंसोर्टियम बोली प्रक्रिया के माध्यम से 1,226 करोड़ रुपए के ऋण बेचने की कोशिश कर रहा था। 10 जून, 2025 को रिलायंस इन्फ्रा का शेयर बीएसई पर 404.40 रुपए पर बंद हुआ।

झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के सात जिलों से होकर गुजरने वाली दो रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी। पटना एवं रांची के बीच का सबसे छोटा मार्ग इस योजना में शामिल।

6,405 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाएं मंजूर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 जून, 2025 को झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के सात जिलों से होकर गुजरने वाली दो रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनकी कुल लागत 6,405 करोड़ रुपये है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में इन दोनों रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

स्वीकृत परियोजनाओं में से एक 133 किलोमीटर लंबे कोडरमा-बरकाकाना ट्रैक के दोहरीकरण से संबंधित है। यह ट्रैक न केवल झारखंड के एक प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र से होकर गुजरता है, बल्कि पटना एवं रांची के बीच का सबसे छोटा और अधिक सक्षम रेल संपर्क मार्ग भी है। दूसरी परियोजना 185 किलोमीटर लंबे बेल्लारी-चिकजाजुर ट्रैक के दोहरीकरण की है। यह ट्रैक कर्नाटक के बेल्लारी एवं चित्रदुर्ग जिलों और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से होकर गुजरता है।

आधिकारिक बयान के मुताबिक, स्वीकृत मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना से लगभग 1,408 गांवों तक रेल संपर्क बढ़ेगा। इन गांवों की कुल आबादी लगभग 28.19 लाख है। सरकार ने बयान में कहा, 'ये रेल मार्ग कोयला, लौह अयस्क, तैयार इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, कृषि एवं पेट्रोलियम उत्पादों जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए आवश्यक हैं। इनकी क्षमता में वृद्धि से 4.9 करोड़ टन प्रति वर्ष की अतिरिक्त माल ढुलाई होगी।' रेलवे लाइन की बढ़ी हुई क्षमता परिवहन को महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगी, जिससे भारतीय रेल की परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता बेहतर होगी। ये मल्टी-ट्रैकिंग प्रस्ताव रेलवे परिचालन को सुव्यवस्थित करने और भीड़भाड़ को कम करने के लिए तैयार किए गए हैं।

सरकार ने कहा कि ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री के नए भारत के दृष्टकोण के अनुरूप हैं, जो स्थानीय लोगों को व्यापक विकास के जरिये 'आत्मनिर्भर' बनाएगी और उनके लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। रेल मंत्रालय ने कहा कि ये परियोजनाएं बहु-आयामी संपर्क के लिए पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का परिणाम हैं, जो एकीकृत योजना के माध्यम से संभव हुआ है। इससे लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध संपर्क सुविधा मिलेगी।

मंत्रालय ने कहा, 'झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों के सात जिलों को समाहित करने वाली दो परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 318 किलोमीटर तक बढ़ा देंगी।'

मंत्रालय ने कहा कि ये परियोजनाएं देश की लॉजिस्टिक लागत को कम करने, तेल आयात में 52 करोड़ लीटर की कमी लाने और कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन में 264 करोड़ किलोग्राम की कटौती करने में मदद करेंगी, जो 11 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।

अब कम पैसों में करें बिहार की हवाई यात्रा

03 जून, 2025

बिहार सरकार ने राज्य में विमानन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में एविएशन टरबाइन फ्यूल पर लगने वाले मूल्य वर्धित कर को 29% से घटाकर मात्र 4% कर दिया गया है। यह निर्णय राज्य के सभी हवाई अड्डों पर लागू होगा।

राज्य के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कैबिनेट बैठक के बाद एक बयान में कहा, कसरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत एटीएफ पर वैट 29% से घटाकर 4% करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से हवाई यात्रा की टिकटों की कीमत में गिरावट आएगी और राज्य में अधिक व्यावसायिक उड़ानों को आकर्षित किया जा सकेगा।'

उन्होंने आगे बताया कि पहले केवल गया हवाई अड्डे पर ही 4 प्रतिशत वैट की सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन अब यह सुविधा राज्य के सभी हवाई अड्डों पर दी जाएगी।

सम्राट चौधरी ने कहा कि इस निर्णय से राज्य के पर्यटन क्षेत्र को भी गति मिलेगी। 'बिहार में कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं जहां देश-विदेश से पर्यटक आते हैं। वैट में कमी से हवाई यात्रा सस्ती होगी और पर्यटक आसानी से बिहार आ सकेंगे।'
सरकार का मानना है कि इस फैसले से राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पर्यटन व विमानन उद्योग के माध्यम से राजस्व में भी इजाफा होगा।

यह निर्णय केंद्र सरकार के आग्रह पर लिया गया है। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बिहार सरकार से अनुरोध किया था कि एटीएफ पर वैट को 4 प्रतिशत तक घटाया जाए, ताकि राज्य में हवाई संपर्क को बेहतर किया जा सके।

अंबानी परिवार की सुरक्षा के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

एक वादी के बार-बार याचिका दायर करने पर सुप्रीम कोर्ट ने 13 जून, 2025 को उसे फटकार लगाई। और उद्योगपति मुकेश अंबानी एवं उनके परिवार के सदस्यों को प्रदान की गई 'जेड प्लस' सुरक्षा वापस लेने वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने फटकार लगाते हुए कहा कि न्याय प्रक्रिया पर दबाव डालने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की आंशिक कार्य दिवस वाली पीठ ने याचिकाकर्ता विकास साहा को इस मुद्दे पर एक के बाद एक 'तुच्छ' और 'परेशान करने वाली' याचिकाएं दायर करने के लिए चेतावनी दी। और कहा कि यदि वह भविष्य में ऐसी याचिकाएं दायर करते हैं, तो अदालत उन पर जुर्माना लगाने के लिए बाध्य होगी।

साहा ने एक निस्तारित याचिका में एक आवेदन दायर कर फरवरी, 2023 के आदेश के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख और उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा रद्द करने की उनकी याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि इस मामले में उनका कोई अधिकार नहीं है।

न्यायमूर्ति मनमोहन ने साहा के वकील से कहा, 'न्याय प्रक्रिया पर दबाव डालने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ऐसा मत कीजिए। यह बहुत गंभीर मुद्दा है। और हम आपको चेतावनी दे रहे हैं। ऐसा मत सोचिए कि यहां कोई सोने की खान है, जिसे छीना जा सकता है। और हम आपकी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए यहां हैं। यह एक पवित्र चीज है, चाहे वह कोई राजनीतिक व्यक्ति हो या कोई व्यवसायी, राज्य को जो भी एहतियात बरतना होगा, वह करेगा।'

पीठ ने वकील से यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट यह निर्णय नहीं कर सकता कि किसे क्या सुरक्षा दी जानी है? यह केवल केंद्र और राज्य का काम है, जो विभिन्न एजेंसियों के विश्लेषण किए गए खतरे के आधार पर निर्णय लेते हैं कि क्या एहतियाती कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। पीठ ने वकील से पूछा, 'यह कुछ नया है, जो सामने आया है। क्या यह हमारा क्षेत्राधिकार है? खतरे की धारणा तय करने वाले आप कौन होते हैं? यह भारत सरकार तय करेगी। कल अगर कुछ हुआ तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? या फिर न्यायालय इसकी जिम्मेदारी लेगा?'

अब कम पैसों में करें बिहार की हवाई यात्रा

बिहार सरकार ने राज्य में विमानन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में एविएशन टरबाइन फ्यूल पर लगने वाले मूल्य वर्धित कर को 29% से घटाकर मात्र 4% कर दिया गया है। यह निर्णय राज्य के सभी हवाई अड्डों पर लागू होगा।

राज्य के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कैबिनेट बैठक के बाद एक बयान में कहा, कसरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत एटीएफ पर वैट 29% से घटाकर 4% करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से हवाई यात्रा की टिकटों की कीमत में गिरावट आएगी और राज्य में अधिक व्यावसायिक उड़ानों को आकर्षित किया जा सकेगा।'

उन्होंने आगे बताया कि पहले केवल गया हवाई अड्डे पर ही 4 प्रतिशत वैट की सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन अब यह सुविधा राज्य के सभी हवाई अड्डों पर दी जाएगी।

सम्राट चौधरी ने कहा कि इस निर्णय से राज्य के पर्यटन क्षेत्र को भी गति मिलेगी। 'बिहार में कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं जहां देश-विदेश से पर्यटक आते हैं। वैट में कमी से हवाई यात्रा सस्ती होगी और पर्यटक आसानी से बिहार आ सकेंगे।'

सरकार का मानना है कि इस फैसले से राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पर्यटन व विमानन उद्योग के माध्यम से राजस्व में भी इजाफा होगा।

यह निर्णय केंद्र सरकार के आग्रह पर लिया गया है। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बिहार सरकार से अनुरोध किया था कि एटीएफ पर वैट को 4 प्रतिशत तक घटाया जाए, ताकि राज्य में हवाई संपर्क को बेहतर किया जा सके।

अभिव्यक्ति की आजादी लेकिन जिम्मेदारी से

डॉ. के.पी. सिंह
पूर्व पुलिस महानिदेशक

एक 22 वर्षीय छात्रा और सोशल मीडिया पर सक्रिय प्रभावी शर्मिष्ठा पनौली को पश्चिम बंगाल पुलिस ने गुरुग्राम से 'ऑपरेशन सिंदूर' पर एक विवादास्पद वीडियो को लेकर गिरफ्तार किया था। इस वीडियो में उसने तथाकथित अपमानजनक और सांप्रदायिक भाषा का प्रयोग किया था। 3 जून, 2025 को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शर्मिष्ठा को अंतरिम जमानत देने से यह कहते हुए इंकार कर दिया कि 'इस विविधता से भरे देश में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यह मतलब नहीं है कि दूसरों को कष्ट पहुंचाएं।' लेकिन दो दिन बाद ही कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उसे यह कहते हुए जमानत दे दी कि उसके खिलाफ की गई शिकायत में किसी संज्ञेय अपराध का घटित होना नहीं पाया गया।

9 मई, 2025 को पुणे पुलिस ने एक 19 वर्षीय इंजीनियरिंग की छात्रा खदीजा को भी सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के समर्थन में संदेश पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। यही नहीं, मुख्य दण्डाधिकारी (सांसद-विधायक) मऊ की विशेष अदालत ने 31 मई, 2025 को यूपी के विधायक अब्बास अंसारी को 2022 के चुनाव प्रचार में घृणित भाषण देने का दोषी ठहराया था। राहुल गांधी को भी वर्ष 2019 की एक राजनीतिक रैली में 'सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है' जैसी अभद्र टिप्पणी पर अदालत ने आपराधिक मानहानि का दोषी ठहराया था।

हाल ही में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यू-ट्यूबर अजय शुक्ला के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की है, क्योंकि उसने उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। ये वही न्यायाधीश थे जिन्होंने मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के मामले की सुनवाई की थी। 22 मई, 2025 को हरियाणा पुलिस ने अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को एक तथाकथित आपत्तिजनक ट्वीट करने पर गिरफ्तार किया था। उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकरण में गहन जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एस-ाआईटी) के गठन का आदेश पारित किया है। अशोका विश्वविद्यालय के संस्थापक ने यह स्पष्ट किया है कि सामाजिक सक्रियता एक विकल्प हो सकता है, स्वतंत्र कला शिक्षण का अनिवार्य हिस्सा नहीं। सामाजिक सक्रियता और शैक्षणिक कार्य दो अलग-अलग बौद्धिक विचारधाराएं हैं। वहीं शिक्षाविदों का मानना है कि इस आजादी के बिना अनुसंधान और बौद्धिक कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

सोशल मीडिया पर सक्रिय व्यक्तियों ने पहले ही कई मासूम लोगों की मानसिक शांति और जीवनयापन के ढंग को प्रभावित किया है। इसमें दो राय नहीं है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं की जननी है, लेकिन यदि इसे बिना किसी जवाबदेही के प्रयोग में लाया जाएगा तो यह आत्मघाती भी सिद्ध हो सकती है। दैनिक इंडियन एक्सप्रेस अखबार बनाम भारत सरकार (1985) में उच्चतम न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी के पीछे चार व्यापक सामाजिक उद्देश्य बताए थे : पहला, यह व्यक्ति को आत्म-संतुष्टि प्राप्त करने में सहायक है, दूसरा, यह सत्य की खोज में सहायक है। तीसरा, यह निर्णय लेने की प्रक्रिया में व्यक्ति की भागीदारी की क्षमता को मजबूती प्रदान करता है तथा चौथा, यह एक ऐसा तंत्र प्रदान करता है जिसमें स्थिरता और सामाजिक परिवर्तन के बीच संतुलन बनाया जा सके।

आदर्श रूप में किसी भी अभिव्यक्ति को संयम और उद्देश्य की छलनी से गुजरना ही होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) में स्पष्ट किया गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यह अर्थ कतई नहीं है कि कोई व्यक्ति बिना आधार के गैर जिम्मेदाराना आरोप लगाए अथवा टिप्पणियां करे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को परिस्थितियों में प्रतिबंधित किया जा

सकता है यदि इससे भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशों के साथ संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, अदालत की अवमानना अथवा किसी की मानहानि होने का अंदेशा हो या किसी अपराध के लिए उकसाए जाने का खतरा हो।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) का तात्पर्य यह है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बिना जिम्मेदारी के नहीं मिलती। अभिव्यक्ति की आजादी, सभी प्रकार के विचार से ऊपर उठकर प्रत्येक व्यक्ति पर जिम्मेदारी और जवाबदेही निर्धारित करती है, ताकि राज्य के वैध हितों को कोई हानि न पहुंचे। भारतीय न्याय संहिता 2023 (बीएनएस) की धारा 152 के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की एकता व अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्यों के लिए सजा का प्रावधान है। इसी संहिता की धारा 196 के अनुसार धर्म, नस्ल, जन्मस्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर समुदायों के बीच दुश्मनी फैलाने और सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाना अपराध घोषित किया गया है। धारा 197 राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाले कार्यों के लिए व्यक्ति के लिए दण्ड का प्रावधान करती है। धारा 296 में अश्लीलता और अभद्रतापूर्ण व्यवहार को सजा की श्रेणी में रखा गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जीने के अधिकार जितना ही पवित्र माना गया है, लेकिन जब इसे किसी व्यक्ति द्वारा किसी की मानहानि करने अथवा व्यंग्यात्मक और अपमानजनक टिप्पणी करने तक ले जाया जाए तो उसकी जवाबदेही भी उसी व्यक्ति पर आनी चाहिए।

1982 में जोधपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ए.एन. निगम को तत्कालीन प्रधानमंत्री के विरुद्ध की गई अपमानजनक टिप्पणी के कारण निलंबित कर दिया गया था। उच्चतम न्यायालय ने प्रोफेसर निगम को किसी भी प्रकार की राहत देने से इंकार कर दिया था। मानहानि के प्रकरण में राहुल गांधी की सजा को निलंबित करते हुए उच्चतम न्यायालय ने राजनेताओं को सलाह दी थी कि 'सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति को भाषण देते समय सावधानी बरतनी चाहिए।' राधा मोहन लाल बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय मामले में उच्चतम न्यायालय ने चेतावनी दी थी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को न्यायपालिका के विरुद्ध बेबुनियाद और शरारती आरोप लगाने की आजादी न समझा जाए। ध्यान रहे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करते समय शालीनता और सामाजिकता की सीमाओं का उल्लंघन न हो।

आदर्श रूप से, संविधान में निहित विचारों की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की शक्ति का उपयोग समाज में नकारात्मकता फैलाने की बजाय मानवता के समग्र कल्याण और विकास के लिए किया जाना चाहिए। छात्रों और सोशल मीडिया पर सक्रिय युवाओं को मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यवहार के तौर-तरीकों को लेकर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। उन्हें सोशल मीडिया पर निहित स्वार्थी तत्वों की प्रयोग की गई भाषा और व्यंग्य के तौर-तरीकों की आंख बंद करके नकल करने से बचना चाहिए।

कानून लागू करने वाली एजेंसियों को भी स्पष्ट कानूनी अर्थों में प्रावधान को समझने और उन्हें लागू करने की आवश्यकता है। उन्हें किसी अभिव्यक्ति के पीछे के वास्तविक इरादों को उसके अभिव्यक्ति के समय, लहजे, भाव, संदर्भ और उद्देश्य के आधार पर समझने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। पुलिस के कानूनों को शाब्दिक रूप में पढ़ने की प्रवृत्ति और उन्हें सत्ता के आदेशानुसार चुनींदा रूप से लागू करने की नियत के कारण पहले ही पुलिस की छवि खराब हो चुकी है। पुलिस को समझना चाहिए कि बिना दुर्भावना या अपराध को भड़काए बिना की गई अभिव्यक्ति कोई अपराध नहीं होती है। उम्मीद करें कि न्यायपालिका कानून के प्रयोग से संबंधित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सभी मामलों की कानूनी जांच के लिए उचित मानदंड और एक समान मानक निर्धारित करेगी।

(लेखक हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक हैं।)

कैंसर पर जीत फिर विश्व सुंदरी का खिताब

अरुण नैथानी

पिछले दिनों भारत में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारतीय प्रतिनिधि नंदिनी गुप्ता की दावेदारी भले ही शीर्ष बीस तक सिमट कर रह गई हो, लेकिन थाईलैंड की सुंदरी ओपल सुचाता ने विश्व सुंदरी का खिताब जीतकर खूब सुर्खियां बटोरीं। उल्लेखनीय है कि थाईलैंड में भारतीय संस्कृति का व्यापक प्रभाव रहा है, उनके नाम का उच्चारण भी कुछ-कुछ भारतीय-सा लगता है। नतीजे में उनके नाम ने भी भारतीयों का ध्यान खींचा। जिसे भारतीय फिल्मों के प्रति उनकी दीवानगी ने और पुख्ता भी किया। मई महीने में भारतीय दुनियाभर से आई सुंदरियों की चहल-पहल लगातार सौंदर्य प्रतियोगिता से जुड़े विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों के जरिए महसूस करते रहे थे। तेलंगाना के हैदराबाद स्थित हाईटेक्स में संपन्न ग्रैंड फिनाले में आखिरकार ओपल सुचाता के सिर विश्व सुंदरी का ताज सजा।

दरअसल, इस खिताब को जीतकर ओपल सुचाता ने थाईलैंड के 72 साल से मिस वर्ल्ड के ताज के इंतजार को खत्म किया। सुचाता एक साधारण पृष्ठभूमि से आती हैं। और विश्व स्तरीय सौंदर्य स्पर्धा के शिखर तक पहुंचती हैं। हालांकि, यह हकीकत है कि सौंदर्य प्रतियोगिता के मानक व उद्देश्य सौंदर्य प्रसाधन बाजार को विस्तार देने का ही एक उपक्रम है। बहुत संभव है हमारे आसपास व दूरदराज के इलाकों में जो वास्तविक विश्व स्तरीय सौंदर्य हो, वो इस प्रतियोगिता के कायदे-कानूनों से नकार दिया जाएगा। बहरहाल, बहते वक्त की धारा में आज ओपल सुचाता विश्व सुंदरी हैं। उनकी कामयाबी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वे एक कैंसर सर्वाइवर हैं। साथ ही लगातार महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूक कर रही हैं।

मिस वर्ल्ड के 72वें संस्करण में मिस वर्ल्ड चुनी गई ओपल सुचाता चुआंगश्री ने खिताब हासिल करने के बाद कहा कि उनका ताज सिर्फ थाईलैंड का ही प्रतिनिधित्व नहीं करता बल्कि वह उन करोड़ों महिलाओं की आवाज भी है, जिन्हें अनसुना किया गया। वे उनके हक के लिये खड़ी होंगी। दरअसल, ओपल ने अठारह वर्ष की उम्र से सौंदर्य प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना शुरू किया। उनका मानना था कि उनका सौंदर्य स्पधाओं में भाग लेना नेम-फेम कमाना ही नहीं था, बल्कि इस उपलब्धि को उद्देश्यपूर्ण बनाना ही मुख्य लक्ष्य था। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर थाईलैंड की संस्कृति को भी सम्मान दिलाना एक मकसद था। उल्लेखनीय है कि ओपल वर्ष 2024 में मिस यूनिवर्स स्पर्धा में थाईलैंड का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। तब वह तीसरे स्थान पर आई थीं। मिस वर्ल्ड स्पर्धा के लिए उन्होंने वह खिताब छोड़ दिया। उनका मानना है कि इस खिताब को हासिल करने का उनका मुख्य मकसद यह है कि वे सामाजिक बदलाव की वाहक बन सकें।

ओपल का मानना है कि यह खिताब सिर्फ सौंदर्य मानकों पर खरा उतरना मात्र नहीं है। ओपल मानती हैं कि यह लोगों के लिये सुंदर काम करने के लिए दिया गया खिताब है। वे उस भारतीय दर्शन की हामी हैं कि दैहिक सौंदर्य अल्पकालिक होता है, लेकिन सुंदर उद्देश्य सार्वकालिक होता है। उनका एक सपना यह भी है कि वे एक दिन राजदूत बनें।

दरअसल, 21 वर्षीय ओपल वर्षों से ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी महिलाओं के लिए काम कर रही हैं। वैसे तो हर विश्व सुंदरी अपनी जीत के बाद समाज सेवा और करुणा के प्रति प्रतिबद्धता जताने में पीछे नहीं रहती, लेकिन कैंसर ओपल का भोगा यथार्थ है। वे उस त्रासदी से गुजरी हैं और कैंसर पीड़ितों के दर्द को करीब से महसूस करती हैं। यही वजह है कि उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूकता का प्रसार करने वाले कई सामाजिक संगठनों के साथ सक्रिय भागेदारी की है। उनका मानना है कि वे नई जिम्मेदारियों के बावजूद ब्रेस्ट कैंसर पीड़ितों के लिए काम करती रहेंगी। उनका कहना है कि महिलाओं को रूटीन चेकअप करते रहना चाहिए। उन्हें डॉक्टर के पास जाने में संकोच नहीं करना चाहिए। यदि इस महामारी का समय रहते पता चल जाए तो इससे बचाव संभव हो सकता है। उनका कहना है कि मैं इस मुद्दे पर लगातार महिलाओं से बात करती रहना चाहूंगी।

ओपल बौद्धिक रूप से समृद्ध हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मनोविज्ञान व मानव से जुड़े विज्ञान में उनकी गहरी रुचि भी है। इतना ही नहीं वे जीव-जंतुओं के प्रति गहरी संवेदना रखती हैं। उनका पशु प्रेम इस बात से झलकता है कि उनके घर में दर्जन से अधिक बिल्लियां व करीब आधा दर्जन कुत्ते पलते हैं।

बहरहाल, विश्व सुंदरी के खिताब से मिली प्रतिष्ठा के साथ ओपल आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर व समृद्ध हुई हैं। उनकी तमाम योजनाएं अब सिरे चढ़ने वाली हैं क्योकि इस खिताब के साथ-साथ उनके खाते में एक मिलियन डॉलर भी आए हैं।

वहीं दूसरी ओर ओपल भारतीय संस्कृति व फिल्मों के प्रति भी खासा लगाव रखती हैं। पिछले दिनों खिताब जीतने के बाद एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि बॉलीवुड की फिल्में उन्हें आकर्षित करती हैं। उन्होंने गंगुबाई फिल्म देखी। यदि मुझे बॉलीवुड में काम करने का मौका मिला तो मैं आलिया भट्ट के साथ काम करना पसंद करूंगी।

भारत की राष्ट्रीय पार्टियों का भविष्य

प्रभु चावला
वरिष्ठ पत्रकार, स्तंभकार

भारतीय राजनीति में जहां वंशवाद हावी है, वहां सत्ता ही एकमात्र ऐसी चीज है, जिसे छीना जाना जरूरी है। तेलंगाना की भारत राष्ट्र समिति ने भाई-बहन के बीच लड़ाई की ऐसी प्रतियोगिता आयोजित की है, जिसके सामने रियलिटी शो भी शर्मिंदा है। के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने अपने पिता की विरासत पर हमला करते हुए आरोप लगाया है कि उनके 'गलत सलाहकारो' ने उन्हें पार्टी का भाजपा में विलय करने की सलाह दी है, जबकि उनके भाई केटी रामा राव डूबते जहाज के कप्तान की तरह पार्टी के फैसले से बंधे हुए हैं।

यह सड़ांध सभी वंशवादी पार्टियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जहां भाई-बहन, भतीजे-भतीजे और बेटे जाति, समुदाय और क्षेत्रीय गौरव के नाम पर लड़ते हैं। बीआरएस के तेलुगु क्षेत्र से लेकर एनसीपी के महाराष्ट्र तक, सपा के यादव वर्चस्व से लेकर आरजेडी के ओबीसी वर्चस्व तक, बीएसपी के दलित सपनों से लेकर तृणमूल के बंगाली जोश तक, डीएमके की द्रविड़ जड़ों से लेकर पीएमके की वन्नियार पहचान तक, यही प्रवृत्ति

दिखाई देती है। ये सभी पार्टियां सामाजिक और क्षेत्रीय पहचानों पर पलती-बढ़ती हैं, लेकिन इनके पारिवारिक विवाद इन वास्तविकताओं की सच्चाई को उजागर करते हैं।

क्या ये राजनीतिक वंशज झगड़ों के बाद भी अपना राजनीतिक अस्तित्व बनाए रख पाएंगे? क्या समृद्धि और शिक्षा इन वंशवादी दलों को खत्म कर देगी? और इनके राजनीतिक भाग्य का हमारे राजनीतिक दलों के भविष्य से क्या लेना-देना है? स्वतंत्र तेलंगाना राज्य के आंदोलन के दौरान जन्मी बीआरएस ने तेलुगु स्वाभिमान को अपना आधार बनाया। लेकिन कविता की बगावत और पार्टी पर केटीआर की मजबूत पकड़ ने दिखा दिया है कि पार्टी अपनी पहचान खो सकती है। केसीआर इस मुद्दे पर चुप हैं, लेकिन उनके वंशजों की आपसी लड़ाई उन मतदाताओं को अलग-थलग कर सकती है जो स्वतंत्र तेलंगाना राज्य के लिए एकजुट हुए थे, अगर बीआरएस टूटती है तो इसका फायदा भाजपा और कांग्रेस उठाएंगे। बिहार में आरजेडी ओबीसी और मुस्लिम वोट बैंक और लालू प्रसाद की सवर्ण विरोधी विरासत पर टिकी है।

उनके बेटे तेजप्रताप और तेजस्वी के बीच विवाद चल रहा है। तेजप्रताप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 'जयचंद' और पुराने रोमांस का जिक्र है। इस पर तेजप्रताप की अलग रह रहीं पत्नी ऐश्वर्या की शिकायती प्रतिक्रिया पार्टी से मतदाताओं को दूर कर सकती है, अगर राजद अलग-थलग पड़ गया तो राज्य का युवा फिर से भाजपा या नीतीश कुमार के पास जा सकता है, लेकिन अगर तेजस्वी के मार्गदर्शन में राजद मजबूत होकर उभरी तो वह भाजपा के वर्चस्व को चुनौती देगी और कांग्रेस को महागठबंधन में राजद का अनुसरण करना पड़ेगा।

उत्तर प्रदेश में यादव और ओबीसी पहचान के आधार पर बनी सपा अभी भी 2016 के पारिवारिक झगड़े से उबर नहीं पा रही है, हालांकि अखिलेश अब सपा के वोट बैंक के साथ मजबूती से खड़े हैं, लेकिन राज्य के शहरी युवा जातिवाद से कम प्रभावित हैं, अगर सपा और बिखरती है तो हिंदुत्व और विकास मॉडल के जरिए भाजपा राज्य में और मजबूत होगी और कांग्रेस को और भी हाशिये पर धकेल देगी। वहीं अगर सपा यादव-मुस्लिम आधार को मजबूती से थामे हुए साथ आती है तो भाजपा को कड़ी चुनौती मिल सकती है।

एनसीपी ने मराठा गौरव और मजबूत ग्रामीण नेटवर्क के साथ महाराष्ट्र में एक मजबूत आधार बनाया था, लेकिन पार्टी 2023 में अजीत पवार के भाजपा में जाने के सदमे से अभी तक उबर नहीं पाई है। यदि यथास्थिति बनी रही, तो भाजपा और उसकी सहयोगी शिवसेना का दबदबा बना रहेगा, जबकि कांग्रेस को शहरी क्षेत्रों में कुछ समर्थन मिलेगा, लेकिन अगर एनसीपी एकजुट होती है, तो वह किंगमेकर बन सकती है।

दलितों को सशक्त बनाने के लक्ष्य को लेकर बसपा आगे बढ़ी और मायावती इसकी केंद्र बिंदु बनीं। मायावती का अपने भाई आनंद कुमार और भतीजे आकाश आनंद को पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देने का फैसला भाई-भतीजावाद का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। जाटव और दलित बसपा का वोट बैंक रहे हैं, लेकिन भाजपा के विकास कार्यों के प्रति शिक्षित दलितों के आकर्षण के कारण बसपा का जनाधार सिकुड़ रहा है, अगर बसपा पर वंशवाद का बोझ रहा तो भाजपा इसका फायदा उठाकर उत्तर प्रदेश में खुद को और मजबूत करेगी, जबकि कांग्रेस को शहरी दलितों का कुछ वोट मिलेगा। दूसरी ओर, अगर मायावती अपनी सक्रियता छोड़ देती हैं और आकाश आनंद के नेतृत्व में बसपा खुद को मजबूत करती है, तो बसपा उत्तर प्रदेश की जातिगत राजनीति में राष्ट्रीय दलों को चुनौती देने की स्थिति में होगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के मार्गदर्शन पर चलती है और अभिषेक बनर्जी उनके उत्तराधिकारी हैं।

सांसद और महासचिव के तौर पर तृणमूल में अभिषेक के उदय ने पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को असहज कर दिया है। अभी पार्टी में सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर ममता के बाद पार्टी टूटती है तो राज्य के मतदाता भाजपा के पाले में जा सकते हैं। वहीं अभिषेक के नेतृत्व में एकजुट तृणमूल राष्ट्रीय दलों को अपने साथ खड़ा होने पर मजबूर कर सकती है।

तमिलनाडु में करुणानिधि के बेटे एमके स्टालिन उदयनिधि को अपना उत्तराधिकारी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। डीएमके नेतृत्व मजबूत है, लेकिन तमिलनाडु में खुशहाली लाने वाले आईटी युवाओं को वंशवाद पसंद नहीं है, अगर डीएमके अस्थिर होती है तो शहरी मतदाताओं का समर्थन भाजपा को मिलेगा और ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन एआईएडीएमके को मिलेगा, जबकि उदयनिधि के नेतृत्व में एकजुट डीएमके तमिलनाडु को क्षेत्रीय शक्ति बनाए रखेगी। अगर ये वंशवादी दल अलग हो जाते हैं तो भाजपा उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में बड़ी बढ़त हासिल कर लेगी।

कांग्रेस को अल्पसंख्यकों और शहरी मतदाताओं का समर्थन भी मिलेगा। जेडीयू और एआईएडीएमके जैसी क्षेत्रीय पार्टियों को भी फायदा हो सकता है, हालांकि 2029 के चुनाव में इस बात की संभावना ज्यादा है कि एकजुट बीआरएस, एसपी और डीएमके गठबंधन सहयोगियों पर दबाव बनाएंगे और भाजपा और कांग्रेस भी उनका अनुसरण करेंगी, लेकिन यह प्रक्रिया ज्यादा दिन नहीं चलेगी। भविष्य में राष्ट्रीय पार्टियों का बोलबाला होगा, क्योंकि लोग वंशवाद के आधार पर क्षेत्रीय पार्टियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन यह तभी होगा जब राष्ट्रीय पार्टियां राजनीति को परिवारवाद और वंशवाद से मुक्त करने की दिशा में काम करेंगी।

(लेखक के ये अपने विचार हैं।

मन्दिरों में बन्द हो पैसे लेकर एवं वीआईपी दर्शन

ललित गर्ग
स्तंभकार

ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में पैसे लेकर दर्शन कराने वाले बाउंसरों की गिरफ्तारी के बाद श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में सुगम दर्शन के नाम पर एक साथ इक्कीस लोगों की गिरफ्तारी जहां मंदिर प्रशासन की व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह है, वही ईश्वर के दरबार में पांव फैला रहा भ्रष्टाचार गहन चिन्ताजनक एवं शर्मनाक हैं। कुछ ही दिनों पहले ओंकारेश्वर स्थित ममलेश्वर मंदिर में भक्तों से वीआइपी दर्शन के नाम पर अवैध वसूली करने पर प्रशासन ने एक होमगार्ड जवान और दो पंडितों पर कार्रवाई की है। देश-विदेश के भक्त अगाध श्रद्धा से अपने आराध्य का दर्शन करने आते हैं, लेकिन देश के प्रमुख मन्दिरों में सीधे दर्शन कराने के नाम पर पैसों की लूट मची है या वीआईपी संस्कृति के नाम पर त्रासद एवं भेदभावपूर्ण स्थितियां पसरी है। सवाल यह पूछा जा रहा है कि हिंदुओं के धार्मिक स्थलों और आयोजनों में क्यों भक्तों के बीच भेदभाव होता है? मन्दिरों में गरीब एवं अमीर के बीच भेदभाव की स्थितियां खुला भ्रष्टाचार ही है। पैसे लेकर एवं वीआईपी दर्शन की अवधारणा भक्ति एवं आस्था के खिलाफ है। यह एक असमानता का उदाहरण है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी आघात करती है। श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में तो त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था भी है। मंदिर का चप्पा-चप्पा सीसीटीवी कैमरे की पहुंच में है। यह मन्दिर सुरक्षा कारणों से अतिसंवेदनशील स्थल होने के बावजूद ऐसा कृत्य खेदजनक ही नहीं, आपत्तिजनक भी है। मंदिर प्रबंधन को चाहिए कि दर्शन की प्रचलित व्यवस्था को और सुगम, भ्रष्ठाचार व दोषरहित बनाए ताकि व्यवस्था में कोई सेंध न लगे और जन-आस्था आहत न हो।

श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में तो सुगम दर्शन का शुल्क भी जमा कराया जाता है। लेकिन ठगों की जमात ने शीघ्र दर्शन के नाम पर कमाई का नया रास्ता तलाश लिया। मंदिर प्रबंधन को चाहिए कि वह सुगम दर्शन व्यवस्था के नाम पर हो रही धांधली को गंभीरता से ले। फर्जी पंडा, गाइड बनकर लोगों को झांसे में लेने वाले लोग अचानक एक दिन में डेरा नहीं जमाए होंगे। यह सब काफी समय से चल रहा होगा। इस प्रकार की ठगी करने की संभावना कैसे बन जाती है, इसकी जांच होनी चाहिए। बात केवल ठाकुर बांके बिहारी मंदिर या श्रीकाशी विश्वनाथ धाम की ही नहीं है, बल्कि देश के प्रमुख मन्दिरों में बढ़ती जन-आस्था की भीड़ एवं लम्बी-लम्बी लाइनों के बीच पैसे लेकर या वीआईपी दर्शन कराने की त्रासद एवं विसंगतिपूर्ण स्थितियों की हैं, जिसने न केवल देश के आम आदमी के मन को आहत किया है, बल्कि भारत के समानता के सिद्धान्त की भी धज्जियां उड़ा दी है। कुछ विशेष लोगों को मिलने वाले वीआईपी सम्मान एवं सुविधा पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है।

बांके बिहारी मंदिर में एक बार फिर वीआईपी कल्चर का खेल सामने आया है। मंदिर की भीड़ से हटकर वीआईपी दर्शन कराने के नाम पर एक निजी सुरक्षा एजेंसी ने बाउंसर उपलब्ध कराकर पैसे कमाने का गोरखधंधा शुरू कर दिया था। एजेंसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर प्रचार कर यह दावा किया कि वे श्रद्धालुओं को भीड़ से बचाकर विशेष वीआईपी दर्शन कराने में मदद कर सकते हैं। यह तो घोषित गैरकानूनी व्यवस्था है, लेकिन अन्य प्रमुख मन्दिरों में भी मन्दिर से जुड़े लोग या अन्य ठग पैसे लेकर दर्शन कराते हैं। सबसे ज्यादा दुखद एवं विडम्बनापूर्ण है वीआईपी दर्शन का प्रचलन। प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने पहले ही कार्यकाल के दौरान वीआईपी कल्चर को खत्म करते हुए लालबत्ती एवं ऐसी अनेक वीआईपी सुविधाओं को समाप्त कर

दिया था तो मन्दिरों एवं धार्मिक आयोजनों की वीआईवी संस्कृति को क्यों नहीं समाप्त किया? क्यों मन्दिरों में वीआईपी दर्शन के लिये सरकार ने अलग से व्यवस्थाएं की। दरअसल, वीआईपी संस्कृति का दायरा बहुत व्यापक है। यह धार्मिक स्थलों तक सीमित नहीं है। लोकतंत्र से लेकर आस्था तक, कई मौकों पर कुछ खास लोगों को विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत कहता है कि सभी नागरिक समान हैं, फिर भी व्यवहार में कुछ लोग 'विशेष' बन जाते हैं, चाहे वे सड़क पर हों, सरकारी दफ्तरों में, अस्पतालों में या मंदिरों में!

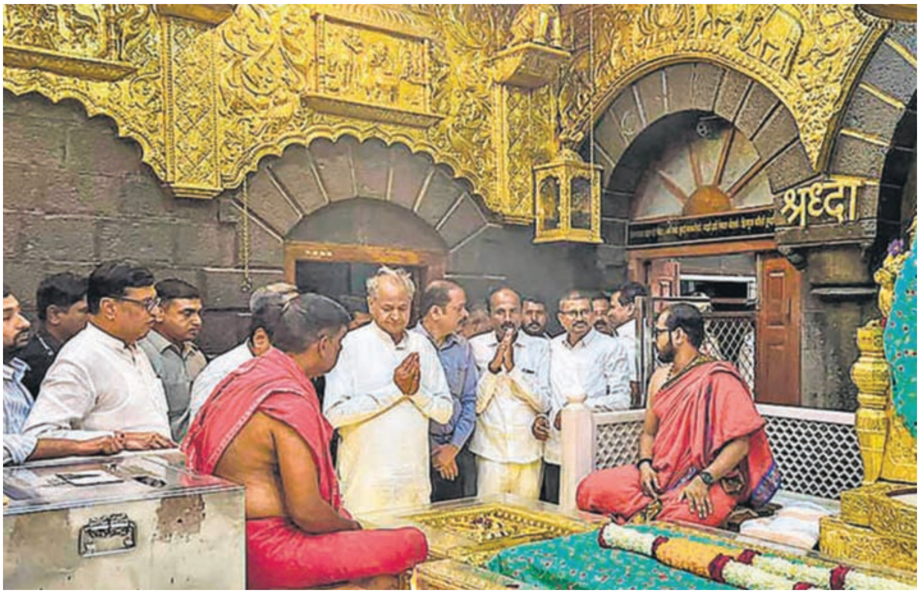

इसी तरह, बड़े नेताओं और अधिकारियों के लिये मन्दिरों में सीधे दर्शन कराने की व्यवस्थाएं हैं, जिससे लम्बी कतारे और लम्बे समय का इंतजार करती है। ऐसी व्यवस्था से मन्दिरों एवं धार्मिक आयोजनों में हादसें भी होते हुए देखे गये हैं। इन वीआईपी के लिए अक्सर यातायात रोक दिया जाता है, जिससे आम जनता घंटों जाम में फंसी रहती है। अस्पतालों में वीआईपी वार्ड हैं, जबकि आम मरीजों को बिस्तर भी नहीं मिल पाता। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर वीआईपी यात्रियों को विशेष सुविधाएं मिलती हैं, जबकि आम लोग लंबी कतारों में खड़े रहते हैं। वीआईपी संस्कृति एक नासूर बन गई है। यही कारण है कि हर सरकार वीआईपी संस्कृति को खत्म करने का वादा करती है, लेकिन हकीकत में इसे बनाए रखने के नए-नए तरीके खोजे जाते हैं।

वीआईपी कल्चर एवं पैसे लेकर दर्शन कराने की धांधली ने एक बार फिर से नए सिरे से बहस छेड़ दी है। सवाल उठ रहा है कि जब गुरुद्वारे में वीआईपी दर्शन नहीं, मस्जिद में वीआईपी नमाज नहीं, चर्च में वीआईपी प्रार्थना नहीं होती है तो सिर्फ हिन्दू मंदिरों में कुछ प्रमुख लोगों के लिए वीआईपी या पैसे लेकर दर्शन क्यों है? क्या इस पद्धति को खत्म नहीं किया जाना चाहिए, जो हिंदुओं में दूरिया पैदा करता है? प्रसिद्ध मन्दिरों में वीआईपी पास एवं दर्शन की व्यवस्था समाप्त क्यों नहीं होती? यह व्यवस्था समाप्त होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ही धार्मिक स्थलों पर होने वाली वीआईपी व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। निश्चित ही जब किसी को वरीयता दी जाती है और प्राथमिकता दी जाती है तो उसे वीवीआईपी या वीआईपी कहते हैं। यह समानता की अवधारणा को कमतर आंकना है। वीआईपी संस्कृति एक पथभ्रष्टता है, यह एक अतिक्रमण है, यह मानवाधिकारों का हनन है। समानता के नजरिए से देखा जाए तो समाज में इसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए, धार्मिक स्थलों एवं मन्दिरों में तो बिल्कुल भी नहीं।

न्यायालय भी देश में बढ़ती वीआईपी संस्कृति को लेकर चिन्तीत है। मद्रास उच्च न्यायालय की मुदुरै पीठ ने अपनी एक सुनवाई के दौरान कहा भी है कि लोग वीआईपी संस्कृति से 'हताश' हो गए हैं, खासतौर पर मंदिरों में। इसके साथ ही अदालत ने तमिलनाडु के प्रसिद्ध मंदिरों में विशेष दर्शन के संबंध में कई दिशा निर्देश जारी किए। राजस्थान में गहलोत सरकार ने भी मन्दिरों में वीआईपी दर्शनों की परम्परा को समाप्त करने की घोषणा की थी कि मन्दिरों में बुजुर्ग ही एकमात्र वीआईपी होंगे। इस तरह की सरकारी घोषणाएं भी समस्या का कारगर उपाय न होकर कोरा दिखावा होती रही है। अक्सर नेताओं एवं धनाढ्यों को विशेष दर्शन कराने के लिए मंदिर परिसरों को आम लोगों के लिये बंद कर दिया जाता है, जिससे श्रद्धालुओं को भारी परेशानी होती है, लोग वास्तव में इससे दुखी होते हैं और कोसते हैं। वीआईपी लोगों को तरह-तरह की सुविधाएं दी जाती है, मन्दिर के मूल परिसर-गर्भ परिसर में दर्शन कराए जाते हैं, उनके वाहन मन्दिर के दरवाजे तक जाते हैं, उनके साथ पुलिस-व्यवस्था रहती है, जबकि आम श्रद्धालुओं को कई किलोमीटर पैदल चलना होता है, भगवान के दर्शन दूर से कराए जाते हैं, उनके साथ धक्का-मुक्की की जाती है। लगता है मन्दिरों में दर्शन में सहभागिता को लेकर आम आदमी गुलामी की मानसिकता को ही जी रहा है। इन स्थानों पर उसके स्वाभिमान, सम्मान एवं समानता को बेरहमी से कुचला जा रहा है। ये कैसा मंदिर और ये कैसा दर्शन जहां सरेआम आम दर्शनार्थी का अपमान हो रहा है। इसलिए जिस भी मंदिर में वीआईपी दर्शन की सुविधा दी जा रही है उसके खिलाफ जनक्रांति हो। आज हिन्दू मन्दिरों की भेदभाव पूर्ण दर्शन-व्यवस्था को समाप्त करके ही आम आदमी को उसका उचित सम्मान किया जा सकता है, उसकी निराशा एवं पीड़ा को समझा जा सकता है। भाजपा सरकार मन्दिरों एवं धार्मिक-स्थलों से वीआईपी संस्कृति को समाप्त करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

हरियाणा में आज जो हालात हैं, वहां डिजिटल नहीं, टॉर्चर इंडिया का निर्माण हो रहा है। एक ऐसी स्थिति जहां फैमिली आईडी और सरल पोर्टल के कारण लाखों अभ्यर्थी जाति प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र और आय प्रमाणपत्र नहीं बनवा पा रहे हैं। जिसके बिना वह न तो सरकारी फॉर्म भर सकते हैं, न छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, न नौकरी की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं।

प्रियंका सौरभ
स्तंभकार

सरल पोर्टल की असफलता यानी हरियाणा के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़

'डिजिटल इंडिया' का सपना दिखाया गया था कि नागरिकों की जिंदगी आसान होगी। सरकारी सेवाएं घर बैठे मिलेंगी, लाइनें खत्म होंगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और हर बच्चा, हर छात्र, हर युवा आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम बढ़ाएगा। लेकिन हरियाणा में आज जो हालात हैं, वहां डिजिटल नहीं, टॉर्चर इंडिया का निर्माण हो रहा है। एक ऐसी स्थिति जहां फैमिली आईडी और सरल पोर्टल के कारण लाखों अभ्यर्थी जाति प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र और आय प्रमाणपत्र नहीं बनवा पा रहे हैं। जिसके बिना वह न तो सरकारी फॉर्म भर सकते हैं, न छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, न नौकरी की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। यह सिर्फ एक तकनीकी समस्या नहीं, लाखों युवाओं के भविष्य का सवाल है।

फैमिली आईडी : सुविधा या फांस?

हरियाणा सरकार की बनाई गई फैमिली आईडी को 'वन स्टेट, वन फैमिली, वन रिकॉर्ड' के नाम पर पेश किया गया था। लेकिन इसकी तकनीकी खामियों ने हजारों परिवारों को बेबस बना दिया है। कई अभ्यर्थियों की फैमिली आईडी में गलत नाम या जन्मतिथि दर्ज है। कुछ परिवारों में सदस्यों की संख्या गलत दर्ज है, तो कुछ में तो मृत व्यक्ति अभी भी जीवित दिख रहे हैं। बच्चों की माताओं के नाम गायब हैं, तो कभी कभार जाति की जानकारी 'नोट एवेलेबल' बता दी जाती है। सरकार ने आदेश दे दिए – 'जो फैमिली आईडी में नहीं, वह सरकारी सुविधा में नहीं।' पर उस आईडी को दुरुस्त कौन करेगा? और कब?

सरल पोर्टल मुश्किल प्लेटफॉर्म!

अंत्योदय सरल

सरल पोर्टल को नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन बनाने के लिए शुरू किया गया था। लेकिन नाम के विपरीत ये पोर्टल ना तो सरल है, ना ही सुचारु। लॉगिन नहीं होती, या बार-बार लॉग आउट कर देती है। ओटीपी या तो आता नहीं, या देर से आता है। डॉक्युमेंट अपलोड 99% पर जाकर फेल हो जाता है। एक अपॉइंटमेंट स्लॉट के लिए छात्र 5-6 दिन तक सुबह से शाम तक वेबसाइट पर चिपके रहते हैं। एक फॉर्म भरने के लिए किसी छात्र को 7-8 दिन तक कंप्यूटर के आगे बैठना पड़े, तो वह पढ़ाई कब करेगा? मानसिक तनाव से कैसे बचेगा?

सीईटी की तारीखें बढ़ीं, पर सर्टिफिकेट कहां से?

सरकार ने सीईटी की फॉर्म डेट को बढ़ाकर दिखाया कि वह छात्रों की परवाह करती है। लेकिन सवाल यह है कि जब जाति और डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही नहीं बन रहे, तो छात्र फॉर्म भरें कैसे? हजारों छात्र ऐसे हैं जिनकी आयु सीमा अंतिम प्रयास पर है। ओबीसी/एससी/एसटी छात्र बिना सर्टिफिकेट के जनरल कैटेगरी में फॉर्म नहीं भर सकते। कई छात्र स्कॉलरशिप या आरक्षण के लाभ से वंचित हो सकते हैं। सरकार को यह समझना होगा कि केवल डेट एक्सटेंड कर देना समाधान नहीं है, जब तक सिस्टम का मूल ढांचा ही ध्वस्त हो।

कौन जिम्मेदार है इस टॉर्चर के लिए?

जब कोई छात्र परेशान होता है, वह अपनी शिकायत लेकर सोशल मीडिया पर जाता है। कुछ मीडिया चैनल आवाज उठाते हैं। परंतु जब मंत्री या विभाग प्रमुख यह कहकर पल्ला झाड़ते हैं कि 'पोर्टल तो ठीक है। तब स्पष्ट हो जाता है कि या तो वे जमीनी हकीकत से कटे हुए हैं, या जानबूझ-कर आंखें मूंद रखी हैं। नायब सैनी जी, क्या आपने कभी खुद सरल पोर्टल खोल कर देखा है कि वह कैसे चलता है? क्या आपने उन छात्रों से बात की है जिनकी उम्र, परीक्षा और सपना इस पोर्टल की देरी के कारण छिन गया?

लाखों युवाओं का प्रश्न : आखिर कब सुधरेगा सिस्टम?

हरियाणा में ही बार-बार क्यों ऐसी दिक्कतें आती हैं? दूसरे राज्यों में छात्र बिना किसी तकनीकी अड़चन के फॉर्म भरते हैं। वहां के पोर्टल ठीक से चलते हैं, डेटा सेव होता है, और सरकारी सिस्टम सहयोग करता है। पर हरियाणा में डिजिटल पोर्टल एक मानसिक यातना गृह बन चुके हैं। सरकार कहती है - 'बेरोजगारी खत्म करेंगे।' पर सवाल ये है - 'क्या नौकरी पाने का मौका भी देंगे?'

क्या समाधान?

सरल पोर्टल की आपातकालीन मरम्मत हो तकनीकी टीम को पोर्टल 24x7 मॉनिटर करने का आदेश मिले। यदि जरूरी हो तो आईआईटी या निक जैसी एजेंसियों से मदद ली जाए। फैमिली आईडी अपडेट प्रक्रिया को तेज और ऑफलाइन विकल्पों के साथ दोबारा शुरू किया जाए। जिलों में विशेष कैंप लगाकर पेंडेंसी दूर की जाए। सभी प्रमाणपत्र बनाने की अंतिम तारीख सीईटी फॉर्म से पहले तय की जाए, ताकि छात्र पहले डॉक्युमेंट तैयार कर सकें। एक सिस्टम हो, जहां छात्र व्यक्तिगत रूप से शिकायत दर्ज करवा सकें। और उन्हें समयबद्ध समाधान मिले। राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाई जाए, केवल चुनाव के समय युवाओं की तस्वीरें लगाकर 'बेरोजगारी भत्ता' देने के वादे न करें, बल्कि व्यवस्था सुधारें।

यह केवल तकनीकी नहीं, नैतिक विफलता है

सरकार की असली परीक्षा तब होती है जब नागरिक संकट में हो। हरियाणा के लाखों छात्र, किसान, गरीब, श्रमिक - सब पोर्टल के इस जाल में फंसे हुए हैं। यदि एक भी छात्र का भविष्य इस कारण से बर्बाद होता है कि वह सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाया – तो यह किसी भी संवेदनशील सरकार के लिए शर्म की बात होनी चाहिए। 'डिजिटल इंडिया' का मतलब डिजिटल शोषण नहीं है। सरकार को जिम्मेदारी लेनी ही होगी।

पिता-पुत्र का रिश्ता बेजोड़ ही नहीं विलक्षण भी कहलाता है

ललित गर्ग
स्तंभकार

भारतीय संस्कृति में पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा माना गया है। पिता ही धर्म है, पिता ही संबल है, पिता ही ताकत है। पिता हर संतान के लिए प्रेरणा, प्रकाश और संवेदनाओं के पुंज हैं। इसके महत्व को दर्शाने और पिता व पिता तुल्य व्यक्तियों के योगदान को सम्मान देने के लिए हर साल जून महीने के तीसरे रविवार को अंतर्राष्ट्रीय पिता दिवस यानी फादर्स डे मनाया जाता है। इस साल 15 जून, 2025 फादर्स डे है।

दुनिया के अलग-अलग देशों में अलग-अलग दिन और विविध परंपराओं के कारण उत्साह एवं उमंग से यह दिवस मनाया जाता है। यह एक ऐसा दिन है, जिसे अपने पिता के सम्मान के लिए मनाया जाता है, साथ ही पितृत्व, पैतृक बंधन और समाज में पिताओं के प्रभाव को भी याद किया जाता है। हिन्दू परंपरा के मुताबिक पितृ दिवस भाद्रपद महीने की सर्वपितृ अमावस्या के दिन होता है। पिता एक ऐसा शब्द है, जिसके बिना किसी के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक ऐसा पवित्र रिश्ता जिसकी तुलना किसी और रिश्ते से नहीं हो सकती। पिता ईश्वर का सबसे अच्छा उपहार हैं। जीवन मं कोई भी पिता की जगह नहीं ले सकता। पिता अपनी संतान के सच्चे शुभचिंतक एवं हितैषी होते हैं।

सोनेरा डोड जब नन्ही-सी थी, तभी उनकी मां का देहांत हो गया। पिता विलियम स्मार्ट ने सोनेरो के जीवन में मां की कमी नहीं महसूस होने दी। और उसे मां का भी प्यार दिया। एक दिन यूं ही सोनेरा के दिल में ख्याल आया कि आखिर एक दिन पिता के नाम क्यों नहीं हो सकता? इस तरह 19 जून, 1910 को पहली बार फादर्स डे मनाया गया। 1924 में अमेरिकी राष्ट्रपति कैल्विन कोली ने फादर्स डे पर अपनी सहमति दी। फिर 1966 में राष्ट्रपति लिंडन जानसन ने जून के तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाने की आधिकारिक घोषणा की। पिता ही बच्चों की सुरक्षा, विकास व समृद्धि के बारे में सोचते हैं। बावजूद बच्चों का पिता की लगातार उपेक्षा, दुर्व्यवहार एवं प्रताड़ना की स्थितियों बढ़ती जा रही है, जिन पर नियंत्रण के लिए इस दिवस की विशेष उपयोगिता एवं प्रासंगिकता है। मानवीय रिश्तों में दुनिया में सबसे बड़ा स्थान मां को दिया जाता है, लेकिन एक बच्चे को बड़ा और सभ्य बनाने में उसके पिता का योगदान कम करके नहीं आंका जा सकता।

पिता नीम के पेड़ जैसा होता है। उसके पत्ते भले ही कड़वे होते हैं, लकिन वो छाया ठंडी देता है। पिता और बच्चों का रिश्ता इस दुनिया में सबसे अलग होता है। एक तरफ पिता बच्चों को डांटते हैं, तो दूसरी तरह बच्चों से बेहद प्रेम भी करते हैं। पिता अपने बेटे की चोट पर व्यथित तो होता है, लेकिन उसे बेटे के सामने मजबूत बने रहना है। ताकि बेटा उसे देख कर जीवन की समस्याओं से लड़ने का पाठ सीखे, सख्त एवं निडर बनकर जिंदगी की तकलीफों का सामना करने में सक्षम हो।

भारतीय संस्कृति एवं संस्कारों में पिता को देवतुल्य माना गया है। हमारे ग्रन्थों में माता-पिता और गुरु तीनों को ही देवता माना गया है। इनकी सेवा और भक्ति में कसर रह जाए तो फिर ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं। और अगर हमने इनकी सेवा पूरे मन से की तो भगवान स्वयं कच्चे धागे से बंधे भक्त के पीछे-पीछे चल पड़ते हैं। इस दिवस को मनाने के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं। लेकिन सभी का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि वे अपने पिता के योगदान को न भूलें और उनको अकेलेपन की कमी को महसूस न होने दें। इतिहास में अनेकों ऐसे उदाहरण है कि पिता की आज्ञा से भगवान श्रीराम जैसे अवतारी पुरुषों ने राजपाट त्याग कर वनों में विचरण किया, मातृ-पितृ भक्त श्रवण कुमार ने अपने अन्धे माता-पिता को कांवड़ में बैठ-ाकर चारधाम की यात्रा कराई। फिर क्यों आधुनिक समाज में पिता और उनकी संतान के बीच दूरियां बढ़ती जा रही है।

आज के पिता समाज-परिवार से कटे रहते हैं और सामान्यतः इस

बात से सर्वाधिक दुःखी है कि जीवन का विशद अनुभव होने के बावजूद कोई उनकी राय न तो लेना चाहता है और न ही उनकी राय को महत्व देता है। समाज में अपनी एक तरह से अहमियत न समझे जाने के कारण हमारे पिता दुःखी, उपेक्षित एवं त्रासद जीवन जीने को विवश है। पिता को इस दुःख और कष्ट से छुटकारा दिलाना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। माँ ममता का सागर है पर पिता उसका किनारा है। मां से ही बनता घर है पर पिता घर का सहारा है। मां से स्वर्ग है मां से बैकुंठ, मां से ही चारों धाम है पर इन सब का द्वार तो पिता ही है। उन्हीं पिता के सम्मान में पितृ दिवस मनाया जाता है। आधुनिक समाज में पिता-पुत्र के संबंधों की संस्कृति को जीवंत बनाने की अपेक्षा है।

हर पिता अपने पुत्र की निषेधात्मक और दुष्प्रवृत्तियों को समाप्त करके नया जीवन प्रदान करता है। वरुण जल का देवता होता है। जैसे जल वस्त्र आदि के मैल को दूर करता है, वैसे ही पिता पुत्र की मानसिक कलुषता को दूर कर सद्संस्कारों का बीजारोपण करता है एवं उसके व्यक्तित्व को नव्य और स्वच्छ रूप प्रदान करता है। चंद्रमा सबको शांति और अह्लाद प्रदान करता है, वैसे ही पिता की प्रेरणाएं पुत्र को मानसिक प्रसन्नता और परम शांति देती है। जैसे औषधि दुख, दर्द और पीड़ा का हरण करती है, वैसे ही पिता शिव शंकर की भांति पुत्र के सारे अवसाद और दुखों का हरण करते हैं। पय का अर्थ है-दूध। जैसे माता का दूध पुष्टि प्रदान करता है, वैसे ही पिता पुत्र के आत्मिक बल को पुष्ट करते हैं। मेरे लिये मेरे पिता स्व. श्री रामस्वरूपजी गर्ग देवतुल्य एवं गहन आध्यात्मिक-धार्मिक जीवट वाले व्यक्तित्व थे। उनकी जैसी सादगी, उनकी जैसी सरलता, उनकी जैसा समर्पण, उनकी जैसी धार्मिकता, उनकी जैसी पारिवारिक नेतृत्वशीलता और उनकी जैसी संवेदनशीलता को जीना दुर्लभ है। उन्होंने परिवार एवं समाज को समृद्धशाली और शक्तिशाली बनाने की दृष्टि से उल्लेखनीय कार्य किया। मेरे लिये तो वे आज भी दिव्य ऊर्जा के केन्द्र हैं। मेरे पिता मेरे आदर्श हैं, मेरे पिता संघर्ष की आंधियों में हौंसलों की उड़ान रहे तो आत्मविश्वास की दीवार रहे।

पिता आंसुओं और मुस्कान का एक समुच्चय है, जो बेटे के दुख में रोता तो सुख में हंसता है। उसे आसमान छूता देख अपने को कद्दावर मानता है तो राह भटकते देख अपनी किस्मत की बुरी लकीरों को कोसता है। पिता गंगोत्री की वह बूंद है जो गंगा सागर तक एक-एक तट, एक-एक घाट को पवित्र करने के लिए धोता रहता है। पिता वह आग है जो घड़े को पकाता है, लेकिन जलाता नहीं जरा भी। वह ऐसी चिंगारी है जो जरूरत के वक्त बेटे को शोले में तब्दील करता है। वह ऐसा सूरज है, जो सुबह पक्षियों के कलरव के साथ धरती पर हलचल शुरू करता है, दोपहर में तपता है और शाम को धीरे से चांद को लिए रास्ता छोड़ देता है। पिता वह पूनम का चांद है जो बच्चे के बचपने में रहता है, तो धीरे-धीरे घटता हुआ क्रमशः अमावस का हो जाता है। पिता समंदर के जैसा भी है, जिसकी सतह पर असंख्य लहरें खेलती हैं, तो जिसकी गहराई में खामोशी ही खामोशी है। वह चखने में भले खारा लगे, लेकिन जब बारिश बन खेतों में आता है तो मीठे से मीठा हो जाता है। बचपन में चॉकलेट, खिलौने दिलाने से लेकर युवावर्ग तक बाइक, कार, लैपटॉप और उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजने तक संतान की सभी मांगों को पिता ही पूरा करते रहते हैं लेकिन एक समय ऐसा आता है, जब भागदौड़ भरी इस जिंदगी में बच्चों के पास अपने पिता के लिए समय नहीं मिल पाता है। इसी को ध्यान में रखकर पितृ दिवस मनाने की परंपरा की शुरूआत हुई।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार हैं)

समान शिक्षा प्रणाली एक दिवास्वप्न तो नहीं?

मो. जाहिद हुसैन
वरिष्ठ शिक्षक

समान शिक्षा प्रणाली की अवधारण अमीर और गरीब के बीच खाई को पाटने का एक सेतु है, जो सत्ता में संभ्रांत वर्गों के कॉकस के कारण आज तक लागू नहीं हो सका। समान स्कूल प्रणाली समुदाय आधारित एक ऐसे विद्यालय श्रृंखला की कल्पना है, जहां अमीर और गरीब के बच्चे एक ही छत के नीचे साथ-साथ पढ़ें- लिखें और खेलें- कूदें यानी अर्थ, जाति, धर्म, स्थान या लिंग का भेद किए बगैर सभी विद्यार्थियों के लिए तुलनात्मक रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराया जाए।

पड़ोस विद्यालय अथवा समान स्कूल प्रणाली की परिकल्पना कोठारी आयोग ने दी थी। शिक्षाविद प्रोफेसर अनिल सदगोपाल का मानना है कि कोठारी आयोग की अनुशंसा को पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968), दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) और 1986 का संशोधित रूप (1992) का कार्यान्वयन योजना यानी तीन बार स्वीकारा गया, लेकिन सरकार अलग-अलग सामाजिक तबकों के लिए अलग-अलग प्रकार की स्कूल व्यवस्थाएं खड़ी करके समान स्कूल व्यवस्था का सरेआम उल्लंघन करती रही। कोठारी साहब की हार्दिक इच्छा थी कि 1968 की शिक्षा नीति के बाद इसकी पूरी योजना बने। और इसे लागू कीजाए। लेकिन ऐसा न हो सका। और आज तक उनके सपनों की शिक्षा प्रणाली लागू न हो सकी।

बिहार में जब 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बनी, तो समाजवादी पृष्ठभूमि के मुख्यमंत्री के समय में 'राष्ट्रपति का हो बेटा या भंगी की संतान, सब की शिक्षा एक समान।' के आधार पर समान शिक्षा प्रणाली आयोग का गठन हुआ। यह बिहार के लिए बहुत ही गर्व की बात थी कि प्रथम बार समान शिक्षा प्रणाली लागू करने आयोग का गठन किया गया। अवकाश प्राप्त विदेश सचिव मुचकुंद दुबे को अध्यक्ष और तत्कालीन शिक्षा सचिव डॉक्टर मदन मोहन झा सचिव बनाए गए। और जाने-माने शिक्षा शास्त्री प्रोफेसर अनिल सदगोपाल को सदस्य बनाया

डॉ. दौलत सिंह कोठारी ने जिस समान स्कूल प्रणाली की कल्पना की थी, वह शिक्षा का एक आदर्श बगीचा था। लेकिन समाज की ठंडी ह-वाओं और असमान संरचना के कारण उसकी कोपलें कुम्हला गईं। सामाजिक अवरोध न होते, तो यह योजना अब तक एक अधिनियम बन चुकी होती। और लागू भी हो चुकी होती। डॉ. दौलत सिंह कोठारी ने जिस समान स्कूल प्रणाली की कल्पना की थी, वह शिक्षा का एक आदर्श बगीचा था। लेकिन समाज की ठंडी हवाओं और असमान संरचना के कारण उसकी कोपलें कुम्हला गईं। सामाजिक अवरोध न होते, तो यह योजना अब तक एक अधिनियम बन चुकी होती। और लागू भी हो चुकी होती।

गया। आयोग ने 8 जून, 2007 को 313 पृष्ठों की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। आयोग ने कहा कि अगले 5 वर्षों के दौरान राज्य के तमाम प्राथमिक और मध्य विद्यालयों की पाठ्यचर्या को गांधीवादी शिक्षा शास्त्रीय सिद्धांत के आधार पर रूपांतरित किया जाएगा।

समान शिक्षा प्रणाली में पैसे पर शिक्षा खरीदने की छूट किसी को नहीं मिलेगी। समान स्कूल प्रणाली (बिहार) की अवधारणा एक ऐसी कुंजी साबित हो सकती थी, जिससे कई ताले एक साथ खुल जाते। कुंजी एक और ताले अनेक। ताले उन दरवाजों पर जड़े थे, जो बिहार के भविष्य की ओर खुलते। यह 'मास्टर की' सांप्रदायिकता, भेद-भाव, वर्णाश्रम और थैलीवाद के तालों को भी खोल देती। और एक नवीन समतामूलक एवं समरस समाज की स्थापना भी करती।

यह कटु सत्य है कि जब तक बिहार की प्रगति नहीं होगी, भारत की प्रगति नहीं होगी। लेकिन हुआ यह कि जिस समान स्कूल प्रणाली से लोगों की काफी आशा थी, उसे बिहार विधान मंडल में कभी पेश ही नहीं किया गया। आयोग के सदस्य-सचिव समकालीन शिक्षा सचिव डॉ मदन मोहन झा जब तक जीवित रहे, येन-केन प्रकारेण समान स्कूल प्रणाली के कार्यान्वयन की दिशा में सक्रिय रहे। लेकिन उनके देहावसान के साथ ही बिहार समान स्कूल प्रणाली आयोग की अनुशंसा को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और युगांतकारी कदम को रोक दिया गया। और बिहार से पूरे भारत में एक अच्छा संदेश जो जाना था, वह नहीं जा सका।

शिक्षा का अधिकार-2009 समान स्कूल प्रणाली की परिकल्पना को तार-तार इस तरह कर दिया कि इसे टुकड़े-टुकड़े में लागू करने की योजना बन गई। 25% पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बहाने निजीकरण का चोर दरवाजा भी प्राथमिक शिक्षा में खोल दिया गया। यह समान शिक्षा प्रणाली को काट करने के लिए सरकार का एक कुत्सित प्रयास था, जो फ्यूज बल्ब का काम किया। और समान शिक्षा प्रणाली का अग्रेत्तर विकास रुक गया। समान शिक्षा प्रणाली यदि लागू हो जाती, तो मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार-2009 की आवश्यकता ही कहां पड़ती? मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार समान शिक्षा प्रणाली का एक अंश मात्र है।

यक्ष प्रश्न है कि 57 वर्षों में आज तक हमारे देश में समान स्कूल प्रणाली क्यों नहीं लागू हो सकी ? यदि लागू होता तो यह विद्यालयी शिक्षा में क्रांतिकारी कदम होता।

समान स्कूल प्रणाली में एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि चाहे नेता हो या अफसर का बेटा, उसी गांव या शहर के स्कूल में पढ़ेगा ,जिसके दायरे में उनका घर आता है। अब फायदे इस प्रकार समझे जा सकते हैं।

मानो कि एमपी या एमएलए साहब का बेटा उसी टूटे-फूटे स्कूल में पढ़ता है, जहां आम बच्चे पढ़ते हैं, तो कितना बदलाव आएगा ? आधारभूत संरचना से लेकर अकादमिक स्थिति सुधर जाएगी। इसका लाभ आम बच्चे को मिलेगा। इसलिए यह प्रणाली एकदम क्रांतिकारी है। फिर बच्चों को महंगे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। निजी विद्यालय अपने बोरिया बिस्तर समेट लेंगे। और सरकारी विद्यालय चकाचक करने लगेंगे। ऐसी ही कल्पना पड़ोस-विद्यालय या समान स्कूल प्रणाली में की गई है, जिसके अनेक फायदे हैं। इससे शिक्षा का बाजारीकरण की विकृति भी खत्म हो जाएगी।

इतिहास गवाह है कि 1911 में जब गोपाल कृष्ण गोखले ने ब्रिटिश विधान परिषद में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने का बिल लाया, तो उसे पास होने नहीं दिया गया। राजे-रजबाड़ों ने तो यह कहकर खिल्ली उड़ाई कि गरीबों के बच्चे जब पढ़ लिख गए, तो हमारी चाकरी कौन करेगा? हमारे खेतों में काम कौन करेगा?

प्रभावशाली लोग शिक्षा नीतियां बनने के बाद भी सही से कार्यान्वयन होने नहीं देते। समान स्कूल प्रणाली को खटाई में डालने के लिए इनकी भूमिका परोक्ष या अपरोक्ष रूप से रहती है। बहुत सारी नीतियों की कार्यान्वयन योजना वातानुकूलित कमरों में अभिजात्य वर्गों के बनाए जाने के कारण जमीन पर उतारी ही नहीं जाती। भारतीय समाज में यदि इसकी पृष्ठभूमि में जाएं, तो जातिवाद को भी पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है।

भारतीय समाज में अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब और गरीब। लघु उद्योग लगभग चौपट हो चुके हैं। और छोटे पूंजीपति बड़े पूंजीपतियों के आगे टिक नहीं पा रहे हैं। और तो और ऊपर से निजीकरण ने तो धनाढ्यों को जैसे कारून के खजाने की चाबी थमा दी गई। आमजन उद्योगपतियों और पूंजी पतियों के 'मुलायम चारा' बनते जा रहे हैं। आखिरकार सब ले देकर तो निम्न और मध्यवर्ग को ही झेलना पड़ता है। चाहे महंगाई हो या बेरोजगारी; क्योंकि पैसा बोलता है। बुर्जुआ वर्ग ने साम, दाम, दंड, भेद से सर्वहारा वर्ग को बस में कर रखा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के कार्यान्वयन के बाद यह अंदेशा है कि कॉरपोरेट वर्ल्ड शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को भी कम वेतन पर खटा सकते है। क्योंकि सरकारी नौकरियां धीरे-धीरे खत्म की जा रही हैं। सभी नौकरियां संविदा पर ही मिलने वाली हैं। और इसमें तो दाता का ही चलेगा, पाता का तो कुछ भी नहीं चलेगा। मालिक जब चाहे, उसे नौकरी से निकाल देगा।

डॉ. दौलत सिंह कोठारी ने जिस समान स्कूल प्रणाली की कल्पना की थी, वह शिक्षा का एक आदर्श बगीचा था। लेकिन समाज की ठंडी हवाओं और असमान संरचना के कारण उसकी कोपलें कुम्हला गईं। सामाजिक अवरोध न होते, तो यह योजना अब तक एक अधिनियम बन चुकी होती। और लागू भी हो चुकी होती।

तौबा तौबा कितनी गर्मी

शिखा चतुर्वेदी

दिल्ली भीषण गर्मी की चपेट में है। राजधानी के विभिन्न इलाकों में तापमान 40.9 से 45.0 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया, जबकि हीट इंडेक्स–यानी नमी और तापमान मिलाकर महसूस होने वाली गर्मी–51.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई। इसके चलते भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, जो सबसे ऊंचे स्तर की चेतावनी है।

दिल्ली कहां रही कितनी गर्मी

11 जून की शाम 5:30 बजे तक आयानगर सबसे गर्म रहा, जहां तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। इसके बाद पलम (44.5 डिग्री सेंटीग्रेड), रिज (43.6डिग्री सेंटीग्रेड), पीतमपुरा (43.5डिग्री सेंटीग्रेड), लोधी रोड (43.4डिग्री सेंटीग्रेड), सफदरजंग (43.3डिग्री सेंटीग्रेड) और मयूर विहार (40.9डिग्री सेंटीग्रेड) रहे। आयानगर में ह-ीटवेव की स्थिति दर्ज की गई।जबकि 10 जून को तीन स्टेशनों पर हीटवेव देखी गई थी।

बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने बताया कि 13 जून की रात से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिल्ली और उत्तर-पश्चिम भारत में हल्की बारिश और गरज के साथ छींटें पड़ने की संभावना है। इसके चलते गर्मी की तीव्रता में कमी आ सकती है और रेड अलर्ट की जगह ऑरेंज अलर्ट लागू किया जाएगा। 14 से 17 जून के बीच तापमान 37-42डिग्री सेंटीग्रेड तक आ सकता है।

गर्मी का असर केवल स्वास्थ्य और पर्यावरण तक सीमित नहीं है, इसका गहरा असर आर्थिक गतिविधियों पर भी दिख रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर में निर्माण कार्यों पर सीधा प्रभाव पड़ा है। भारत में अत्यधिक गर्मी के चलते 2030 तक अनुमानित 80 मिलियन वैश्विक नौकरी नुकसानों में से 34 मिलियन भारत में हो सकते हैं।

अनारॉक समूह के उपाध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि 'गर्मियों में निर्माण स्थलों पर श्रमिकों की कमी 20 से 50 प्रतिशत तक हो जाती है, जिससे परियोजनाएं प्रभावित होती हैं।'

यूनिनव डेवलपर्स के निदेशक अनुप गर्ग ने कहा, 'अत्यधिक गर्मी

से दिहाड़ी मजदूरों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, जिससे वे अनुपस्थित रहते हैं या साइट समय से पहले बंद करनी पड़ती है।'

हीट स्ट्रेस से निपटने के लिए कई कंपनियां आधुनिक तकनीकों की ओर रुख कर रही हैं। इनमें शामिल हैंः

-प्रिफैब्रिकेशन तकनीकः इससे साइट पर काम कम होता है और निर्माण की गति तेज होती है।

-एल्यूमिनियम फॉर्मवर्कः हल्के और दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले सांचे जो निर्माण प्रक्रिया को कारगर बनाते हैं।

-थ्रीडी प्रिंटिंगः संरचनात्मक घटकों को तैयार करने के लिए उपयोग हो रहा है जिससे कुशल श्रमिकों पर निर्भरता घटती है।

-वर्चुअल साइट विज़िट्सः दलालों और ग्राहकों को वर्चुअल टूल्स के जरिए साइट दिखाना।

बड़े डेवलपर्स ने अपने श्रमिकों के लिए नई सुरक्षा रणनीतियां अपनाई हैं जैसे किः

-दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच कार्य रोकना

-ठंडी जगहों में विश्राम

-इलेक्ट्रोलाइट्स, कूलिंग टॉवेल्स, फर्स्ट-एड सुविधा

-हीट स्ट्रोक के लक्षणों की पहचान का प्रशिक्षण

दिल्ली और उत्तरी भारत का मौजूदा गर्मी संकट न केवल जनस्वास्थ्य के लिए चुनौती है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था, श्रमिक उत्पादकता और निर्माण क्षेत्र के लिए भी गंभीर खतरा बन चुका है। राहत की उम्मीद 13 जून के बाद जताई जा रही है, जब मौसम कुछ मेहरबान हो सकता है। तब तक, नागरिकों और उद्योगों दोनों को सतर्क रहने और सुरक्षात्मक उपाय अपनाने की आवश्यकता है।

संजय सिन्हा
स्तंभकार

खतरनाक मोड़ लेता ईरान - इजरायल संघर्ष

ईरान पर लगातार परमाणु हमले किए जा रहे हैं। ऐसे समय में जब वाशिंगटन और तेहरान बातचीत कर रहे थे, ये हमले पूरी तरह से अवैध, लापरवाह और खतरनाक हैं। यदि बातचीत के माध्यम से परमाणु मुद्दे को हल करने की कोई संभावना थी, तो इजरायल ने व्यावहारिक रूप से इसे खत्म कर दिया है। इजरायल और ईरान के बीच हमले अब भी जारी हैं। हालांकि, यह लड़ाई फिलहाल दो देशों तक ही सीमित लगती है। संयुक्त राष्ट्र समेत तमाम देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। लेकिन क्या होगा ,अगर उनकी बात अनसुनी हो जाए? क्या होगा अगर लड़ाई बढ़ती और फैलती है? आशंका जताई जा रही है कि अगर इजरायल या ईरान दोनों में से किसी भी एक ने तनाव कम करने को लेकर कदम नहीं उठाए, तो हालात बिगड़ सकते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि ईरान अपने प्रॉक्सी की मदद से इजरायल पर हमले कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो इजरायल एक बार फिर जवाबी कार्रवाई कर सकता है।

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका के सभी इंकारों के बावजूद, ईरान का स्पष्ट रूप से मानना है कि अमेरिकी सेना ने इजराइल के हमलों का समर्थन किया। कम से कम मौन समर्थन तो जरूर दिया है। ईरान मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर सकता है - जैसे इराक में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज के कैंप, खाड़ी में सैन्य ठिकाने और क्षेत्र में अमेरिकी राजनयिक मिशन प्रमुख तौर पर निशाना बन सकते हैं। ईरान की प्रॉक्सी सेना - हमास और हिजबुल्लाह, इराक में इसके समर्थक मिलिशिया सशस्त्र हैं। और हमला करने में सक्षम हैं। अमेरिका को इस तरह के हमलों की आशंका थी। यही कारण था कि अमेरिका ने मध्य पूर्व से अपने कुछ कर्मियों और उनके परिवारों को वापस बुला लिया था। अपने सार्वजनिक संदेश में अमेरिका ने ईरान को अमेरिकी ठिकानों पर किसी भी हमले के परिणामों के बारे में सख्त चेतावनी दी है। अगर कोई अमेरिकी नागरिक

तेल अवीव या कहीं और मारा जाता है, तो डोनाल्ड ट्रंप खुद को कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर लंबे समय से ईरान को हराने में मदद करने के लिए अमेरिका को घसीटने का आरोप लगाया गया है। अगर अमेरिका युद्ध में शामिल होता है, तो यह एक लंबी और विनाशकारी परिणाम लेकर आएगा।

अगर ईरान इजरायल की मजबूत सेना और अन्य लक्ष्यों को नुकसान पहुंचाने में विफल रहा, तो वह हमेशा खाड़ी में अपने मिसाइलों को नरम लक्ष्यों पर निशाना बना सकता है, खासकर उन देशों पर जिनके बारे में ईरान का मानना है कि उन्होंने वर्षों से अपने दुश्मनों की मदद की। और उन्हें बढ़ावा दिया। क्षेत्र में बहुत सारे ऊर्जा और बुनियादी ढांचे ईरान के लक्ष्य हैं। याद रखें कि ईरान पर 2019 में सऊदी अरब के तेल क्षेत्रों पर हमला करने का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा 2022 में ईरान के प्रॉक्सी हूती विद्रोहियों ने यूएई पर कई मिसाइल हमले किए थे। हाल के वर्षों में ईरान का कुछ खाड़ी देशों से मेल-मिलाप हुआ है। इसमें यूएई, कतर, जॉर्डन, ओमान और सऊदी अरब भी शामिल हैं। लेकिन ये देश अमेरिकी एयरबेस की मेजबानी भी करते हैं। कुछ ने पिछले साल ईरानी मिसाइल हमले से इजराइल की रक्षा करने में भी मदद की थी। अगर खाड़ी पर हमला हुआ, तो उसे भी अमेरिकी युद्धक विमानों की जरूरत पड़ सकती है, जो इजरायल के साथ-साथ उसकी रक्षा के लिए भी आ सकते हैं। क्या होगा अगर ईरान की परमाणु फैसिलिटी बहुत गहराई में स्थित हों, और बहुत अच्छी तरह से संरक्षित हैं? क्या होगा अगर उसका 400 किलोग्राम 60% समृद्ध यूरेनियम - परमाणु ईंधन जो पूरी तरह से हथियार-ग्रेड होने से बस एक छोटा कदम दूर है, जो दस बमों के लिए पर्याप्त है - नष्ट नहीं होता? ऐसा माना जाता है कि यह गुप्त खदानों में छिपा हो सकता है। इजरायल ने भले ही कुछ परमाणु वैज्ञानिकों को मार दिया हो, लेकिन कोई भी बम ईरान के ज्ञान और विशेषज्ञता को नष्ट नहीं कर सकता।

क्या होगा अगर इजरायल के हमले से ईरान के नेतृत्व को यह विश्वास हो जाए कि आगे के हमलों को रोकने का एकमात्र तरीका परमाणु क्षमता के लिए जितनी जल्दी हो सके, दौड़ना है? क्या होगा अगर मेज पर बैठे नए सैन्य नेता अपने मृत पूर्ववर्तियों की तुलना में अधिक हठी और कम सतर्क हों? कम से कम यह इजरायल को और अधिक हमले करने के लिए मजबूर कर सकता है, जिससे संभावित रूप से क्षेत्र लगातार हमले और जवाबी हमले के दौर में बंध सकता है। इजरायलियों के पास इस रणनीति के लिए एक क्रूर वाक्यांश है; वे इसे 'घास काटना' कहते हैं।

तेल की कीमत पहले से ही आसमान छू रही है। क्या होगा अगर ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने की कोशिश की, जिससे तेल की आवाजाही और भी सीमित हो गई? क्या होगा अगर - अरब प्रायद्वीप के दूसरी तरफ - यमन में हूथियों ने लाल सागर में शिपिंग पर हमला करने के अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया? वे ईरान के आखिरी बचे तथाकथित प्रॉक्सी सहयोगी हैं, जिनका अप्रत्याशितता और उच्च जोखिम की भूख का ट्रैक रिकॉर्ड है। दुनिया भर के कई देश पहले से ही जीवन-यापन की लागत के संकट से जूझ रहे हैं। तेल की बढ़ती कीमत वैश्विक आर्थिक प्रणाली में मुद्रास्फीति को बढ़ाएगी, जो पहले से ही ट्रंप के टैरिफ युद्ध के बोझ तले दबी हुई है। और यह न भूलें कि तेल की बढ़ती कीमतों से लाभ पाने वाले एकमात्र व्यक्ति रूस के राष्ट्रपति पुतिन हैं, जो यूक्रेन के खिलाफ अपने युद्ध के लिए भुगतान करने के लिए क्रेमलिन के खजाने में अचानक अरबों डॉलर की बाढ़ देखेंगे। अगर संघर्ष खाड़ी के पानी और राज्यों में फैल जाता है, तो यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी होगा, खासकर भारत के लिए, जिसके लाखों नागरिक इस क्षेत्र में काम करते हैं। और रहते हैं। यहूदी राज्य पर लगाम लगाने और पश्चिम एशिया में स्थिरता बहाल करने के लिए कूटनीति को फिर से शुरू करने के लिए तत्काल, समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयास होना चाहिए।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और सोशल एक्टिविस्ट हैं)

भाजपा के दावे और एम्स की सच्चाई

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री, श्री प्रताप राव जाधव ने 21 मार्च, 2025 को अपने लिखित जवाब में जो आंकड़ा लोकसभा में प्रस्तुत किया है, वो चौंकाने वाला है। उन्होंने बताया है कि मई, 2024 से सितंबर, 2024 के बीच 2,546 मरीजों को दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया है। यानी मात्र पांच महीनों में रायपुर एम्स को 2,546 मरीज दूसरे अस्पतालों में रेफर करने पड़े हैं। ये आंकड़ा बता रहा है कि मरीजों का रेफरल किसी अपवाद का मामला नहीं है, बल्कि एम्स की स्थिति खुद नाजुक है। और स्वास्थ्य राज्यमंत्री का लोकसभा में लिखित जवाब इसकी पुष्टि करता है।

राज कुमार

भाजपा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (एम्स) के बारे में कई दावे कर रही है। भाजपा ने अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक पोस्टर ट्वीट किया है, जिसमें दावा किया गया है कि पिछले ग्यारह साल में भारत में आठ एम्स बने हैं, इनकी संख्या में तीन गुणा बढ़ोत्तरी हुई है। और अब भारत में 23 एम्स हो गए हैं। क्या भाजपा के दावे सही हैं या ये आधी-अधूरी सच्चाई है? आइये, पड़ताल करते हैं।

देश में एम्स की स्थिति

भाजपा आधी-अधूरी जानकारी दे रही है, वो ये तो बता रही है कि देश में 23 एम्स हैं, लेकिन ये नहीं बता रही कि इनमें से कितने फंक्शनल हैं और जो फंक्शनल हैं, क्या उनमें पूरे डॉक्टर और स्टाफ है? तो सबसे पहले एम्स की संख्या और उनकी स्थिति जान लेते हैं कि देश में कितने एम्स फंक्शनल हैं और कितने नहीं। उसके बाद इन एम्स की हालत बात पर करेंगे कि क्या इन एम्स में प्रयाप्त डॉक्टर, स्टाफ, तकनीक और सुविधाएं हैं?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री, प्रताप राव जाधव ने 28 मार्च, 2025 को लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में एम्स के बारे में जनकारी दी है। जिसके अनुसार भारत में 23 एम्स हैं, लेकिन ये सारे के सारे सक्रिय नहीं है, इनमें से तीन संस्थान निमार्णाधीन हैं। और एक संस्थान का अब तक निर्माण भी शुरू नहीं हुआ है, उससे भी प्राथमिक स्टेज पर है। एम्स, रेवाड़ी (हरियाणा), एम्स अवंतिपुरा (कश्मीर), एम्स मदुरई (तमिलनाडु) निर्माणाधीन हैं और एम्स, दरभंगा (बिहार) का निर्माण कार्य भी अभी शुरू नहीं हुआ है, स्थिति प्री इन्वेस्टमेंट स्टेज पर है।

यानी चार संस्थान सक्रिय नहीं है। यानी भारत में सक्रिय एम्स की संख्या 23 नहीं, बल्कि 19 है। अब एक बार उन संस्थानों पर भी नजर डालते हैं, जो सक्रिय हैं। देखते हैं कि उनमें डॉक्टरों और अन्य स्टॉफ की स्थिति क्या है?

एम्स में डॉक्टरों की स्थिति

देश में एम्स संस्थानों में फैकल्टी के कुल 5946 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 2236 पद, यानी 37% खाली पड़े हैं। फैकल्टी के सबसे ज्यादा खाली पद दिल्ली एम्स में हैं, दिल्ली में 432 पद रिक्त पड़े हैं। बिलासपुर एम्स में 52% पद खाली हैं, बाकि संस्थानों में भी स्थिति ऐसी ही है। देश में ऐसा एक भी एम्स

नहीं है जिसमें पूरी फैकल्टी हो।

नॉन-फैकल्टी पदों की स्थित भी गंभीर है। देश के सभी एम्स में नॉन-फैकल्टी (सीनियर/ जुनियर+नर्स) के 53,730 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 16,501 पद, यानी 30% पद खाली पड़े हैं। नॉन-फैकल्टी के सबसे ज्यादा खाली पद दिल्ली एम्स में है। दिल्ली में 2,550 पद खाली पड़े हैं। पटना में 1,391, ऋषिकेश में 1,381, रायपुर में 1,136 और भोपाल एम्स में 1,038 पद खाली पड़े हैं। गुवाहाटी में 92% पद खाली हैं, पटना एम्स में 55% पद खाली हैं। और गोरखपुर में 44% पद खाली हैं। बाकि एम्स में भी स्थिति यही है, देश में ऐसा एक भी एम्स नहीं है, जिसमें नॉन-फैकल्टी के सभी पद भरे हुए हों।

नए एम्स में सुविधाओं की स्थिति-

रायपुर एम्स के बारे में सवाल का लोकसभा में दिया गया जबाब -

एम्स में डॉक्टर और अन्य स्टाफ की स्थिति के बारे में ऊपर विस्तार से बताया गया है। अब इन एम्स की गुणवत्ता पर बात करते हैं। जो नये एम्स बनाए गए हैं और जिनके बारे में भाजपा जोर-शोर से प्रचार कर रही है, उनकी स्थित क्या है ? लोकसभा में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से एम्स रायपुर के बारे में एक सवाल पूछा गया।

स्वास्थ्य मंत्री से पूछा गया कि रायपुर एम्स में मेडिकल सुविधाओं की कमी की वजह से मई, 2024 से सितंबर, 2024 के बीच कितने मरीजों को दूसरे मेडिकल में रेफर किया गया है ? ये सवाल साधारण है, लेकिन ये आंकड़ा रायपुर एम्स की मेडिकल सुविधाओं को आंकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

आमतौर पर बाकी अस्पतालों से रेफर होकर मरीज एम्स में आते हैं। अगर एम्स मरीजों को कहीं और रेफर कर रहा है तो स्थिति अजीब है। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक, रायपुर एम्स में पर्याप्त सुविधाएं और इंतजाम नहीं है, जो एक निश्चित संख्या के बाद मरीजों को रख पाएं और दूसरा कि बीमारी इतनी गंभीर है कि उसके इलाज के लिए पर्याप्त स्पेशलिस्ट, तकनीशियिन, तकनीक और मशीनें उपलब्ध नहीं है। इन दोनों ही स्थितियों में ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि एम्स पूरी तरह सुसज्जित नहीं है। तो रायपुर एम्स ने कितने मरीजों को दूसरे अस्पताल में रेफर किया है, ये आंकड़ा रायपुर एम्स की गुणवत्ता की स्थित को स्पष्ट कर देगा।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री, श्री प्रताप राव जाधव ने 21 मार्च, 2025 को अपने लिखित जवाब में जो आंकड़ा लोकसभा में प्रस्तुत किया है, वो चौंकाने वाला है। उन्होंने बताया है कि मई, 2024 से सितंबर, 2024 के बीच 2,546 मरीजों को दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया है। यानी मात्र पांच महीनों में रायपुर एम्स को 2,546 मरीज दूसरे अस्पतालों में रेफर करने पड़े हैं। ये आंकड़ा बता रहा है कि मरीजों का रेफरल किसी अपवाद का मामला नहीं है, बल्कि एम्स की स्थिति खुद नाजुक है। और स्वास्थ्य राज्यमंत्री का लोकसभा में लिखित जवाब इसकी पुष्टि करता है।

ऊपर दिये गए तमाम तथ्य और आंकड़े बता रहे हैं कि भाजपा के दावे आधी-अधूरी सच्चाई को पेश करते हैं और भ्रामक हैं।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार एवं फैक्ट-चेकर हैं।लेखक के ये विचार अपने हैं)

साहित्यकार को कॉम्यूनल नहीं कहा जा सकता: डॉ. विश्वनाथ त्रिपाठी

डॉ. विश्वनाथ त्रिपाठी बड़े साहित्यकार होने के साथ-साथ एक ज़िंदा दिल इंसान हैं। उनके चेहरे की हल्की मुस्कान धूप की तपिश में तपते इंसान के लिए बारिश की फुहार सी होती है। हर हाल में कैसे ख़ुश रहा जाता है, इस कला में उन्हें महारत हासिल है।
डॉ. विश्वनाथ त्रिपाठी में ग़ज़ब का सम्मोहन है। उनसे जो एक बार मिलता है, वह उनके साथ बने रहना चाहता है। उनके पास शब्द हैं, शिल्प हैं, बिंब हैं। और विभिन्न भाषाओं की बेहतरीन जानकारी भी है।
31 मई की संध्या डॉ. विश्वनाथ त्रिपाठी को उनके आवास पर आचार्य हाशमी स्मृति पुरस्कार- 2025 प्रदान किया गया। आचार्य हाशमी स्मृति पुरस्कार- 2025 के तहत शॉल, शील्ड, प्रशस्ति-पत्र एवं 2100 रुपए की नगद राशि प्रदान की गई। यह पुरस्कार आचार्य हाशमी सौहार्द मंच के अध्यक्ष एवं दूसरा मत के संपादक ए आर आज़ाद ने प्रदान किया। इस अवसर पर जामिया मिलिया इस्लामिया के हिन्दी विभागाध्यक्ष प्रोफ़ेसर नीरज, दिल्ली विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफ़ेसर अनिल राय, मेघ देवता के लेखक सैयद असद आज़ाद एवं किरोड़ी मल कॉलेज के ओम भी ऐतिहासिक क्षण के साक्षी रहे।
आचार्य हाशमी स्मृति पुरस्कार-2025 से पहले डॉ. विश्वनाथ त्रिपाठी को कई अहम पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। इन्हें अब तक साहित्य अकादेमी का भाषा सम्मान और हिन्दी अकादमी का साहित्य सम्मान मिल चुका है। इसके अलावा व्यास सम्मान, मूर्तिदेवी पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार, मैथिलीशरण गुप्त सम्मान, डॉ. रामविलास शर्मा सम्मान, शमशेर सम्मान, शान्तिकुमारी वाजपेयी सम्मान, गोकुलचंद्र शुक्ल आलोचना पुरस्कार एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हो चुका है।

ए आर आज़ाद
वरिष्ठ स्तंभकार

अभी आचार्य हाशमी स्मृति पुरस्कार-2025 आपको प्रदान किया गया। यह पुरस्कार पाकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं?

मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। पुरस्कार तो मिलते रहते हैं। लेकिन यह पुरस्कार आचार्य हाशमी के नाम से है, एक ऐसे आदमी के नाम से है, जो भारत वर्ष में एकता का प्रतीक है, जिसका संबंध हिन्दी उर्दू से नहीं है बल्कि यह जानकर बहुत अच्छा लग रहा है कि बोलियों से है। मैथिली और अन्य बोलियों से है। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जिस ढंग से यह सम्मान प्रदान किया गया है, और इसे प्रदान करने वाले आज़ाद साहब जो उनके साहबज़ादे हैं, मुझे पाकर अच्छा लगा।

आज सांप्रदायिक सौहार्द की क्या स्थिति है। आपके ज़माने और इस ज़माने में कोई फ़र्क़ आया है?

देखिए, छुटपुट घटनाएं तो होती रहती हैं। लेकिन जो सबसे बुरा होना था, वो तो हो चुका। और इतना बुरा हो चुका कि उससे और बुरा कुछ हो नहीं सकता। हिन्दुस्तान तक़सीम हो गया। इससे बुरा तो कुछ हो नहीं सकता था। सांप्रदायिकता यानी कम्यूनिलिज़्म फ़िरक़ापरस्ती उसने अपना इतिहास का जो सबसे भयंकर कृत्य था, वो कर दिया। देश के दो टुकड़े कर दिए। तो मैं एक बात ये जरूर कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के जब टुकड़े हुए, तब फ़िज़ा बहुत ख़राब थी। बहुत उत्पात हुआ। बहुत हिंसा हुई। मुसलमान, जहां वो बहुतात में थे, उन्होंने हिन्दुओं को मारा। हिन्दुओं ने भी कम नहीं मारा। हिन्दुओं ने भी बहुत मारा मुसलमानों को। और ये टुकड़े होना ही ग़लत था। लेकिन गांधी जी नहीं चाहते थे। उन्होंने तो कहा था कि मेरी लाश पर देश के टुकड़े होंगे। और देश के टुकड़े होते ही उनकी लाश हो गई। यह भी सच है। जो होना था हो गया। लेकिन अभी भी छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं। मैं ठीक से नहीं जानाता कि पाकिस्तान में हिन्दुओं की क्या हालत है? और जो कहा जाता है, उसपर मैं यक़ीन नहीं करता। लेकिन ये लोग बताते हैं कि वहां आबादी बहुत कम हो गई है। हिन्दुस्तान में मुसलमान की हालत भी

ठीक नहीं है। लगभग सेकेंड सीटीजन के जैसा है। यह सच्ची बात है। इसको छुपाने की कोई बात नहीं है। आर्मी में पुलिस में उनकी मौजूदगी लगभ नहीं है। प्रधानमंत्री इस मुल्क का कोई मुसलमान होगा, ये मैं सोच नहीं सकता हूं। लेकिन फिर भी हिन्दुस्तान में मुसलमान इज़्ज़त की ज़िंदगी बसर करते हैं। अब हिन्दुस्तान के मुसलमान अपनी कट्टरता में पाकिस्तानी मुसलमान से अलग हैं। मैं यह महसूस कर रहा हूं। अब धीरे-धीरे उनके अंदर बदलाव आया है। गांव में जो ऐसे कट्टर मुसलमान होते थे, तो नारा लगाते थे- हँस कर लिया है पाकिस्तान और लड़कर लेंगे हिन्दुस्तान। तो अब वो बात नहीं है। अब उनको धीरे-धीरे लग रहा है कि हिन्दुस्तान के मुसलमान ज़्यादा सेफ़ हैं। मैं महसूस करता हूं कि वो देशभक्ति की तरफ़ हैं। पाकिस्तान से लड़ाई में तो कई मुसलमानों ने शहादत दी है। इसमें दो नाम तो बिर्गेडियर उस्मान और अब्दुल हमीद को तो सब जानते हैं। औऱ पता करने की जरूरत है कि कितने मुसलमान भारत-पाक की लड़ाई में शहीद हुए हैं। लेकिन अब हिन्दुस्तान की हालत बेहतर है। और पाकिस्तान की भी हालत बेहतर है।

हिन्दू मुसलमान के बीच जो ऩफरत की खाई है, वो तो बढ़ती जा रही है। यह स्थिति अचानक कैसे पैदा हुई?

यह अचानक नहीं पैदा हुई। रिलीजन में हम नफ़रत की बात करते हैं। हिन्दू-मुसलमान छोड़ दीजिए। शिया-सुन्नी में नफ़रत क्यों है? बाभन और चमार में क्यों लड़ाई? कायस्थ और बनिया क्यों लड़ते हैं आपस में? जहां आपने अपने को और लोगों से अलग करके यह बताना शुरू कर दिया कि हम तो बेहतर हैं, तो यह स्थिति बनने लगती है।

मेरा सवाल है कि यह सियासत है या यह सियासी साज़िश है?

सियासत तो उतनी नहीं है। सियासी साज़िश भी है। और सियासत वोट के लिए इलेक्शन में जीतने के लिए भड़काई जाती है। यहां पर और बातें करूंगा तो आप लोग कहेंगे कि पॉलटिक्स हो रही है। दो पार्टियां इस देश में ऐसी हैं, जो कास्टे के नाम पर वोट नहीं मांगती है। कांग्रेस और कम्यूनिस्ट। कम्यूनिस्ट की तो कुछ ऐसी जादू है केरला में के वो वहां बने रहते हैं। और त्रिपुरा में भी थे। कांग्रेस भी कास्ट पर वोट नहीं मांगती थी। जो लोग कास्ट पे वोट मांगते हैं, इन दिनों उनको वोट मिलता है। लेकिन कांग्रेस कभी कास्ट पोलटिक्स नहीं करती। इसलिए कई जगह नहीं जीतती है। इसलिए कम्यूनिस्ट कहीं नहीं जीत रही है। पता नहीं केरला में कैसे जीत रही है? मुझे समझ में नहीं आता। शायद एजुकेशन वहां बहुत है इसलिए।

अक्सर कहा जाता है कि लोग शिक्षित होंगे तो कट्टरता कम होगी। लेकिन आज शिक्षित लोग ज़्यादा हैं। और कट्टरता उन्हीं में देखी जा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे?

नहीं..नहीं।

इसी पर एक श्लोक है- दुर्जनः परिहर्तव्यः विद्ययाऽलंकृतोऽपि सन्

मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकर। आप क्या कहना चाहेंगे ?

यह तुमने बड़ी अच्छी बात कही है। एक हमारे दोस्त हैं बिनोद कुमार श्रीवास्तव। उनका एक उपन्यास है। उसमें उन्होंने कहा है कि जैसे-जैसे लोग पढ़ता-लिखता है, वैसे वैसे कम्यूनल होता चला जाता है। इसकी वजह पढ़ाई नहीं है। सभी के साथ ऐसा नहीं होता है। पढ़ लिखकर कोई सियासत में जाना चाहते हैं, तो कास्ट को एड्रेस करने के लिए यह एक इज़ी साधन है। आप अच्छा काम करके ज़्यादा वोट पाएं, यह मुशिकल है। जो वोटर है, वह इससे प्रभावित जल्दी हो जाता है। हमारे रक्त में इतना ज़हर है कि अच्छा काम करने वाले को वोट नहीं मिलता है।

क्या साहित्यकार भी इसके शिकार हैं ?

हां होंगे।

आपकी नज़र में साहित्यकार भी कम्यूनल हैं ?

साहित्यकार को कॉम्यूनल नहीं कहा जा सकता है। गांव का शब्द है चोरकट। एक चोर होते हैं। और जो कमीने चोर होते हैं, उनको चोरकट कहते हैं। ये चोरकट लोग जो होते हैं, वो ये सब काम करते हैं। कोई साहित्यकार बड़ा कैसे हो जाएगा कॉम्यूनिलज़्म फैलाकर ?

आपने साहित्य की शुरूआत कविता, कहानी, आलेख या निबंध से की ?

कविता से।

जिस समाज को आप देख रहे हैं इसे कैसा देखना चाहते हैं। समाज को लेकर आपकी क्या कल्पना है ?

समाज का सपना देखना बहुत सुना। और बहुत देखा। आदमी जो सपना देखता है, वह यथार्थ का ही एक रूप होता है। आदमी सबकुछ का सपना नहीं देख सकता। ज़िंदगी में जो है, वही बनकर सपना आता है।

एक घटना सुनाता हूं। प्रेमचंद से पूछा गया था कि आपका सपना क्या है।

उन्होंने कहा था कि बच्चों को नौकरी मिल जाए मेरे, और हिन्दुस्तान आज़ाद हो जाए। और दाल रोटी मिले। तो इतना सपना मेरा है। जब इंटरव्यू ख़त्म होने लगा, तो उन्होंने कहा, सुनो-सुनो एक और चीज़ चाहिए। दाल में एक तोला घी भी पड़ा रहे।

इसलिए मेरा सपना यही है कि इस समय बेरोज़गारी बहुत है। और ये लोग समझते नहीं है। हिन्दुस्तान की हालत पहले से बेहतर है। और उसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट जवाहर लाल नेहरू को है। इसमें मैं कोई समझौता नहीं कर सकता हूं। कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है। दुनिया के सामने दलित और नारियों की हालत बेहतर है। यह दो बड़े अचीवमेंट हैं। जो लोग कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, उन्हें उस वक़्त भेज दिया जाता तब पता चलता।

आज बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है। मेरी एक कविता है-

एक स्टूटेंड्स है मेरा
वाद-विवाद प्रतियोगिता में बहुत हिस्सा लेता है
लंबा है, पतला है, ख़ूबसूरत है
लेकिन
जब से एम ए पास हुआ है हकलाने लगा है...

तो नौकरी नहीं मिलती है। एक बेरोज़गार युवक क्या मॉरल बनेगा ? कैसे किसी के सामने सीना तान कर खड़ा होगा ? मेरे ख़्याल से शिक्षा बेहतर होनी चाहिए। और बेरोज़गारी दूर होनी चाहिए। मेरी प्रबल इच्छा यही है कि बेरोज़गारी दूर हो। और शिक्षा फैले।

व्यक्तिगत कोई सपना, जो अधूरा रह गया हो ?

अब मैं 95-96 साल का हो गया। मैं बहुत सटिसफ़ाइड हूं अपनी लाइफ़ से। जो कमी है, वो कमी कोई नहीं पूरी कर सकता। (रोते हुए) जब से सीमा की मां का देहांत हुआ, जैसा है वैसा ही रहे। बिना किसी लंबी बीमारी के मैं लिखना-पढ़ना चाहता हूं। मैं सौ साल तक जीना चाहता हूं। मैं मरना नहीं चाहता हूं। और एक बात और भी है मेरे अंदर, लोग भी बताते हैं। और मैं भी महसूस करता हूं कि ठीक ठाक हूं मैं अभी। दिल और दिमाग़ दुरुस्त हैं अभी मेरे। मुझे अच्छा लगता है सुनकर यह। लेकिन यह भी है कि ज़िंदा हूं, तो याद है। याद भी बहुत ताक़त देती है। बहुत ताक़त देती है। और जो पक्का होना ही है, मैं जब मरने लगूं तो मेरे बच्चे तो मेरे पास हो हीं, लेकिन ज़िंदगी की जो ख़ूबसरती है, वह भी मेरे सामने रहे। मेरी आंखों के सामने वो ख़ूबसरती रहे। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदीऔर मेरी बीवी यह दो मुझे याद आएं मरते समय। और मरने पर बहुत सोचता हूं। लेकिन यह लगता है कि मेरे स्टूडेंटस मुझे बहुत याद करेंगे।

आप अच्छे लेखक के साथ-साथ अच्छे वक्ता भी हैं। जब मेरी पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति सभागार में हो रहा था, तो आप धारा प्रवाह ऐसे बोल रहे थे कि बीच में आपको टोकना ठीक नहीं लगा। और कुल 30 मिनट का कार्यक्रम का समय तय था। लेकिन आपने 35 मिनट तक लाजवाब अंदाज़ में बिखरे चित्र, साहित्य, मुझपर और मेरे ख़ानदान पर स्पीच दिया। नतीजे में उपराष्ट्रपति के

इशारे पर उस कार्यक्रम को 35 मिनट से बढाकर 01.15 मिनट के लगभग किया गया। क्या आपने कभी सियासत में जाने का सोचा या कोई चुनाव लड़ा?

मैं राजनीति में रहा हूं। हां-हां। याद आया उपराष्ट्रपति वाला कार्यक्रम। मैंने इलेक्शन लड़ा। मैं सीपीआई का मेंबर हूं। डूटा का चुनाव जीता हूं। हा-ईएस्ट वोट मुझे मिला था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीपीआई को इतना वोट मिलना इंटरनेशनल इवेंट बन गया। फौरन मुझे मास्को भेजा गया। मैं कई बार मास्को घूम आया। मैं जेल भी गया हं। एक बार आरएसएस में रहते जेल गया। मैं आरएसएस का मेंबर था तगड़ा। और फिर कम्यूनिस्ट पार्टी में भी जेल गया। लेकिन अंदर नहीं गया। सज़ा दी गई थी कि जब तक कोर्ट नहीं उठता है, तब तक अरेस्ट हैं आप।

आपने आरएसएस और सीपीआई दोनों को देखा। यानी पश्चिम और पूरब दोनों को। लेकिन दोनों में से ज़्यादा पसंद कौन आया?

अरे पसंद नहीं। आरएसएस अच्छी नहीं है। आरएसएस में मैं तगड़ा कट्टर था। लेकिन वो ठीक नहीं था।

आपको लगा बाद में कि यह हमारे लायक़ नहीं है?

संक्रीण दिमाग़ है उसका।

कभी एमएलए-एमपी के चुनाव का ऑफ़र आया?

ऑफ़र नहीं आया। और जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि हट गया उधर से।

हिन्दुस्तान में कोई लेखक रॉयल्टी के बल पर ज़िंदा नहीं रह सकता ऐसा क्यों?

पहले लोग रॉयल्टी के बल पर ज़िंदा रहते थे।

हिन्दी और उर्दू में केवल है। बाक़ी भाषा में अगर आप चर्चे में हैं, तो आपके कमाने खाने के तरीके़ साहित्य से निकल जाते हैं।

आपको लगता है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। सरकार से आप इस तरह की कोई मांग करना चाहेंगे?

ज़रूर होना चाहिए। और सरकार से मैं ऐसी मांग भी करना चाहंगा। मैं तो यह कहूंगा कि लेखकों को रॉयल्टी ठीक से क्यों नहीं दी जाती है, इस पर प्रकाशकों से पूछताछ होनी चाहिए। और सीबीआई व ईडी जैसे सरकारी संस्थानों को प्रकाशकों पर नकेल कसनी चाहिए।

युवाओं के लिए कोई सूत्रवाक्य

कुल मिलाकर सुखी होना सच्चे अर्थों में सबसे बड़ी नैतिकता है। लेनिन ने कहा था कि आदमी को ज़िंदगी सिर्फ़ एकबार मिलती है, उस ज़िंदगी को ऐसे बसर करना चाहिए कि कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़े कि मैंने ऐसा काम किया। मगर ऐसा होता नहीं है। आदमी को बहुत ऐसे काम करने पड़ते हैं ज़िंदगी में जिससे कि शर्मिंदा होना पड़ता है। वो आदमी बड़ा बदक़िस्मत होगा, जो ज़िंदगी में कभी शर्मिंदा नहीं हुआ होगा। अच्छी जिंदगी होनी चाहिए। आदमी को नाशुक्रा नहीं होना चाहिए। मनहूस आदमी बहुत पापी होता है। ज़िंदगी से सिर्फ़ शिकायतें ही नहीं करनी चाहिए।

(साथ में मेघ देवता के लेखक सैयद असद आज़ाद)

तमाल बंद्योपाध्याय
वरिष्ठ स्तंभकार, राजस्थान

बैंकरों के सिर पर लटकती तलवार

'सतर्कता' सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के कर्मचारियों के लिए एक भयावह शब्द है। ऐसे भी उदाहरण हैं जहां उच्चाधिकारी इस भय का दुरुपयोग करते हैं। गत वर्ष राजस्थान में एक सरकारी बैंक के मुख्य प्रबंधक को सेवानिवृत्ति के एक दिन पहले नोटिस दिया गया। इसमें उन पर 2022 में एक रियल एस्टेट परियोजना की फाइनैंसिंग में धोखाधड़ी को लेकर आरोप लगाया गया था।

करीब दो साल तक चली विभागीय जांच के दौरान इस सरकारी बैंक के कई कर्मचारी सतर्कता जांच के दायरे में आए। ये कर्मचारी किसी न किसी तरह से ऋण मंजूरी या वितरण की प्रक्रिया से जुड़े हुए थे। मुख्य प्रबंधक को 35 साल के बेदाग कार्यकाल में पहली बार चार्जशीट मिली थी। सेवानिवृत्ति के पहले उनके पास इतना समय ही नहीं था कि वह लंबी विभागीय जांच का सामना करें और अपना बचाव करें। उन्होंने आरोप स्वीकार कर लिए। अगर वह स्वीकार नहीं करते तो उन्हें जांच पूरी होने तक सेवानिवृत्ति से जुड़े कई लाभों से वंचित होना पड़ता जिसमें पेंशन भी शामिल है। यह जांच कई साल चल सकती थी। अपने करियर के अंतिम दिन उन्हें छह वार्षिक वेतनवृद्धि रोककर दंडित किया गया। इसके साथ ही बेसिक वेतन पर महंगाई भत्ता भी कम किया गया।

ऐसी ही एक दूसरी घटना में एक सरकारी बैंक के मुख्य महाप्रबंधक का संबंध एक भारी भरकम ऋण से जोड़ा गया जो फंस गया था। इसके बाद एक सतर्कता जांच का प्रस्ताव रखा गया। जब वह कार्यकारी निदेश-क के पद पर पदोन्नति के लिए एक साक्षात्कार में शामिल होने गए तो यह जांच

रास्ते में आ गई।

बाद में वह आरोपों से बरी हो गए लेकिन उन्हें पदोन्नति के कई मौके गंवाने पड़े क्योंकि हर साक्षात्कार के समय उनके खिलाफ लंबित जांच सामने आ जाती। आखिरकार लंबी प्रतीक्षा के बाद वह कार्यकारी निदेशक बन गए लेकिन प्रबंध निदेशक नहीं बन सके क्योंकि उनके पास कम समय बचा था। भारत के सरकारी बैंकरों के लिए सतर्कता जांच सिर पर तलवार लटकने जैसा है। इसकी वजह से वे हमेशा भय और तनाव में रहते हैं। वे जनता के धन को संभालते हैं और ऐसे निर्णय लेते हैं जो कई बार गलत साबित हो सकते हैं और बैंक को नुकसान हो सकता है। बैंक को यह सवाल करना चाहिए कि यह वाणिज्यिक निर्णय के गलत होने का मामला है या इसमें गलत नीयत शामिल है? सतर्कता जांच जवाब तलाशने के लिए होती है लेकिन कई मामलों में ऐसी जांच अंतहीन चलती है जो संबंधित बैंकर पर बहुत भारी गुजरती है। ऐसे में कई बैंकर निर्णय नहीं लेने का निश्चय करते हैं ताकि सिर पर लटकती तलवार से बच सकें। विभागीय जांच बंद दरवाजों के पीछे होती हैं और साबित करने का बोझ जांचकर्ता पर नहीं होता। कुछ कमियों का उल्लेख और प्राथमिक दस्तावेजी प्रमाण बैंकरों को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त होते हैं।

जांच अधिकारी अक्सर आरोपित से वरिष्ठ होता है और वह जांच के नतीजे अनुशासनात्मक प्राधिकारी को सौंपता है। अनुशासनात्मक प्राधिकारी न्यायाधीश की भूमिका निभाता है और आरोप की गंभीरता के मुताबिक उसके पास निर्णय लेने के अधिकार होते हैं।

अगर किसी शाखा प्रबंधक द्वारा मंजूर खातों में फंसे कर्ज बढ़ते हैं तो उसकी सतर्कता जांच की जा सकती है। परंतु ऐसे फंसे कर्ज की कोई तय सीमा नहीं है। नियम कहते हैं कि तीन महीने में प्राथमिक जांच हो जानी चाहिए। परंतु प्राथमिक स्तर की तथाकथित सलाह लेने की कोई समय सीमा नहीं है। एक बार अनुशासनात्मक प्राधिकारी और मुख्य सतर्कता अधिकारी मामले को जांच लायक पाते हैं तो पहले चरण की सलाह मुख्य सतर्कता आयोग को भेज दी जाती है। मुख्य सतर्कता अधिकारी बैंक और सतर्कता आयोग तथा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के बीच पुल का काम करता है। यह अधिकारी बैंक के प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करता है। आमतौर पर इसकी नियुक्ति बैंक के बाहर से की जाती है ताकि निष्पक्षता बनी रहे। पहले चरण की सलाह के बाद बैंक आरोपपत्र जारी कर विभागीय जांच की शुरूआत करता है। ऐसी जांच में लगने वाला समय तीन माह से अधिक नहीं होना चाहिए और पूरी प्रक्रिया 15 महीने में पूरी हो जानी चाहिए। हालांकि इस समय सीमा का हमेशा पालन नहीं होता। अगर कोई बैंकर अनुशासनात्मक प्राधिकारी के दंड से पीड़ित महसूस करे तो वह आदेश मिलने के 45 दिन के भीतर अपील कर सकता है। आमतौर पर अपीलीय प्राधिकारी अनुशासनात्मक प्राधिकारी से एक पद ऊपर होता है। अगर बैंकर इसके निर्णय से भी असंतुष्ट रहा तो वह अदालत जा सकता है। वह मामला समय पर निपटाने के लिए भी अदालत की शरण ले सकता है।

गत माह एएम कुलश्रेष्ठ बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जांच की कार्यवाही को खारिज करते हुए आदेश दिया कि प्रभावित अधिकारी को सभी सेवानिवृत्ति लाभ दिए जाएं। ऐसे तमाम आदेश हैं जहां विभागीय जांच प्रक्रियाएं दिशानिर्देश के अनुरूप नहीं पाई गईं। हालांकि आमतौर पर अदालत विभागीय प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती बशर्ते कि प्रक्रिया के उल्लंघन के ठोस सबूत न हों। अलग-अलग बैंकों में एक जैसी गलतियों के लिए प्रक्रियाओं और दंड की प्रकृति अलग होती है। एक मामले में एक महाप्रबंधक के विरुद्ध विभागीय जांच एक दिन में पूरी हो गई थी और आरोप खारिज हो गए थे। ऐसा इसलिए किया गया ताकि उनकी पदोन्नति बाधित न हो क्योंकि अगले हफ्ते उनकी पदोन्नति का साक्षात्कार था। ऐसे भी मामले रहे हैं जहां अधिकारियों के समूह के खिलाफ आरोप थे लेकिन उनमें से एक को बरी कर बाकियों पर जांच चलती रही। यह सब इस पर निर्भर करता है कि आपके कितने मजबूत संपर्क हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2023 में मुख्य सतर्कता आयोग को 2,661 शिकायतें मिलीं जिनमें 554 शिकायतें तो साल 2022 की थीं। इनमें से 1995 शिकायतें निपटा दी गईं जबकि 706 लंबित रहीं। सतर्कता आयोग की 2023 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष2019 में 1,508 अधिकारियों को दंडित किया गया। वर्ष 2020 में यह आंकड़ा 2,652 और 2021 में 2,476 था। वर्ष2022 में 1,987 अधिकारियों को दंडित किया गया और 2023 में 1,509 अधिकारियों को दंडित किया गया।

यह डर सरकारी बैंकों के अधिकारियों को हमेशा निर्णय लेने से रोकता है। जितने कम निर्णय लिए जाएंगे मुश्किल में फंसने की उतनी ही कम संभावना होगी। दूसरी ओर सही निर्णय लेने पर कोई पुरस्कार नहीं मिलता। इस डर के अभाव में निजी बैंकों के कर्मचारी आक्रामक तरीके से कदम उठाते हैं और कारोबारी निर्णय लेते हैं। आश्चर्य नहीं कि सरकारी बैंक अपनी बाजार हिस्सेदारी उनके हाथों गंवा रहे हैं।

मुख्य सतर्कता आयोग ने सतर्कता के मामलों के समय पर निपटान पर जोर दिया है। गत माह उसने एक सर्कुलर जारी करके अधिकारियों से कहा कि वे जल्दबाजी के निर्णयों पर नजर डालें। उसने जोर देकर कहा कि वाणिज्यिक स्तर पर जोखिम लेना कारोबार का हिस्सा है और किसी सरकारी संगठन को हर नुकसान की जांच जरूरी नहीं है, फिर चाहे वित्तीय हो या कोई और। हाल में आई एक खबर के मुताबिक सरकारी बैंकों के भीतर एक कार्य समूह कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया के दिशानिर्देश तैयार कर रहा है। अब उम्मीद करनी चाहिए कि एक बार इसके बन जाने के बाद सरकारी बैंकों के कर्मचारियों के सिर पर हमेशा तलवार नहीं लटकेगी।

जब विवाह वारदात बन जाए

प्रेम, जो कभी विश्वास का प्रतीक था, अब सुपारी शब्द के साथ जुड़ने लगा है। विवाह, जो कभी दो आत्माओं का मिलन था, अब क्राइम थ्रिलर की स्क्रिप्ट लगने लगा है। हनीमून, जो सबसे सुंदर स्मृति बनती थी, अब हत्या का ठिकाना बन रहा है।

त्रिभुवन लाल साहू
स्तंभकार

मेघालय की भीगी वादियों में प्रेम की शुरूआत हुई थी कम से कम ऐसा दिखाया गया। एक नया जोड़ा, एक नया जीवन, और एक नया सफर जिसे 'हनीमून' कहा गया। लेकिन यह सफर, एक ऐसे मोड़ पर जाकर थम गया जहां से लौटना मुमकिन नहीं था एक खाई में गिरी लाश के साथ।

राजा रघुवंशी की कहानी कोई साधारण प्रेमकथा नहीं, बल्कि इस दौर के रिश्तों का कड़वा आइना है।

11 मई को शादी, 20 को टिकट, 23 को भ्रमण की शुरूआत। और फिर 2 जून को एक लाश। शादी से महज तीन हफ्ते में, वह रिश्ता जो सात फेरों के सात वचनों पर टिका था, मौत के कुएं में समा गया। और अब, सबसे बड़ा सच सामने है राजा की हत्या उसी ने करवाई, जिससे उसने जीवनभर साथ निभाने की कसमें खाई थीं।

यह सिर्फ एक हत्या नहीं, यह उस भरोसे की मौत है जिस पर हमारे समाज की नींव टिकी है। जब प्रेम छल बन जाए, जब दुल्हन ही शिकारी निकले, और जब 'हनीमून' ही साजिश की जमीन बन जाए तब समाज को सोचने की जरूरत है कि आखिर हम जा कहां रहे हैं?

बीते छह माह में देशभर में ऐसे कई मामले सामने आए, जहां पत्नियों ने अपने प्रेमियों के साथ मिलकर पतियों की निर्मम हत्या की। कोई फांसी पर लटका, किसी को टुकड़ों में काटा गया, किसी के पास सांप छोड़ा गया, तो किसी को हनीमून की वादियों में धकेल दिया गया।

क्या यह सब महज संयोग है? नहीं। यह पूरी तरह सुनियोजित हत्याएं हैं-ठंडे दिमाग से रची गईं, किराए के शूटरों से करवाई गईं, और सबसे खतरनाक मासूम भरोसे के नाम पर की गईं।

प्रेम, जो कभी विश्वास का प्रतीक था, अब सुपारी शब्द के साथ जुड़ने लगा है। विवाह, जो कभी दो आत्माओं का मिलन था, अब क्राइम थ्रिलर की स्क्रिप्ट लगने लगा है। हनीमून, जो सबसे सुंदर स्मृति बनती थी, अब हत्या का ठिकाना बन रहा है।

क्या अब प्रेम के नाम पर विश्वासघात ही बंधन की बुनियाद है? क्या रिश्तों में संवाद की जगह साजिशें ले रही हैं? क्या समाज ने स्त्रियों की स्वतंत्रता को समझे बिना केवल उसकी सीमाएं ढूंढ़ना शुरू कर दिया है?

बीते छह माह में देशभर में ऐसे कई मामले सामने आए, जहां पत्नियों ने अपने प्रेमियों के साथ मिलकर पतियों की निर्मम हत्या की। कोई फांसी पर लटका, किसी को टुकड़ों में काटा गया, किसी के पास सांप छोड़ा गया, तो किसी को हनीमून की वादियों में धकेल दिया गया।

क्या यह सब महज संयोग है? नहीं। यह पूरी तरह सुनियोजित हत्याएं हैं-ठंडे दिमाग से रची गईं, किराए के शूटरों से करवाई गईं, और सबसे खतरनाक मासूम भरोसे के नाम पर की गईं।

प्रेम, जो कभी विश्वास का प्रतीक था, अब सुपारी शब्द के साथ जुड़ने लगा है। विवाह, जो कभी दो आत्माओं का मिलन था, अब क्राइम थ्रिलर की स्क्रिप्ट लगने लगा है। हनीमून, जो सबसे सुंदर स्मृति बनती थी, अब हत्या का ठिकाना बन रहा है।

क्या अब प्रेम के नाम पर विश्वासघात ही बंधन की बुनियाद है? क्या रिश्तों में संवाद की जगह साजिशें ले रही हैं? क्या समाज ने स्त्रियों की स्वतंत्रता को समझे बिना केवल उसकी सीमाएं ढूंढ़ना शुरू कर दिया है?

महाराष्ट्र नगर निकायों के चुनाव की तैयारी शुरू

आगामी चुनाव महाराष्ट्र में 2022 से बदले राजनीतिक समीकरण के संदर्भ में होंगे। मुख्य चुनावी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), शिवसेना और राकांपा के सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन और विपक्षी गठबंधन 'महा विकास आघाडी' के बीच होने की उम्मीद है, जिसमें शिवसेना (उबाठा), राकांपा (शरदचंद्र पवार) और कांग्रेस शामिल हैं।

सुशील मिश्र

महाराष्ट्र में स्थानीय नगर निकाय के चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं और प्रशासनिक स्तर पर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार ने महापालिकाओं, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए वार्ड (प्रभाग) रचना के आदेश जारी किए हैं। दरअसल, महाराष्ट्र में पिछले 3-4 वर्षों से स्थानीय नगर निकाय के चुनाव लंबित थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है।

परिसीमन प्रक्रिया जारी

बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) सहित महाराष्ट्र भर के 29 नगर निगमों के वार्ड की सीमाओं को अंतिम रूप देने के लिए एक अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार, बीएमसी के लिए चुने जाने वाले पार्षदों की संख्या 227 तक सीमित कर दी गई है। मुंबई के प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद चुना जाएगा। इसके विपरीत अन्य नगर निगमों में हर वार्ड से चार पार्षद चुने जाएंगे, लेकिन यह संख्या तीन से पांच के बीच भी हो सकती है।

वार्ड परिसीमन प्रक्रिया राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) की मंजूरी के

साथ आगे बढ़ेगी। मुंबई के लिए बीएमसी के आयुक्त को मसौदा परिसीमन योजना तैयार करने का काम सौंपा गया है। अधिसूचना में निर्देश दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार शहर की आबादी को प्रति वार्ड औसत जनसंख्या निर्धारित करने के लिए पार्षदों की संख्या से विभाजित किया जाएगा। मसौदे को अंतिम रूप देने से पहले, नगर निकाय को जनता की आपत्तियों और सुझावों पर विचार करना चाहिए। अंतिम योजना, एक बार संशोधित होने के बाद, अनुमोदन के लिए राज्य चुनाव आयोग को प्रस्तुत की जाएगी और बाद में नगर निकाय के आयुक्त द्वारा प्रकाशित की जाएगी।

अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने की संभावना

नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों की वार्ड संरचना के लिए अलग-अलग आदेश दिए गए हैं। इसलिए अब यह स्पष्ट हो गया है कि आगामी अक्टूबर-नवंबर में नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के चुनाव होंगे। मुंबई समेत ए, बी और सी नगर पालिका क्षेत्रों में वार्ड संरचना का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी संबंधित आयुक्तों को सौंपी गई है, जबकि डी नगर निगम में वार्ड संरचना की जिम्मेदारी जिला कलेक्टरों को सौंपी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राजनीतिक आरक्षण के मुद्दे के कारण रुके हुए नगर निगम, नगर पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव चार महीने के भीतर कराए जाएं। तदनुसार, राज्य सरकार ने स्थानीय चुनावों के लिए काम करना शुरू कर दिया है। इस वार्ड संरचना के लिए लगभग ढाई महीने का समय लगेगा और इसके लिए गूगल मैप्स को आधार बनाने को कहा गया है।

आगामी चुनाव महाराष्ट्र में 2022 से बदले राजनीतिक समीकरण के संदर्भ में होंगे। मुख्य चुनावी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), शिवसेना और राकांपा के सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन और विपक्षी गठबंधन 'महा विकास आघाडी' के बीच होने की उम्मीद है, जिसमें शिवसेना (उबाठा), राकांपा (शरदचंद्र पवार) और कांग्रेस शामिल हैं।

वायरस से मुकाबला

विजय गर्ग
वरिष्ठ स्तंभकार

पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय के स्कूल आफ पब्लिक हेल्थ और पेन स्टेट के शोधकर्ताओं के किए गए एक हालिया अध्ययन में एम-आरएनए वैक्सीन का एक नया प्रकार विकसित किया गया है, जिसे 'ट्रांस-एमप्लीफाइंग एम-आरएनए प्लेटफार्म' नाम दिया गया है। एमआरएनए वैक्सीन का यह नया स्वरूप लगातार उत्परिवर्तित (म्यूटेट) होने वाले वायरसों- जैसे सार्स- सीओवी - 2 और एवियन इन्फ्लूएंजा ए (एचएन1) के लिए अधिक प्रभावी है। हालांकि वर्तमान एम-आरएनए वैक्सीन, जैसे कि कोविड- 19 को रोकने के लिए प्रयोग किए जाने वाले, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रेरित करने में अत्यधिक प्रभावी हैं, लेकिन ये दो महत्वपूर्ण चुनौतियां प्रस्तुत करते है- इनके उत्पादन के लिए बड़ी मात्रा में एम-आरएनए की जरूरत होती और वायरस के निरंतर भेष बदलने की प्रकृति । शोधपत्र के वरिष्ठ लेखक सुरेश कुचिपुडी के मुताबिक, 'वायरस बदलता रहता है, जिससे लक्ष्य भी बदलता है, और वैक्सीन को अद्यतन करने में समय लग जाता है।' यही वह बिंदु है जहां नई ट्रांस- एंप्लीफाइंग तकनीक वायरस का खेल बिगाड़ सकती है।

नई वैक्सीन तकनीक दो अलग-अलग एम-आरएनए अणुओं का प्रयोग करती है- रेप्लिकेस अनुक्रम और एंटीजन अनुक्रम। जहां रेप्लिकेस अनुक्रम एम-आरएनए अणु वायरस प्राप्त एक एंजाइम को कोड करता है जो कोशिका के अंदर एम-आरएनए की प्रतिलिपि बनाता है, जिससे एंटीजन उत्पादन बढ़ता है। वहीं एंटीजन अनुक्रम एम-आरएनए अणु वायरस के स्पाइक प्रोटीन जैसे संरचनात्मक प्रोटीन को कोड करता है, जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करता है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि रेप्लिकेस अनुक्रम को पहले से तैयार रखा जा सकता है। जब भी किसी नए वायरस के विरुद्ध वैक्सीन विकसित करनी हो, तो शोधकताओं को केवल नया एंटीजन जोड़ना होगा, जिससे उत्पादन लागत और समय में भारी बचत आएगी।

शोधकताओं ने सार्स- सीओवी - 2 के सभी प्रमुख वैरिएंट्स के स्पाइक प्रोटीन का विश्लेषण कर एक साझा संरचना निकाली, जिसे 'कंसेंसस स्पाइक प्रोटीन' कहा जाता है। यही तकनीक इस नई वैक्सीन का आधार बनी। इस नई वैक्सीन के निर्माण में एम-आरएनए की मात्रा पारंपरिक वैक्सीनों की अपेक्षा 40 गुना कम लगती है। इससे लागत में कमी आती है। बड़े पैमाने पर उत्पादन सरल होता है। इसकी व्यापक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के कारण बार-बार बूस्टर डोज की जरूरत भी कम हो सकती है। शोधकताओं को उम्मीद है कि भविष्य में इस कम लागत और व्यापक सुरक्षा वाले एंटीजन डिजाइन के सिद्धांतों पर आधारित वैक्सीन को बर्ड फ्लू जैसी अन्य जटिल चुनौतियों पर लागू किया जा सकेगा।

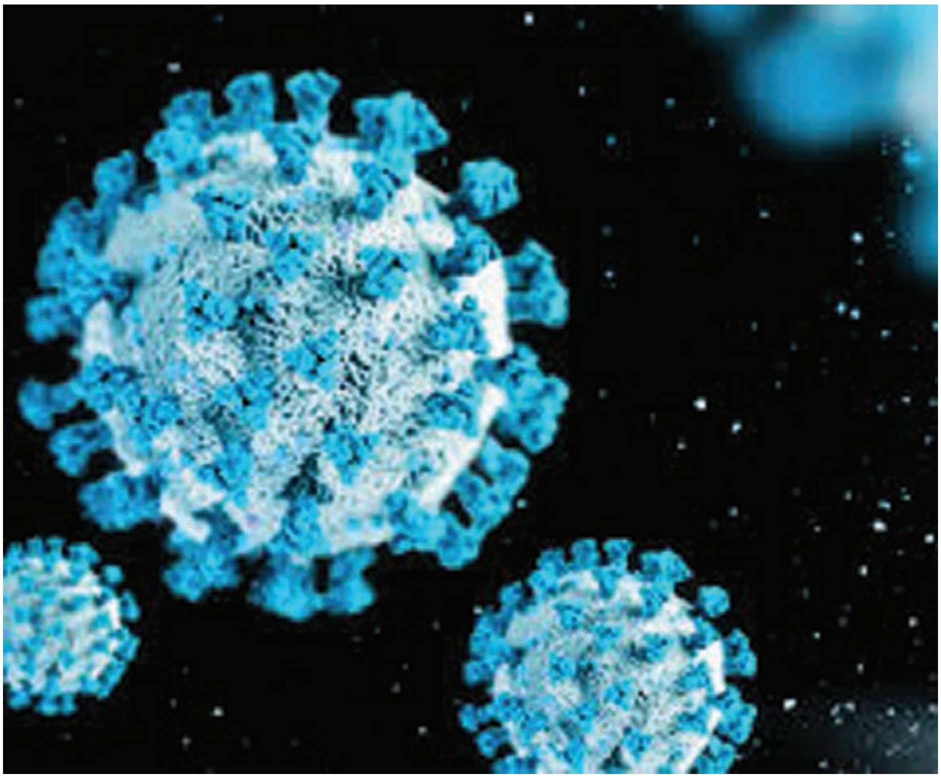

जलवायु परिवर्तन से संकट में नींद

जलवायु परिवर्तन से सिर्फ पर्यावरण में बदलाव ही नहीं आ रहे हैं, बल्कि मानव का सामान्य जीवन में भी परिवर्तन आना तय बताया जा रहा है। एक तरफ जहां जलवायु परिवर्तन से कृषि संकट बढ़ रहा है तो वहीं मानव शरीर में इसका असर देखा जाना है। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज का सामना दुनियाभर की आबादी कर रही है। इस वजह से बाढ़, तूफान के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी की वजह से असहनीय गर्मी मुख्य रही है। जलवायु परिवर्तन की ये चुनौतियां सिर्फ पर्यावरणीय ही नहीं है। इसका मानव जीवन पर व्यापक असर पड़ना तय माना जा रहा है। कुल जमा वैज्ञानिक मान रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से मानव को आर्थिक के साथ ही शारिरिक नुकसान होना तय है। जलवायु परिवर्तन की वजह से एक तरफ जहां फूड प्रोडक्ट यानी खाद्य पदार्थों के दामों में दोगुने तक की भी बढ़ोतरी होगी तो वहीं जलवायु परिवर्तन मानव की नींद का भी बड़ा दुश्मन बन सकता है। आइए समझते हैं कि पूरा मामला क्या है- 2035 तक दोगुने होंगे फूड प्रोडक्ट के दाम जलवायु परिवर्तन की वजह से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। इस वजह से कृषि संकट गहराया है और इस वजह से खाद्य पदार्थों के दामों में बढ़ोतरी हुई है। इस संबंध में यूरोपिय सेंट्रल बैंक के जलवायु परिवर्तन से दुनिया भर में बढ़ती महंगाई के आंकड़ों का विश्लेषण किया है। आंकड़ों के बाद बैंक ने अनुमान लगाया है कि 2035 यानी अभी से 10 साल बाद गर्म तापमान की वजह से मंहगाई में 0.5 से 1.2 फीसदी की दर से वार्षिक बढ़ोतरी होगी। जबकि खाद्य कीमतों के दामों में दोगुनी की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। जलवायु परिवर्तन की वजह से नींद का संकट जलवायु परिवर्तन की वजह से तापमान में बढ़ोतरी होती है, जो भोजन के बाद किसी मनुष्य के लिए आवश्यक नींद के लिए बड़ा संकट पैदा कर रही है। हालांकि हम तापमान को कम करने के लिए एयरकंडीशनर चला रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी रात में बढ़ता तापमान हमारी नींद में खलल डाल रहा है।

इसको लेकर चीन की फुडन यूनिवर्सिटी ने लोगों की नींद के डेटा का विश्लेषण किया है। यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने लोगों की नींद के 20 मिलियन से अधिक में रातों की निगरानी की। जिसमें पाया गया है कि अगर किसी रात तापमान में 10 डिग्री की बढ़ोतरी होती है, तो लोगों की भरपूर नींद ना लेने की संभावनाएं 20 फीसदी तक बढ़ जाती हैं। रिसर्चर ने अनुमान लगाया है कि तापमान में बढ़ोतरी के कारण इस सदी के अंत तक चीन में प्रत्येक व्यक्ति प्रति वर्ष लगभग 33 घंटे की नींद खो सकता है।

विजय गर्ग

डॉ. नीरज भारद्वाज
स्तंभकार

मीडिया बुलेट सिद्धांत और जनता

वर्तमान संचार क्रांति का युग है। यहां सभी कुछ शिक्षा, व्यापार, मनोरंजन आदि तरंगों पर तैर रहा है। पलक झपकते ही देश-दुनिया का नजारा बदलता नजर आता है। मोबाइल-लेपटॉप की तरह व्यक्ति को भी अपडेट रहना पड़ रहा है। आज देश-दुनिया की बातें सभी जानते हैं या जानना चाहते हैं। जिस प्रकार बुलेट अर्थात गोली बंदूक से बाहर निकलते ही लक्ष्य का भेदन करती है, ठीक उसी प्रकार बुलेट सिद्धांत के अनुसार संचार-माध्यमों से मिलने वाली जानकारी या संदेश श्रोताओं पर सीधा तथा शक्तिशाली प्रभाव छोड़ती है। इस सिद्धांत का मूल तत्व भी श्रोता को तीव्रगति से संदेश पहुंचाना है।

विचारक यह मानते हैं कि बुलेट सिद्धांत पाश्चात्य देशों से निकलकर आया, दूसरे शब्दों में कहें तो प्रथम विश्वयुद्ध के बाद यह सिद्धांत विकसित हुआ और सन 1940 तक प्रचलित रहा। कई बार तो यह सिद्धांत आज भी प्रासंगिक नजर आता है। इसका उद्भव अमेरिका और यूरोप में उस समय हुआ, जब समाज में तीव्रगति से परिवर्तन हो रहे थे। पारंपरिक समाज शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के रास्ते पर जा रहा था। समाज में आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक तौर पर असमानताएं बढ़ रही थी। और समाज का विघटन हो रहा था। लोगों में आपसी तालमेल और सहयोग नाममात्र का रह गया था। ऐसी स्थिति में मीडिया साधनों का महत्त्व बढ़ रहा था। और लोग एक दूसरे से ज्यादा मीडिया साधनों पर निर्भर रहने लगे थे।

वर्ष 1920 तक रेडियो संचार का एक सशक्त माध्यम बन चुका था। और हर घर तक अपनी आवाज पहुंचा रहा था। रेडियो लोगों के दिलों-दिमाग पर अपना असर डाल रहा था। साठ से सत्तर के दशक में टेलीविजन लोगों के मन मस्तिष्क पर छा गया। मीडिया के बढ़ते प्रभावों को देखते हुए विद्वानों ने मीडिया प्रभावों पर शोध आरंभ किए। समाज शास्त्री व जनता दोनों ही अब मानने लगे थे कि मीडिया एक ऐसा शक्तिशाली हथियार है, जिसके जरिए आम जनता के विचारों और व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। इन्ही सब धारणाओं ने मैजिक (जादुई) बुलेट थ्योरी को जन्म दिया, जिसके अनुसार मीडिया संदेश प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर सीधा और शक्तिशाली प्रभाव छोड़ता है।

पेयम फंड अध्ययन संस्था ने बुलेट सिद्धांत का समर्थन किया। इसमें शोध का एक विषय फिल्मों का भी बनाया गया, जिसमें फिल्मों से बच्चों के मानसपटल पर पड़ने वाले प्रभावों की पुष्टि की गई। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक हैडली कैंटरिल (अमेरिकी विद्वान) ने रेडियो नाटकों पर शोध अध्ययन किया। कैंटरिल प्रिंसटन रेडियो रिसर्च प्रोजेक्ट के सदस्य भी थे। मालूम हो कि कैंटरिल ने 1938 में हुए ऑरसन वेल्स के वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स रेडियो प्रसारण के समय हुई घबराहट का अध्ययन करके सामाजिक मनोविज्ञान और संचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कैंटरिल ने उन परिस्थितियों का अध्ययन किया, जिसमें लोगों ने रेडियो नाटक को वास्तविक समझा। इस शोध से संकेत मिला कि रेडियो के संदेश का प्रभाव बहुत शक्तिशाली जरूर था। लेकिन यह प्रभाव सभी श्रोताओं पर एक जैसा नहीं था। कैंटरिल ने अध्ययन किया कि श्रोताओं के व्यक्तित्व में असमानताओं के कारण श्रोताओं की मीडिया के प्रति प्रतिक्रियाएं भिन्न थी। इसलिए शोधकर्ता मानने लगे कि बुलटे सिद्धांत में खामियां हैं।

शोध और सर्वेक्षण से यह भी तथ्य प्रकाश में आए हैं कि न तो संचार-माध्यम सभी पर एक जैसे घातक प्रभाव छोड़ सकते हैं। और न ही सभी ग्राहक (लोग) मूक भाव के प्रेषित संदेश से समान रूप से प्रभावित होते हैं। संचार माध्यम व्यक्तियों की अलग-अलग सोच, विचार और जरूरतों को पूरा करते हैं, क्योंकि सभी व्यक्तियों के सोचने के तरीके में भिन्नता हैं। संचार-माध्यम भी श्रव्य, दृश्य और दृश्य-श्रव्य हैं। और इनके प्रभाव भी अलग-अलग हैं। एक बात अवश्य है कि किसी भी साधन के लाभ हैं, तो उनके दोष भी हैं। यह तो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह उसका उपयोग किस तरीके से करता है।

दवाओं की खुदरा कीमत तय

संकेत कौल

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 41 दवाओं की खुदरा कीमतें तय कर दी हैं। जिनमें डायबिटीज की बिना पेटेंट की दवा एम्पाग्लिफ्लोजिन के 18 प्रकार भी शामिल हैं। इन्हें जर्मन दवा कंपनी बोरिंजर इंगेलहेम ने विकसित किया है।

यह कदम 11 मार्च को एम्पाग्लिफ्लोजिन के पेटेंट की समाप्ति के बाद उठाया गया है। इसके बाद दवा कंपनियों के लिए इसके जेनेरिक संस्करण का बाजार खुल गया है। इन वेरिएंट्स के आने से दवा की कीमतों में 80 से 85 प्रतिशत की भारी गिरावट आई है। एनपीपीए ने पिछले महीने एम्पाग्लिफ्लोज़िन के 36 अन्य प्रकार और संयोजनों की खुदरा कीमतें तय की थीं।

नई सूची में एम्पाग्लिफ्लोजिन के साथ लिनाग्लिप्टिन, ग्लिमेपाइराइड, सिटाग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड से जुड़े एंटी-डायबिटिक कॉम्बिनेशन शामिल हैं, जिन्हें ब्लू क्रॉस लैबोरेटरीज, टॉरंट फार्मा, कैडिला, ग्लेनमार्क और एल्केम लैबोरेटरीज जैसी दवा कंपनियां बनाती और बेचती हैं।

इसमें क्लिंडामाइसिन और निकोटिनामाइड जेल का कॉम्बिनेशन भी शामिल है, जिसका उपयोग मुंहासों के इलाज के लिए किया जाता है। साथ ही इसमें आयरन और फोलिक एसिड वाली मल्टीविटामिन टैबलेट तथा सायनोकोबालामिन सिरप शामिल हैं।

प्राधिकरण औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ) के तहत फार्मास्यूटिकल उत्पादों की कीमतों को कायदे में रखता है। कीमतों में संशोधन को एनपीपीए की 133वीं बैठक के दौरान मंजूरी दी गई, जो 29 मई को आयोजित की गई थी।

दूसरा मत

हार्दिक शुभकामनाएं

पढ़ें और पढ़ाएं दूसरा मत

एक शुभचिंतक, दिल्ली

छुट्टी को यादगार बनाएं

विजय गर्ग
वरिष्ठ स्तंभकार

छुट्टी को यादगार बनाने के तरीके में शिक्षकों और अभिभावकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों को छुट्टियों से बहुत प्यार है। जैसे ही उनकी घोषणा की जाती है, उनके चेहरे खुशी से झूम उठते हैं। यह स्कूल की दैनिक हलचल से स्वतंत्रता प्राप्त करने का एक सुनहरा समय है, सुबह जल्दी उठने के लिए नहीं, पसंदीदा खेल खेलने के लिए, यात्रा करने और परिवार के साथ लंबा समय बिताने के लिए। छुट्टियों के दौरान, बच्चों को ऐसा काम दिया जाना चाहिए जो उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है और उनकी प्रगति और विकास से संबंधित है। छुट्टी के काम का उद्देश्य केवल पाठ्यक्रम का अभ्यास करने तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि बच्चों के मन, मस्तिष्क, शरीर और चरित्र को भी पूरी तरह से विकसित करना चाहिए। दूसरे, अगर हम इस बार को बच्चों के कौशल को निखारने का एक विशेष अवसर कहते हैं, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। बच्चे इस समय का अच्छा उपयोग करके अपने ज्ञान में मूल्यवान परिवर्धन कर सकते हैं।

होमवर्क पूरा करना

पहली बात जो बच्चों को करनी है, वह होमवर्क को करना है। जो बच्चे अपने लक्ष्य के पीछे हैं, वे कड़ी मेहनत कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। स्कूल के माध्यम से बच्चों को विशेष अवकाश गृहकार्य उपलब्ध कराया गया है। यह काम बहुत दिलचस्प और ज्ञान बढ़ाने वाला है। इस काम पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। वैसे भी पढ़ाई में नई ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। बच्चे छुट्टी के अवसर का लाभ उठा सकते हैं और पाठ-सहायता गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं।

जीवन कौशल प्रशिक्षण

शिक्षा केवल पुस्तकों तक ही सीमित नहीं है। बच्चों को घर के काम, खाना बनाना, बजट बनाना, चीजों का ख्याल रखना आदि सीखने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। बच्चों को सिखाया जाना चाहिए कि दैनिक कार्यों की सूची कैसे बनाई जाए, खरीदारी की सूची बनाएं और खर्चों का अनुमान लगाएं, सरल व्यंजनों को बनाने की कोशिश करें, आदि। उन्हें बताया जाना चाहिए कि अपने कमरे को कैसे साफ रखें, सब कुछ अपनी जगह पर रखें, आदि। इस तरह के कार्य बच्चों में आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी की भावना पैदा करते हैं।

सुंदर लेखन

विद्वानों का कहना है कि अगर लेखन सुंदर है, तो अध्ययन करना आसान हो जाता है। छुट्टियों के दौरान, बच्चों को अपने लेखन को सुंदर बनाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस काम के लिए हस्तलिखित प्रतियों का उपयोग किया जा सकता है। प्रत्येक अक्षर की संरचना को गहराई से समझा जा सकता है। सुंदर लेखन के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। परीक्षाओं में सुंदर लेखन बहुत महत्वपूर्ण है। इससे छात्रों को अपने पेपर में बहुत अच्छे अंक मिल सकते हैं क्योंकि जब शिक्षक पेपर चेक करता है तो उन्हें पेपर चेक करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इससे छात्रों को पेपर में बहुत अच्छे अंक मिलते हैं।

ड्राइंग और पेंटिंग का काम

बच्चों के हितों के अनुसार अवकाश का काम किया जाना चाहिए। छुट्टियों के दौरान ड्राइंग और पेंटिंग भी की जा सकती है। एक बच्चा जो ड्राइंग में अच्छा है, वह अपनी पढ़ाई में अधिक प्रगति कर सकता है। जबकि यह एक बहुत ही दिलचस्प विषय है, यह ज्ञान को भी बढ़ाता है। यह काम बच्चों की कल्पना को बढ़ाता है और उनकी आंतरिक क्षमताओं को विक-सित करता है। यदि संभव हो, तो बच्चों को पेंटिंग में छुट्टियों के दौरान कोचिंग दी जानी चाहिए ताकि बच्चों के कौशल में सुधार हो सके।

खेलकूद और योग में भाग लेना

छुट्टियों के दौरान बच्चों को अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए खेलों में भाग लेना चाहिए। खुले मैदान में खेले जाने वाले आउटडोर खेलों में भाग लेना चाहिए। इसके अलावा इनडोर खेलों में भी भाग लिया जा सकता है। खेलों से बच्चे में सहयोग, सहजता, बड़ों के प्रति सम्मान और

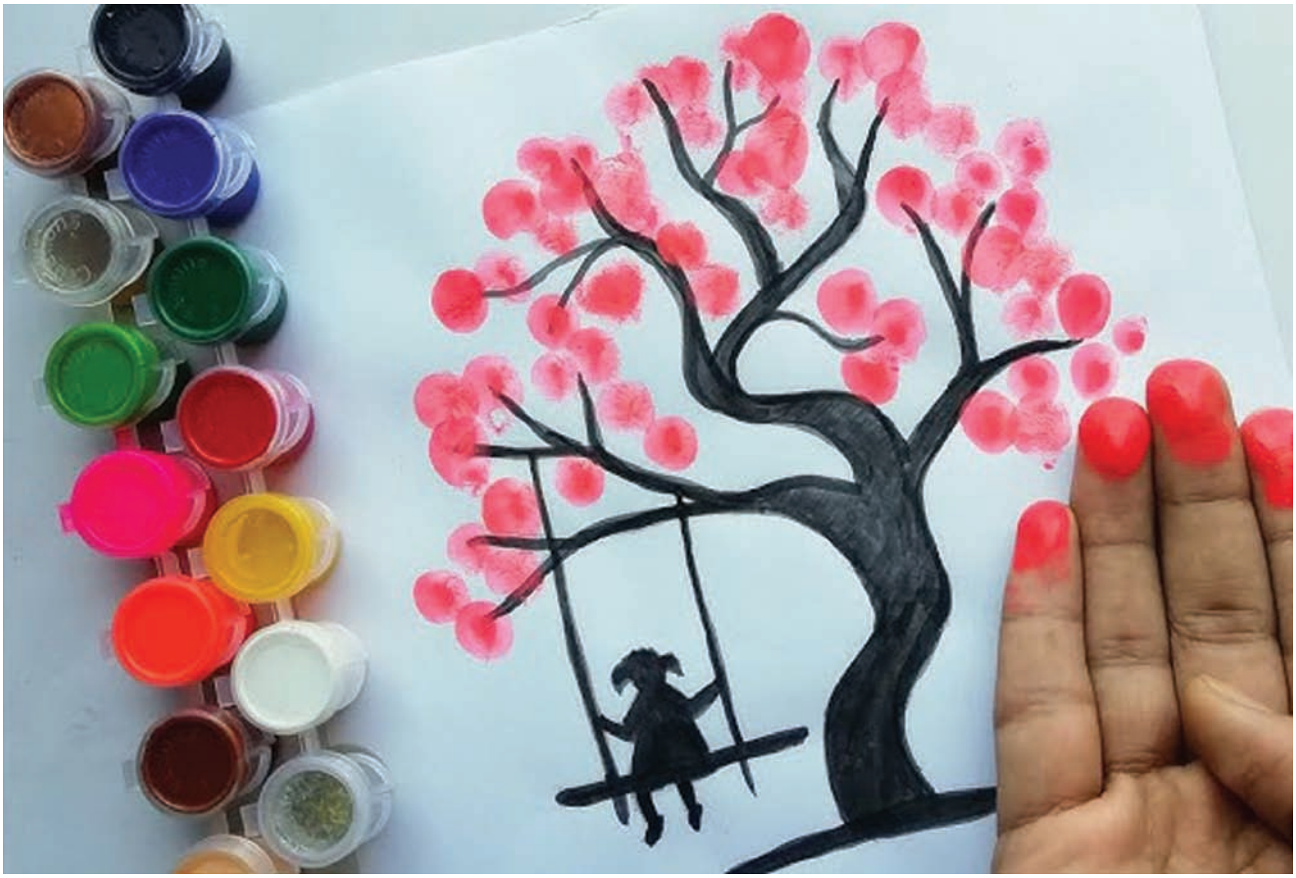

अनुशासन की भावना विकसित होती है। इसके अलावा छुट्टियों के दौरान छोटे बच्चों को कबड्डी, लुका-छिपी, बरहन-डीटी, कोटला-छपकी आदि खेलों में भी भाग लेना चाहिए। इनसे बच्चों में धैर्य, शक्ति और टीम वर्क के गुण बढ़ते हैं। छुट्टियों के दौरान बच्चों को किसी उपयुक्त शिविर में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे बच्चों के चरित्र में सुधार हो सके और इससे छात्रों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है।

तकनीकी युग से संबंधित कार्य आज के दौर में तकनीक का बहुत महत्व है। शर्त यह है कि इसे बर्बाद न किया जाए। बच्चों को ऑडियो-वीडियो प्रोजेक्ट बनाने के बारे में बताया जाना चाहिए। रील या वीडियो के माध्यम से शैक्षणिक सामग्री का निर्माण और उसके अध्ययन को गहराई से समझाया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में वे तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर सफलता प्राप्त कर सकें। आज के समय में बच्चों को कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है, इसलिए छुट्टियों में बच्चों को कंप्यूटर की कोचिंग भी देनी चाहिए, ताकि छुट्टियों में बच्चे कंप्यूटर में एक्सपर्ट बन सकें।

पर्यावरण संरक्षण

छुट्टियों के दिनों में बच्चे पर्यावरण की देखभाल के लिए आगे आ सकते हैं। वास्तव में पर्यावरण को खुशनुमा बनाना हम सबका कर्तव्य है। हम गांव के आम स्थानों, स्कूलों और अपने घर के बगीचों की सुरक्षा करके और नए पौधे लगाकर इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। बच्चों को पौधों की देखभाल के लिए प्रेरित करने की जरूरत है ताकि उन्हें पर्यावरण के बारे में जानकारी मिल सके।

प्रतिदिन टहलना और व्यायाम करना

रोजाना सैर और व्यायाम भी छुट्टियों का हिस्सा होना चाहिए। हल्का-फुल्का व्यायाम और सैर करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। रोजाना सैर करने से कई बीमारियाँ दूर होती हैं। इसलिए सुबह की सैर और व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए।

खिलौने बनाना

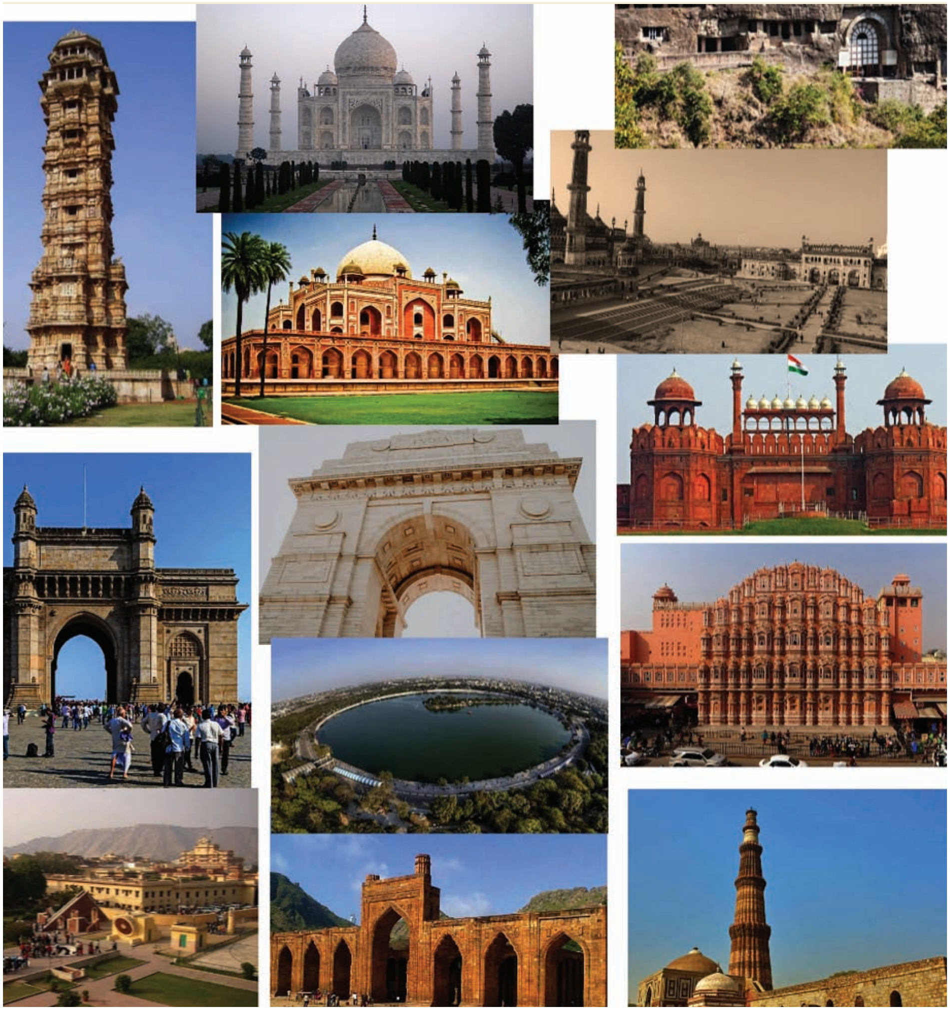

बच्चे पुरानी और इस्तेमाल की हुई चीजों से खिलौने बना सकते हैं। यह गतिविधि रोचक और सार्थक दोनों है। यह बच्चों को अपनी प्रतिभा को विकसित करने का सुनहरा अवसर देता है।

साहित्यिक पुस्तकों का अध्ययन

छुट्टियों के दौरान लाइब्रेरी की किताबें पढ़नी चाहिए। कहानियाँ, आत्मकथाएँ, ऐतिहासिक किताबें या धार्मिक ग्रंथ बच्चों की सोच को व्यापक बनाते हैं। इसके अलावा अच्छी और ज्ञानवर्धक किताबें हमारे घर की लाइब्रेरी का हिस्सा होनी चाहिए। अच्छा साहित्य पढ़ने से न केवल हमारा ज्ञान बढ़ता है बल्कि हमारा शब्द भंडार भी बढ़ता है। हमें उन्हें महान विद्वानों, वैज्ञानिकों और गणितज्ञों की किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि उनमें वैज्ञानिक सोच विकसित हो सके।

पर्यटन

कान और आंखों के बीच सिर्फ चार अंगुल का फासला नहीं होता। यह अंतर बहुत बड़ा है। किसी भी चीज के बारे में पढ़ने से ज्यादा जानकारी आपको उसे देखकर मिलती है। अगर आप ताजमहल के बारे में विस्तार से लिखना चाहते हैं, तो उसे अपनी आँखों से देखना बहुत जरूरी है। इसलिए बच्चों के लिए सैद्धांतिक ज्ञान ही काफी नहीं है, उन्हें ऐतिहासिक जगहों पर जाना चाहिए, जिससे उन्हें व्यावहारिक जानकारी मिले।

माता-पिता की मदद करना

बच्चों को छुट्टियों के दौरान घर और बाहर के कामों में अपने माता-पिता की मदद भी करनी चाहिए। इससे बड़ों के प्रति सम्मान बढ़ता है। वहीं दूसरी ओर काम करने की इच्छा और जिम्मेदारी का अहसास भी बढ़ता है।

सामाजिक रूप से जिम्मेदार कार्य

बच्चों को सामाजिक भावना से जुड़ने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। कम क्षमता वाले बच्चों को उपचारात्मक कक्षाएं लगाकर शिक्षित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यदि संभव हो तो उनके घर जाकर उन्हें शिक्षित करना बहुत ही ईमानदारी का काम होगा। इसके अलावा पानी बचाने के लिए पोस्टर बनाना, पक्षियों के लिए पानी के बर्तन रखना, पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ लगाना आदि छुट्टियों के दौरान किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल किए जाने चाहिए।

छुट्टियों में किए जाने वाले काम बच्चों को न केवल पढ़ाई में बल्कि जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करते हैं, जो उन्हें रचनात्मक, सीखने योग्य और जीवन कौशल से परिपूर्ण बनाते हैं। बच्चों को हर दिन कुछ नया सीखने, सोचने और करने के लिए उत्साहित होना चाहिए। इसलिए गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग करते हुए बच्चों को अपनी कला और प्रतिभा को निखारने का अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। आज के समय के संदर्भ में इन नेक कामों की अधिक आवश्यकता है।

(लेखक सेवानिवृत्त प्रिंसिपल एवं शैक्षिक स्तंभकार हैं।)

अशोक गुप्त
स्तंभकार

दया का सार्वजनिक प्रदर्शन

हमारा समाज दया भावी लोगों से भरा पड़ा है। हमें इंसानों पर दया आए न आए पर कीड़े मकोड़े व पशु पक्षियों पर हम इस कदर दया बरसाते हैं कि उनकी सेहत की भी परवाह नहीं करते। एक वक्त था जब दया भाव के चलते गाय और कुत्ते के लिए रोटी या रोटी का टुकड़ा निकाल कर रखा जाता था। खाना शुरू करने से पहले अपनी पहली रोटी या उसका कुछ भाग गाय या कुत्ते के लिए रख लिया जाता था। तब गाय और कुत्ते शाम होते ही घरों के बाहर खड़े हो जाते थे, और लोग वह रोटी डाल देते थे जिसे खा कर वे अगले घर के लिए चल पड़ते थे। धीरे-धीरे यह प्रसाद समाप्त होती गई। शहरों में गाय आदि पालने पर प्रतिबंध लग गए। और कुत्तों की रोटी भी भुला दी गई।

सतत बढ़ती महंगाई के चलते फिर भी कुछ लोग कुत्तों को कुछ न कुछ खिलाते नजर आते रहते हैं। कुछ कुत्ते प्रेमी कुत्तों को बिस्किट खिलाते देखे जाते हैं। और कुछ कुत्तों को दूध भी पिलाते दिखते हैं। फिर शहरों में बंदरों का आगमन प्रारंभ हुआ, तो कुछ लोगों ने उन्हें केले खिलाने शुरू कर दिए। नतीजतन उन्हें शहरों का चस्का पड़ गया और धीरे-धीरे में खुद ही दिल फ्रिज खोलकर जो मिला, उसे खाने लगे। लोग सावधान हुए तो कुछ बंदर तो छीन कर भी खाने लग। वृंदावन के बंदर तो लोगों की ऐनक

या पर्स खींच कर ब्लैकमेल करने के आदी हो चुके हैं, लेकिन इंसान है कि वह अपने दया भाव के हाथों मजबूर है।

सुबह सैर के लिए पार्क जाता हूं। गेट के दोनों ओर मुंडेर पर कुछ लोग रात का बचा खुचा खाना, भोजन, सूखी ब्रेड व चावल आदि रख जाते हैं। उन्हें लगता है कि पक्षी, गिलहरी आदि खाकर उन्हें दुआ देंगे। ऐसे ही कुछ सेवाभावी चीटियों के लिए आटा चीनी भी डाल आते हैं। शायद उन्हें भगवान या प्रकृति की व्यवस्था में विश्वास नहीं है।

अब दिल्ली में सड़क किनारे और मुख्य चुनाव के आसपास और आवारा जानवरों को चारा आदि डालने वालों पर एमसीडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ऐसी सभी जगह से दाना बेचने वाले वालों को हटा दिया गया है। और नियमों का उल्लंघन करने पर चालान करना प्रारंभ कर दिया गया है। एमसीडी के अनुसार, जहां दाना डाला जाता है, वहां जानवरों की संख्या भी बढ़ जाती है। आवारा जानवरों को चारा डालने से जानवर चारा खाकर वही गोबर करते हैं। और गंदगी के साथ ट्रैफिक में भी बाधा पैदा करते हैं। कबूतरों की बीट के बारे में कहा जा रहा है कि बीट हवा में उड़ने से सांस संबंधी कई गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। बेहतर यही होगा कि अपना दया भाव सार्वजनिक स्थलों पर न दिखाएं। जो रखना हो , अपने घर की मुंडेर पर रखें।

राजनीतिक राय में बड़े अंतर का दिख रहा ट्रेंड

दीप्ति अंगरीश

स्तंभकार

राजनीति में अब केवल पीढ़ियों के बीच का फर्क नहीं, बल्कि जेनरेशन-जेड के भीतर भी बड़ा वैचारिक अंतर सामने आ रहा है। खासकर लड़के और लड़कियों के बीच राजनीतिक सोच में बड़ा अंतर देखा जा रहा है, जो न सिर्फ लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं बल्कि समाज की दिशा को भी प्रभावित कर रहा है।

1995 के बाद जन्मे युवाओं को जेन-जी माना जाता है। हाल के चुनावों में देखा गया है कि इस पीढ़ी के युवाओं की राजनीतिक सोच में

तीव्र लैंगिक विभाजन उभर रहा है। जहां लड़कों का झुकाव दक्षिणपंथी विचारधाराओं की ओर है, वहीं लड़कियां अधिकतर वामपंथी सोच का समर्थन कर रही हैं। यह ट्रेंड केवल भारत में ही नहीं, बल्कि अमेरिका, यूरोप और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में भी देखा जा रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि युवा पुरुष खुद को सामाजिक-आर्थिक रूप से हाशिए पर महसूस करते हैं और विविधता की नीतियों को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। इसके उलट, युवा महिलाएं समानता के बढ़ते अवसरों को प्रगति के रूप में देखती हैं और लैंगिक बराबरी के सवालों को प्रमुख मानती हैं।

भारत में यह अंतर अभी पश्चिमी देशों जितना गहरा नहीं है। 'द हिंदू' में छपे सीएसडीएस-लोकनीति के 2024 पोस्ट-पोल सर्वे के अनुसार, 37% पुरुषों और 36% महिलाओं ने भाजपा को वोट दिया, जबकि कांग्रेस को 22% महिलाओं और 21% पुरुषों ने समर्थन दिया। यह आंकड़े दिखाते हैं कि भारत में अभी लैंगिक ध्रुवीकरण सीमित है, लेकिन भविष्य में इसमें बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं।

2016 के एक सर्वेक्षण के अनुसार, शहरी युवा पुरुषों में 81% राजनीति में रुचि रखते हैं, जबकि महिलाओं में यह संख्या केवल 46% है। शिक्षा स्तर बढ़ने के साथ यह अंतर और गहराता है। अधिक शिक्षित महिलाओं में राजनीतिक मुद्दों पर 'कोई राय नहीं' रखने की प्रवृत्ति देखी गई।

24 वर्षीय राहुल (बदला हुआ नाम), बीएचयू से पोस्टग्रेजुएट हैं। उनका कहना है कि वे बीजेपी को अंतरराष्ट्रीय मंच पर मजबूत मानते हैं और इसलिए समर्थन करते हैं। दूसरी ओर, 25 वर्षीय भूमि (बदला हुआ नाम), जेएनयू की छात्रा होते हुए भी दक्षिणपंथी सोच की समर्थक हैं। उनका मानना है कि वामपंथ केवल 'बराबरी की बातें' करता है, पर जमीन पर प्रभाव नहीं दिखता।

वहीं, रीती (बदला हुआ नाम), जो वामपंथी सोच से जुड़ी हैं, कहती हैं कि वे जाति और धर्म आधारित राजनीति से दूरी बनाकर नीति आधारित मतदान करती हैं।

दक्षिण कोरिया के आगामी चुनावों में भी ऐसा ही परिदृश्य देखने को मिल रहा है, जहां युवा महिलाएं रूढ़िवादी पार्टियों के खिलाफ मतदान की तैयारी में हैं। कोविड से पहले तक दोनों ही वर्ग प्रगतिशील पार्टियों को समर्थन करते थे, पर अब युवा पुरुष दक्षिणपंथ की ओर बढ़ रहे हैं। ली जियोंग-मिन जैसे युवा पहली बार वोट दे रहे हैं और उन्होंने दक्षिणपंथी रिफॉर्म पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन देने की घोषणा की है।

दुनिया भर में जेन-जी की राजनीतिक सोच में लैंगिक अंतर तेजी से उभर रहा है। यह न केवल भविष्य की लोकतांत्रिक राजनीति को आकार देगा, बल्कि नीति-निर्माण, रोजगार और सामाजिक संरचना को भी प्रभावित करेगा। भारत में इस बदलाव की गति धीमी है, लेकिन चेतावनी स्पष्ट है–राजनीति अब केवल विचारधाराओं का नहीं, बल्कि लिंग के नजरिए का भी युद्ध बनती जा रही है।

2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप ने निर्माण क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और विविधता कार्यक्रमों पर निशाना साधते हुए खासतौर पर युवा श्वेत और हिस्पानियाई पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करने की रणनीति अपनाई। इस रणनीति का परिणाम यह हुआ कि युवा महिलाओं से उनकी दूरी और बढ़ गई, जिससे पहले से मौजूद लिंग आधारित राजनीतिक खाई और गहरी हो गई।

आंकड़ों की मानें तो 18 से 29 वर्ष के लगभग 50 फीसदी पुरुषों ने ट्रंप को वोट दिया, जबकि 61 फीसदी युवा महिलाओं ने उनकी प्रतिद्वंद्वी, कमला हैरिस को समर्थन दिया। खास बात यह रही कि युवा ब्लैक मतदाताओं–चाहे पुरुष हों या महिलाएं–ने बड़े पैमाने पर कमला हैरिस का समर्थन किया।

इस महीने ऑस्ट्रेलिया में हुए चुनावों में जेन-जी के बीच ऐसा लिंग आधारित विभाजन सामने नहीं आया। वहां चुनावों में किसी बड़े मतभेद का संकेत नहीं मिला। विशेषज्ञों के अनुसार, इसका एक अहम कारण ऑस्ट्रेलिया में अनिवार्य मतदान प्रणाली हो सकती है।

ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के राजनीतिक विश्लेषक इंतिफार चौधरी का मानना है कि 'अनिवार्य मतदान अक्सर चरमपंथी विचारों और ध्रुवीकरण को नियंत्रित कर देता है।' इस कारण सभी वर्गों के मतदाताओं की सहभागिता होती है और कोई एक पक्ष बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं बन पाता।

राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो यदि सरकारें युवा पीढ़ी की मूल समस्याओं–जैसे घरों की बढ़ती कीमतें, अस्थिर नौकरियों और युवा पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों–को गंभीरता से नहीं लेतीं, तो यह लिंग आधारित राजनीतिक संघर्ष और लंबा खिंच सकता है।

विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि युवा पुरुषों में बढ़ती आत्महत्या की दर अब एक गंभीर नीति संकट बन चुकी है। अगर इस ओर तत्काल ध्यान नहीं दिया गया तो यह केवल राजनीति में नहीं, बल्कि समाज के ताने-बाने में भी दरारें डाल सकता है।

जेन-जी के बीच राजनीतिक सोच का यह लैंगिक विभाजन अब केवल विचारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह चुनावी फैसलों, सामाजिक दृष्टिकोण और नीति निर्धारण को भी प्रभावित कर रहा है। जहां एक ओर युवा महिलाएं समानता और समावेशिता की ओर झुकाव रखती हैं, वहीं कई युवा पुरुष खुद को हाशिए पर महसूस करते हुए परंपरागत और प्रतिरोधी राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं। अगर यह रुझान यूं ही जारी रहा, तो यह निश्चित रूप से भविष्य की राजनीति का चेहरा बदल सकता है।

डॉ. साधना झा की दो कविताएं

सागर और मन

सागर में
उफनती लहरें
और
मन में
भाव !
व्याकुल मन
अशांत सागर !

मन मांगता चैन
लौटा दो प्यार !

सागर बांटता स्नेह
कहता लुटा दो प्यार !!

समय की धारा

जीवन हर पल
बदलता है
यूं ही समय की
धारा में
हम बहते हैं !

कभी-कभार
जीवन तटबंध पर
जो अपने मिलते हैं
कुछ लम्हें पलकों में
सो जाते हैं
और कुछ में हम
सौ बरस जी लेते हैं !!

कोलकाता

दूसरा मत

हार्दिक शुभकामनाएं

पढ़ें और पढ़ाएं दूसरा मत

एक शुभचिंतक, दिल्ली

अब माइक्रो फिल्में बनेंगी क्या?

राजेश कुमार सिन्हा
वरिष्ठ स्तंभकार

हमारे देश में सिनेमा की शुरूआत मूक फिल्मों से हुई थी। और फिर धीरे धीरे तकनीकी विकास इनोवेशन और क्रिएटिविटी के सहारे आज डिजिटल और अब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म तक का सफर तय कर चुका है। बेशक,हर चरण ने कहानी कहने के तरीके और दर्शकों के अनुभव को नया आकार दिया है। इस निरंतर विकसित होते परिदृश्य में, इन दिनों एक नया और रोमांचक विचार उभर रहा जिसे माइक्रो फिल्म का नाम दिया गया है। यह अवधारणा न केवल फिल्म निर्माण की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देती है, बल्कि भविष्य के मनोरंजन और सूचना वितरण के लिए एक नया मार्ग भी खोलती है। क्या माइक्रो फिल्में वास्तव में सिनेमा का अगला बड़ा कदम हैं, या यह केवल एक दौर है? जो कुछ दिनों में भुला दिया जाएगा। दरअसल माइक्रो फिल्म, अपने सबसे बुनियादी अर्थ में, बेहद कम अवधि की फिल्म होती है। जबकि 'लघु फिल्म' की अपनी एक तय शुदा श्रेणी है जो आमतौर पर 1 मिनट से लेकर 40-50 मिनट तक की हो सकती है, माइक्रो फिल्म इस अवधि को और भी छोटा कर देती है। इसका अर्थ है कि एक माइक्रो फिल्म कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनटों तक की हो सकती है, जिसमें आमतौर पर 3-5 मिनट की अवधि को ऊपरी सीमा माना जाता है। थोड़े में कहा जाए तो यह लघुता ही माइक्रो फिल्मों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इस नए तरीके की लघुता का निहित अर्थ वाकई गहरा है। यह फिल्म निमार्ताओं को न्यूनतम संसाधनों के साथ अधिकतम प्रभाव प्राप्त करने के लिए विवश करता है। हर शॉट, हर संवाद, हर दृश्य को अत्यंत सावधानी से नियोजित करना होता है ताकि एक पूरी कहानी, एक भावना, या एक विचार को इतनी कम अवधि में प्रभावी ढंग से सामने लाया जा सके। यह सिर्फ एक ट्रेलर या टीजर नहीं है; यह अपने आप में एक संपूर्ण कथा अनुभव है।

सच कहा जाए तो माइक्रो फिल्मों का उदय कई तकनीकी और सामाजिक कारकों का परिणाम है जिनमें से एक है स्मार्टफोन और डिजिटल कैमरा की उपलब्धता। आज लगभग हर किसी के पास एक अच्छी क्वालिटी के कैमरा वाला स्मार्टफोन है। यह तकनीकी उपलब्धता बड़ी सहजता से फिल्म निर्माण का मार्ग प्रशस्त करती है। अब फिल्म बनाने के लिए महंगे उपकरणों या बड़े क्रू की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने फोन पर एक माइक्रो फिल्म शूट कर सकता है, उसे संपादित कर सकता है और दुनिया के साथ साझा कर सकता है। इसी क्रम में सोशल मीडिया और शॉर्ट-फॉर्म कंटेंट के बढ़ते प्रभाव को भी रखा जा सकता है। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉट्‌र्स जैसे प्लेटफॉर्म ने छोटी अवधि के वीडियो कंटेंट की खपत को आज एक ऐसे स्तर पर पहुंचा दिया है, जिसकी कल तक कल्पना भी नहीं की जा

सकती थी। आज का दर्शक कम समय में जानकारी और मनोरंजन प्राप्त करने के आदी हो गया है। माइक्रो फिल्में इस ट्रेंड के साथ पूरी तरह से फिट बैठती हैं, क्योंकि वे तुरंत इस्तेमाल के लिए डिजाइन ही की गई हैं। इसका एक और महत्त्वपूर्ण कारण है।

बढ़ता 'ध्यान अवधि संकट' अर्थात किसी चीज विशेष को लंबे समय तक नहीं देख पाना। आज डिजिटल युग में, लोगों की ध्यान अवधि सिकुड़ती जा रही है। लंबी फिल्मों या बड़ी डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए धैर्य कम होता जा रहा है। ऐसे में माइक्रो फिल्में इस समस्या का समाधान करती हैं, क्योंकि वे कम समय में प्रभाव डाल सकती हैं, जिससे दर्शकों को बांधे रखना आसान होता है। फिल्म निर्माण से जुड़े लोगों का मानना है कि कम लागत और दशकों तक आसान पहुंच भी माइक्रो फिल्म की अवधारणा को समर्थन करती हुई नजर आती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पारंपरिक फिल्म निर्माण बेहद महंगा और समय लेने वाला होता है। माइक्रो फिल्में इस बाधा को तोड़ती हैं। इन्हें कम बजट में, कम समय में बनाया जा सकता है, जिससे नए और उभरते फिल्म निमार्ताओं के लिए उद्योग में प्रवेश करना आसान हो जाता है। आज फिल्मों खास कर हिंदी फिल्मों में कहानी का जो हाल है उसकी तुलना में यहां नई सोच की कहानी को कहने का अवसर ज्यादा मिलता है अतः फिल्म निमार्ताओं को नए और अपरंपरागत तरीकों से कहानी कहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। शायद यह भी एक वजह है कि आज किस्सागोई की नई शैली परवान चढ़ने को बेताब नजर आती है। वैसे देखा जाए तो माइक्रो फिल्मों की क्षमता केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है बल्कि उनके कई अन्य प्रयोग भी हो सकते हैं जेसे,कई फिल्म निमार्ता माइक्रो फिल्मों को कलात्मक प्रयोग और अभिव्यक्ति के लिए एक मंच के रूप में उपयोग कर सकते हैं। वे एक विचार, एक भावना, या एक अवधारणा को संक्षेप में और शक्तिशाली ढंग से व्यक्त करने के लिए एक अद्वितीय माध्यम प्रदान करते हैं। कंपनियां अपने उत्पादों या सेवाओं का विज्ञापन करने के लिए माइक्रो फिल्मों का उपयोग कर सकती हैं। एक छोटी, आकर्षक कहानी दर्शकों को उत्पाद के साथ भावनात्मक रूप से जोड़ने में मदद कर सकती है, जो पारंपरिक विज्ञापनों से अधिक प्रभावी हो सकती है।जटिल अवधारणाओं या सूचना को संक्षिप्त और आकर्षक तरीके से समझाने के लिए माइक्रो फिल्मों का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, विज्ञान, इतिहास या सामाजिक मुद्दों पर 2-3

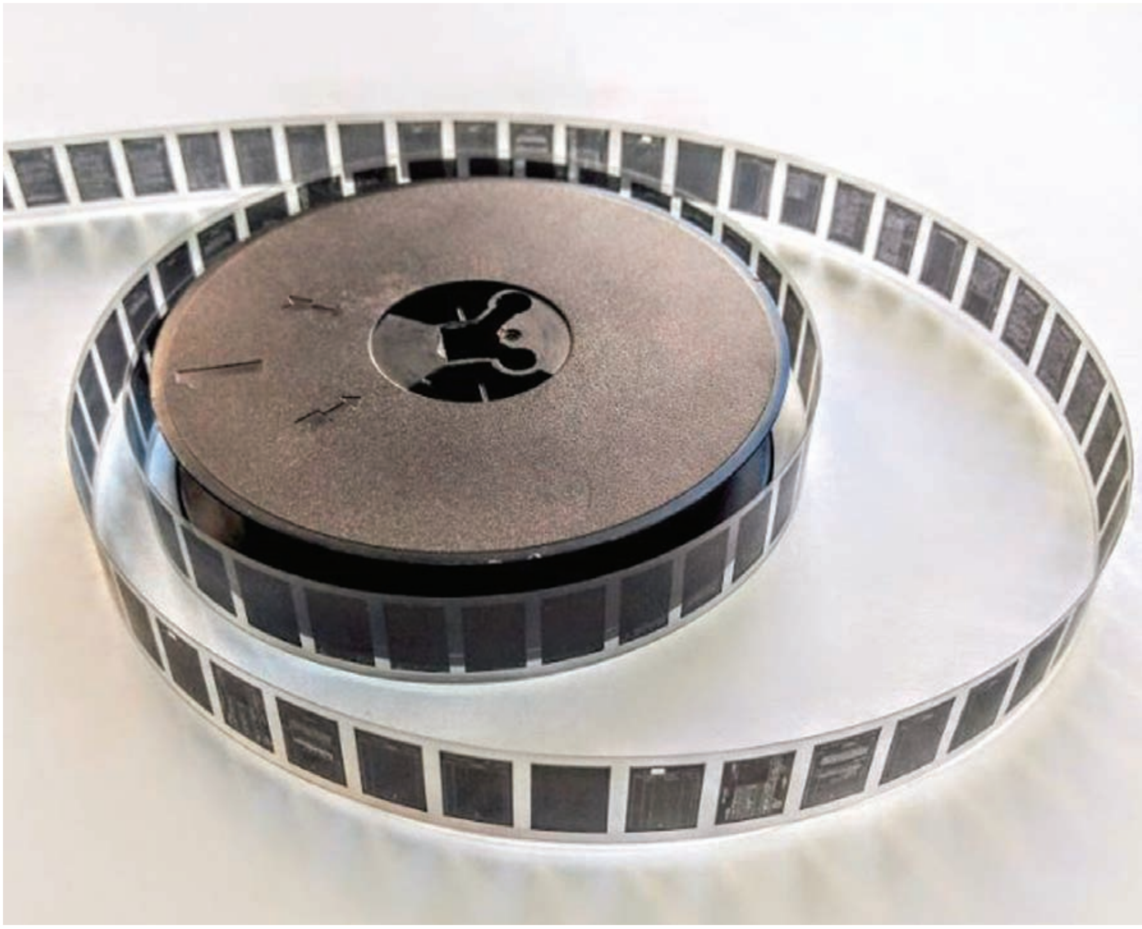

मिनट की एनिमेटेड माइक्रो फिल्म छात्रों या आम जनता के लिए अधिक सुलभ हो सकती है।सामाजिक मुद्दों जैसे पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य जागरूकता या मानवाधिकारों पर संदेश फैलाने के लिए माइक्रो फिल्में एक शक्तिशाली उपकरण हो सकती हैं। एक छोटी, भावनात्मक कहानी दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर सकती है और कार्रवाई के लिए प्रेरित कर सकती है। ब्रेकिंग न्यूज या महत्वपूर्ण घटनाओं के त्वरित सारांश के लिए माइक्रो फिल्मों का उपयोग किया जा सकता है। यह विशेष रूप से युवा पीढ़ी के लिए उपयोगी हो सकता है जो त्वरित अपडेट पसंद करते हैं।नए फिल्म निमार्ता, निर्देशक, लेखक और अभिनेता अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए माइक्रो फिल्मों का उपयोग कर सकते हैं। यह उन्हें बड़े प्रोजेक्ट्स में ब्रेक पाने में मदद कर सकता है।हालांकि माइक्रो फिल्मों में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन उनके साथ कुछ चुनौतियाँ और सीमाएँ भी जुड़ी हुई हैं, जिन्हें इस क्रम में रखा जा सकता है।

कथा विकास की चुनौतीः

इतनी कम अवधि में एक अच्छी तरह से विकसित कहानी बनाना एक बड़ी चुनौती है। चरित्र विकास, प्लॉट ट्विस्ट और भावनात्मक एंगल को प्रभावी ढंग से बुनना या दिखाना मुश्किल हो सकता है।

प्रोफेशनल नजरिया :

वर्तमान में, माइक्रो फिल्मों के लिए एक स्पष्ट राजस्व मॉडल स्थापित करना मुश्किल है। विज्ञापन, स्पॉन्सर या प्लेटफॉर्म सदस्यता के माध्यम से आय उत्पन्न करना एक चुनौती है।

कलात्मक क्वालिटी बनाम वायरल क्षमताः

कई माइक्रो फिल्में ₹वायरल₹ होने के उद्देश्य से बनाई जाती हैं, जिस्‍ाका अर्थ है कि कलात्मक क्वालिटी कभी-कभी पीछे छूट सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि माइक्रो फिल्में केवल क्लिक के लिए न हों, बल्कि वास्तविक कलात्मक मूल्य भी प्रदान करें।

उद्योग की स्वीकृतिः

मुख्यधारा फिल्म उद्योग अभी भी लंबी फिल्मों और पारंपरिक प्रारूपों पर केंद्रित है। माइक्रो फिल्मों को एक वैध कला रूप और व्यावसायिक उद्यम के रूप में स्वीकार करने में समय लग सकता है।

कॉपीराइट और चोरी का जोखिमः छोटे वीडियो कंटेंट के तेजी से प्रसार के साथ, कॉपीराइट उल्लंघन और सामग्री की चोरी का जोखिम बढ़ जाता है। अगर हम अपने आस पास के देशों पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि माइक्रो फिल्मों की अवधारणा विश्व स्तर पर अपनी पकड़ बना रही है, हालांकि विभिन्न देशों में इसके विकास और स्वीकृति का स्तर अलग-अलग है। चीन में टिकटॉक (जिसे वहां डौयिन के नाम से जाना जाता है) और कुएशो जैसे प्लेटफॉर्म पर शॉर्ट-फॉर्म वीडियो का बोलबाला है। ये प्लेटफॉर्म माइक्रो फिल्मों के लिए एक उर्वर जमीन प्रदान करते हैं, जहां लाखों उपयोगकर्ता हर दिन रचनात्मक लघु वीडियो अपलोड करते हैं। भारत में भी, टिकटॉक पर प्रतिबंध के बाद, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और विभिन्न भारतीय ऐप जैसे एमएक्स टकाटक ने शॉर्ट-फॉर्म वीडियो को लोकप्रिय बनाया है। इन प्लेटफॉर्म्स पर कई फिल्म निमार्ता और कंटेंट क्रिएटर अपनी माइक्रो फिल्मों को प्रदर्शित कर रहे हैं, जो अक्सर सामाजिक संदेशों, कॉमेडी या कलात्मक प्रयोगों पर आधारित होती हैं। दक्षिण कोरिया में भी, वेब ड्रामा और शॉर्ट-फॉर्म कंटेंट की लोकप्रियता बढ़ रही है, जिसमें माइक्रो फिल्मों के तत्व शामिल हैं। पश्चिमी देश (यूएसए, यूरोप)ः पश्चिमी देशों में भी शॉर्ट-फॉर्म कंटेंट की खपत बढ़ रही है, लेकिन इसका विकास थोड़ा अलग है। यहां, माइक्रो फिल्मों को अक्सर 'टिकटॉक फिल्म्स' या 'वायरल वीडियो' के रूप में देखा जाता है। हालांकि, कुछ स्वतंत्र फिल्म निर्माता और त्योहार भी हैं जो माइक्रो फिल्मों को एक वैध कला रूप के रूप में बढ़ावा दे रहे हैं। उदाहरण के लिए, विभिन्न लघु फिल्म समारोहों में अब 'माइक्रो-शॉर्ट' या 'अल्ट्रा-शॉर्ट' श्रेणियों को शामिल किया जा रहा है। ब्रांड्स और विज्ञापन एजेंसियां भी अपने मार्केटिंग अभियानों में माइक्रो फिल्मों का उपयोग कर रही हैं। आज यू ट्यूब एक लोकिप्रय और महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है जहां कई स्वतंत्र निमार्ता अपनी छोटी अवधि की फिल्में साझा करते हैं। यूरोपीय देशों में भी, कलात्मक फिल्मों और प्रयोगात्मक सिनेमा में लघु प्रारूपों का उपयोग किया जा रहा है। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भी स्मार्टफोन और इंटरनेट की पहुंच बढ़ने के साथ, शॉर्ट-फॉर्म वीडियो कंटेंट लोकप्रिय हो रहा है। स्थानीय कहानियों और सांस्कृतिक अनुभवों को साझा करने के लिए माइक्रो फिल्में एक शक्तिशाली माध्यम बन सकती हैं। कई युवा फिल्म निमार्ता अपने समुदायों की कहानियों को बताने के लिए मोबाइल फोन का उपयोग कर रहे हैं और इन वीडियो को सोशल मीडिया पर प्रसारित कर रहे हैं।ऐसे में एक सवाल सहज ही पैदा होता है कि क्या माइक्रो फि ल्में सिनेमा का भविष्य हैं? इस मुद्दे पर विचार करने के क्रम में यह कहना जल्दबाजी होगी कि माइक्रो फिल्में पारंपरिक सिनेमा का पूरी तरह से स्थान ले लेंगी। बड़ी बजट वाली फीचर फि ल्में, उनकी भव्यता और गहराई के साथ, हमेशा दर्शकों के लिए एक अलग आकर्षण रखेंगी। हालांकि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि माइक्रो फि ल्में मनोरंजन और कहानी कहने के परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। हां,माइक्रो फि ल्में, फीचर फि ल्मों की प्रतिद्वंद्वी बनने के बजाय, एक पूरक माध्यम के रूप में अधिक काम करेंगी। वे दर्शकों को इंस्टैंट मनोरंजन, सूचना और कलात्मक अनुभव प्रदान कर सकती हैं, जबकि लंबी फि ल्में गहन और विस्तृत कथाओं को प्रस्तुत करती रहेंगी। माइक्रो फिल्मों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि भविष्य में कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है मसलन, प्लेटफॉर्मों का विकासः ऐसे प्लेटफॉर्म जो विशेष रूप से माइक्रो फिल्मों को क्यूरेट और वितरित करते हैं, की संख्या बढ़ सकती है। ये प्लेटफॉर्म फिल्म निमार्ताओं को राजस्व मॉडल

और दर्शकों तक पहुंचने के नए तरीके प्रदान कर सकते हैं।

नए कथाकारों को मौकाः माइक्रो फिल्में विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को कहानी कहने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं, जिससे सिनेमा में अधिक विविधता आ सकती है।

तकनीकी इनोवेशनः वास्तविकता और आभासी वास्तविकता जैसी तकनीक माइक्रो फिल्मों के अनुभव को और बढ़ा सकती हैं, जिससे वे अधिक इमर्सिव और इंटरैक्टिव बन सकें।

३स्नैकएबल३ या त्वरित कंटेंट का बढ़ता महत्वः फि ल्मों से जुड़े आलोचकों का ऐसा कहना है कि जैसे-जैसे लोगों का जीवन व्यस्त होता जाएगा, 'स्नैकएबल' या त्वरित उपभोग योग्य कंटेंट की मांग बढ़ती जाएगी और माइक्रो फिल्में इस मांग को पूरा करने के लिए पूरी तरह से अनुकूल हैं।

शिक्षा और ब्रांडिंग में अहम भूमिकाः माइक्रो फिल्में शिक्षा और ब्रांडिंग के लिए एक मानक उपकरण बन सकती हैं, जिससे जानकारी और विज्ञापन को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया किया जा सके।

माइक्रो फिल्में केवल क्षणिक मनोरंजन या उपयोग का उपकरण नहीं बल्कि एक उभरता हुआ माध्यम हैं जिसमें सिनेमा और कहानी कहने के भविष्य को आकार देने की अपार क्षमता है। तकनीकी प्रगति, सोशल मीडिया के प्रभुत्व और दशकों की बदलती आदतों ने इस नई सोच को जन्म दिया है। जहां वे अपनी चुनौतियों के साथ आती हैं, वहीं क्रिएटिविटी पहुंच और प्रभाव के लिए भी अपार अवसर प्रदान करती हैं।

यह संभावना है कि माइक्रो फिल्में पारंपरिक फिल्म निर्माण के साथ सह-अस्तित्व में रहेंगी, एक दूसरे का पूरक बनेंगी और समग्र रूप से सिनेमाई परिदृश्य को समृद्ध करेंगी। वे न केवल नए फिल्म निमार्ताओं को एक मंच प्रदान करेंगी, बल्कि दर्शकों के लिए मनोरंजन और जानकारी प्राप्त करने के नए तरीके भी खोलेंगी। तो, क्या अब माइक्रो फिल्में बनेंगी? जवाब स्पष्ट है,वे पहले से ही बन रही हैं, और उनका भविष्य बेहद उज्ज्वल प्रतीत होता है। यह एक ऐसे युग की शुरूआत है जहां कहानी कहने की शक्ति उसकी लंबाई में नहीं, बल्कि उसके प्रभाव और पहुंच में निहित होगी।

(लेखक के ये अपने विचार हैं।)

'डॉन 3' में कृति सेनन

सुभाष शिरढोनकर
फिल्म स्तंभकार

फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' से कियारा आडवाणी के बाद शरवरी वाघ का भी पत्ता कट चुका है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अब इस फिल्म में रणवीर सिंह के अपोजिट कृति सेनन नजर आएंगी।

यदि खबरों की मानें तो कृति सेनन बहुत जल्द फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली हैं। यदि ऐसा होता है तो ये पहली बार होगा जब रणवीर सिंह और कृति सेनन एकसाथ बड़े पर्दे पर नजर आएंगे।

'डॉन 3' की शूटिंग फरहान अख्तर जल्द से जल्द शुरू करने वाले हैं। पहले और दूसरे शेडयूल में फिल्म को यूरोप की कई लोकेशंस पर शूट किया जाएगा।

दूसरा मत

हार्दिक शुभकामनाएं

पढ़ें और पढ़ाएं दूसरा मत

एक शुभचिंतक, दिल्ली

कृति सेनन अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में बनी रहती हैं। पिछले काफी दिनों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि उन्हें इश्क हो गया है और वे उम्र में 9 साल छोटे यूके के एनआरआई बिजनेसमैन कबीर बाहिया को डेट कर रही हैं। कबीर बहिया एमएस धोनी वाइफ साक्षी सिंह के कजन हैं।

कृति सेनन आनंद एल राय की फिल्म 'तेरे इश्क में' साउथ स्टार धनुष के साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आने वाली हैं।

भूषण कुमार, टी-सीरीज और कलर येलो व्दाकरा बनाई गई इस फिल्म को आनंद एल राय ने डायरेक्ट किया है। 'रांझणा' (2013) के बाद, आनंद एल राय, धनुष और ए.आर. रहमान की यह एक और इमोशनल लव स्टोरी हैं। ये फिल्म 28 नवंबर, 2025 को दुनिया भर में हिंदी और तमिल में रिलीज होने वाली है।

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर पिछले साल रिलीज हुई फिल्म 'दो पत्ती' में कृति सेनन काजोल और शहीर शेख के साथ नजर आई थीं। इस सस्पेंस थ्रिलर फिल्म में उनका डबल रोल था। कृति सेनन ने इस फिल्मं को अपनी बहन नुपुर सेनन के साथ 'ब्लू बटरफ्लाई फिल्म्स' नाम से स्थुापित अपने खुद के प्रोडक्शन हाउस के अंतर्गत बनाया था।

टाइगर श्रॉफ के साथ फिल्म 'हीरोपंती' से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली कृति सेनन अपने दस साल के करियर में 'बरेली की बर्फी', 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' और 'क्रू' जैसी बॉलीवुड की कई बेहतरीन फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेर चुकी हैं।

69 वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में कृति सेनन को 2021 में रिलीज हुई फिल्म 'मिमी' के लिए बैस्ट एक्ट्रैस श्रेणी में में नेशनल अवॉर्ड मिल चुका है।

अपनी खूबसूरती, दिल फरेब स्टाइल और बेहतरीन एक्टिंग के दम पर इंडस्ट्री में एक खास मुकाम बना चुकी कृति सेनन का आज हर कोई दीवाना है। उनका नाम बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार है।

कृति सेनन अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में बनी रहती हैं। पिछले काफी दिनों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि उन्हैं। इश्क हो गया है और वे उम्र में 9 साल छोटे यूके के एनआरआई बिजनेसमैन कबीर बाहिया को डेट कर रही हैं। कबीर बहिया एमएस धोनी वाइफ साक्षी सिंह के कजन हैं।

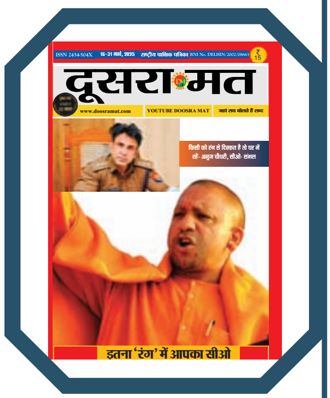

दूसरा मत

पढ़ें और पढ़ाएं

एक शुभचिंतक

नई दिल्ली

विगत 23 वर्षों से देशहित में समाज-निर्माण के संकल्प के साथ

न हम डरते है न डराते हैं
हम देशप्रेम की भावना जगाते हैं

अगर आप में है जोश और
देश से प्यार

तो आइए दिल्ली से प्रकाशित
राष्ट्रीय पाक्षिक पत्रिका
दूसरा मत
के साथ

अगर शिक्षक, प्रोफेसर, इंजीनियर और डॉक्टर बनते हो तो हमेशा एक ही काम करोगे लेकिन पत्रकार बनते हो तो दुनिया समझने को मिलेगी, दुनिया समझाने को मिलेगी। दुनिया को पढ़ने का मौक़ा मिलेगा, दुनिया को पढ़ाने का मौक़ा मिलेगा

हम आपके हाथ में देते हैं क़लम
समाज-निर्माण की ताक़त के साथ।

योग्यता
ख़बरों की समझ
और देश के साथ
सच्ची प्रेम-भावना

सोचो, समझो और दूसरा मत से जुड़ो

संपर्क : +91-9643709089

47
YEARS OF EXCELLENCE
हार्दिक
शुभकामनाएं
!! RADHA SOAMI JI !!
Kasturi Jewellers
SINCE 1976
100% HALLMARK JEWELLERY SHOWROOM
#GOLD #DIAMOND JEWELLERY #SOLITAIRES
100% Lifetime Maintenance Free
100% Buy Back Diamond Jewellery
100% Certified Diamond Jewellery
Shop No. 15, 16, 17, 18, SDM Market, Mangal Bazar Road, Uttam Nagar, New Delhi-110 059
Shop No. 54-55, Main Pankha Road, Opp. Sagar Pur Police Station, New Delhi-110 046
Kasturi Lal Ph. 98186 09444 | Manish (Monu) Ph. 98186 11313

दूसरा मत मतलब

देशदृष्टि की मिसाल

एक शुभचिंतक, दिल्ली